वर्ष 13 • अंक 19 • 12 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

सोमवार 9 मार्च 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 3

सोना बढ़े, चांदी ठहरे तो क्या होगा ?

लक्ष्मी निवास मित्तल ▸▸ पृष्ठ 2

कोरोना से आर्सेलरमित्तल की बिक्री पर पड़ेगा असर

एक नज़र

बाजार में बना रह सकता है इस हफ्ते भी उतार-चढ़ाव

होली के अवकाश के चलते कम कारोबारी दिवस वाले इस हफ्ते बाजार दबाव में रह सकता है। निवेशकों की नजर येस बैंक संकट तथा कोरोनावायरस पर है। इन दोनों के कारण कारोबारी धारणा पर असर पड़ा है। स्टॉक एक्सचेंज मंगलवार को होली के कारण बंद रहेंगे। औद्योगिक उत्पादन और खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े गुरुवार को और थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े शुक्रवार को जारी होंगे। विशेषज्ञों ने कहा कि उतार-चढ़ाव और मौजूदा माहौल के कारण आशंका को देखते हुए निवेशक वित्तीय संकट को लेकर चीजें साफ होने तक बाजार से दूर रह सकते हैं और निवेश घटा सकते हैं। बाजार में जब तक स्थिति सामान्य नहीं रहती, बाजार में दबाव और उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।

टिकट रद्द कराने पर शुल्क नहीं वसूलेगी गोएयर

किफायती विमानन सेवा प्रदाता कंपनी गो एयर ने कहा कि 30 अप्रैल तक बुक कराए हवाई टिकट रद्द किए जाने की स्थिति में वह यात्रियों से कोई शुल्क नहीं लेगी। यात्रा की तारीख में बदलाव पर भी कंपनी यात्रियों से शुल्क नहीं लेगी। कोरोनावायरस संक्रमण के बाद पैदे हुए हालात के मद्देनजर इस विमानन कंपनी ने यह घोषणा की है। कंपनी ने रविवार को कहा कि निर्णय 8 मार्च से 30 अप्रैल तक बुक कराए गए टिकटों और 8 मार्च से 30 सितंबर तक की यात्रा की तिथि पर लागू होगा। प्रस्थान की तारीख से 14 दिन पहले तक टिकट रद्द कराने या यात्रा तिथि में बदलाव पर इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। इससे पहले शनिवार को इंडिगो ने भी 12 मार्च 31 मार्च तक यात्रा की तिथि में बदलाव पर बुक कराए टिकटों पर शुल्क नहीं लेने की पेशकश की थी।

ओपेक में दरार से खाड़ी देशों के बाजारों में गिरावट

सऊदी अरब का शेयर बाजार रविवार को शुरुआती कारोबार में 6.5 प्रतिशत नीचे आ गया। खाड़ी के अन्य देशों में भी शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई और वे कई साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए। तेल निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) और सहयोगियों के बीच तेल उत्पादन में कटौती को लेकर समझौता नहीं होने के बाद शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। तेल कंपनी सऊदी अरामको का शेयर आईपीओ मूल्य से नीचे आ गया। दुबई फाइनैंशियल बाजार 8.5 प्रतिशत तथा कुवैत और आबुधाबी के बाजारों में 7 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई।

एयरसेल के लाइसेंस पर रोक की याचिका खारिज

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली पंचाट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (एनसीएलटी) के फैसले के खिलाफ दूरसंचार विभाग की याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें कहा गया था कि दिवालिया हो चुकी एयरसेल के स्पेक्ट्रम और लाइसेंस को दिवालिया प्रक्रिया के दौरान वापस नहीं लिया जा सकता है। एनसीएलएटी ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने में देरी कर दी है, जिसके चलते याचिका को खारिज कर दिया गया। दूरसंचार विभाग ने एनसीएलटी की मुंबई शाखा के आदेश के खिलाफ अपील की थी।

15 प्रतिशत से कम हिस्सेदारी वाली कंपनियों को मिले छूट

सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से कहा है कि सेवाओं की न्यूनतम दर रखने का प्रावधान केवल उन्हीं कंपनियों के लिए रखा जाना चाहिए, जिनका संबंधित सेवा क्षेत्र में ग्राहकों का आधार 15 प्रतिशत से अधिक है। इन कंपनियों ने कहा कि जिन दूरसंचार कंपनियों के ग्राहकों की संख्या न के बराबर है या बहुत कम है, उन्हें न्यूनतम दरों से छूट दी जानी चाहिए। ट्राई के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) पूरे देश में मोबाइल ग्राहकों के आधार पर बाजार हिस्सेदारी करीब 10.3 प्रतिशत है। टीएनएल दिल्ली और मुंबई में काम करती है और उसकी बाजार हिस्सेदारी 0.29 प्रतिशत है।

आज का सवाल

क्या येस बैंक संकट से निवेशकों की धारणा होगी प्रभावित

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या येस बैंक संकट से अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर?	हां	66.67%
	नहीं	33.33%

राणा कपूर ईडी की हिरासत में

4,300 करोड़ रुपये की रिश्वत का मामला, सीबीआई ने भी दर्ज की धोखाधड़ी की प्राथमिकी

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 8 मार्च

येस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और उनके परिवार ने दर्जन भर मुखौटा फर्में बनाई थीं जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर 4,300 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने और संपत्तियों में अवैध तरीके से निवेश करने के लिए किया जाता था। यह बात प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शुरुआती जांच में पता चली है।

ईडी ने धनशोधन मामले में 62 वर्षीय कपूर को रविवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। कपूर को मुंबई की सत्र अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 11 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। इससे तीन दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने येस बैंक से धन निकासी पर 30 दिन की बंदिश लगा दी थी और उसके बोर्ड को भंग कर दिया था। इस बीच आरबीआई ने जमाकर्ताओं को फिर से भरोसा दिलाया है कि उनकी जमा राशि सुरक्षित है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी कपूर, दीवान हाउसिंग फाइनैंस (डीएचएफएल) और इसके प्रवर्तकों एवं अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।

सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत में कहा कि कपूर परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित कुछ कंपनियों में उनकी भूमिका की जांच के लिए राणा कपूर को हिरासत में लेने की जरूरत है। ईडी ने कहा कि यह मामला 4,300 करोड़ रुपये के धनशोधन से जुड़ा है, जिसमें आम जनता का पैसा लगा है।

ईडी की जांच से आगे पता चला है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल रिश्वत के पैसे से 2,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां खरीदने में किया गया है। अधिकारी ने बताया कि इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है। जांच एजेंसी के पास कपूर द्वारा ब्रिटेन में खरीदी गई दो संपत्तियों से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं। अभी इन संपत्तियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके अलावा जांच एजेंसी ने कपूर के आवास से 44 पेंटिंग्स भी जब्त की हैं जिनकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपये है। सूत्रों ने कहा कि इनमें से कुछ कंपनियों का कारोबार का कोई रिकॉर्ड नहीं है और कुछ के बोर्ड में निदेशक तक नहीं हैं। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि इन मुखौटा फर्मों पर कपूर, उनकी पत्नी तथा उनकी तीन बेटियों का प्रत्यक्ष और परोक्ष नियंत्रण था। अधिकारी ने कहा कि कपूर और उनके परिवार से जुड़े सभी वित्तीय लेनदेन एजेंसी के जांच दायरे में हैं।

कारोबारी इकाइयों को येस बैंक से ऋण देने के बदले रिश्वत लेने में इन मुखौटा फर्मों के इस्तेमाल का आरोप है। डीएचएफएल द्वारा कपूर परिवार के कारोबार डूईट अर्बन वेंचर्स में 40 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों के एवज में 600 करोड़ रुपये देने का आरोप है। यह तब किया गया जब हाउसिंग फाइनैंस कंपनी बैंक को 3,700 करोड़ रुपये के कर्ज का भुगतान करने में विफल रही थी। डीएचएफएल के साथ अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है जिसमें निजी बैंक ने धीरज वधावन के आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स को मुंबई की एक परियोजना के लिए 750 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया था जबकि उस समय तक डीएचएफएल का कर्ज एनपीए बन चुकी थीं। (शेष पृष्ठ 7 पर)

रविवार सुबह मुंबई में येस बैंक के प्रवर्तक राणा कपूर को गिरफ्तार कर ले जाते ईडी के अधिकारी। *फोटो : कमलेश पेडणेकर*

- रिश्वत के 2,000 करोड़ रुपये संपत्तियों में किए गए निवेश
- ब्रिटेन में दो संपत्तियां चिह्नित, मूल्यांकन का काम जारी
- तलाशी के दौरान 44 कीमती पेंटिंग्स जब्त
- येस बैंक ने डीएचएफएल को 3,700 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया था
- राणा कपूर, उनकी पत्नी और तीनों बेटियों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी

पेंशन क्षेत्र में व्यापक सुधार की तैयारी

शुभमय भट्टाचार्य
नई दिल्ली, 8 मार्च

- पीएफआरडीए अधिनियम में होंगे 30 बदलाव
- विदेशी पेंशन कोषों को आकर्षित करने में मिलेगी मदद
- पीएफआरडीए का नाम बदलकर पीआरडीए होगा
- समूचे पेंशन क्षेत्र का इकलौता नियामक होगा

देश के पेंशन बाजार में व्यापक सुधार की तैयारी की जा रही है। इसके तहत विदेशी पेंशन फंडों को देश में स्वतंत्र पेंशन ट्रस्ट बनाने की अनुमति देने और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को पेंशन उत्पादों की मंजूरी देने वाला इकलौता प्राधिकरण बनाया जाएगा। इससे बीमा कंपनियों और कुछ म्युचुअल फंडों को अपनी मौजूदा पेंशन योजनाओं को नए सिरे से तैयार करना होगा। ये उन 30 बदलावों का हिस्सा हैं जिन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 में संशोधन के जरिये शामिल करने की योजना बनाई है। संशोधन में नियामक के नाम में बदलाव भी शामिल होगा। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण की जगह इसे पेंशन नियामक विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि नियामक के नाम से 'कोष' शब्द को इसलिए हटाया जाएगा क्योंकि नियामक को पूरे पेंशन क्षेत्र का जिम्मा सौंपा जाएगा और यह केवल कोष तक सीमित नहीं होगा। संशोधनों से विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करने में मदद मिलेगी, जिन्हें बीमा क्षेत्र में अभी 49 फीसदी तक ही निवेश की अनुमति है। हालांकि सरकार के अधिकारी अक्सर इस सीमा को बढ़ाकर 74 फीसदी करने की बात करते रहे हैं लेकिन पेंशन नियमों की वजह से अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। भारत में पेंशन क्षेत्र कई खंडों में बंटा हुआ है। उदाहरण के लिए देश के सबसे बड़े पेंशन कोष के संचालक कर्मचारी भविष्य निधि का परिचालन श्रम मंत्रालय के तहत किया जाता है और यह पीएफआरडीए के दायरे से बाहर आता है। निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारी जिनकी आय निर्धारित सीमा से कम है उन्हें अनिवार्य रूप से ईपीएस की सदस्यता लेनी होती है।

सबसे अहम सुधार एक से अधिक पेंशन ट्रस्ट स्थापित करने की है जबकि अभी नैशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट इकलौता ट्रस्ट है। एनपीएस ट्रस्ट का गठन 2008 में पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस ट्रस्ट डीड के जरिये किया गया था। कोई भी कामगार जो पीएफआरडीए द्वारा संचालित पेंशन सिस्टम की सदस्यता लेता है वह एनपीएस ट्रस्ट के दायरे में आता है। इस निवेश पर ब्याज की गारंटी एनपीएस बोर्ड के न्यासियों द्वारा दी जाती है। सरकार का मानना है कि इकलौते एनपीएस से क्षेत्र का विकास प्रभावित हो रहा है। इसलिए ट्रस्ट डीड में बदलाव कर कई ट्रस्ट को अनुमति दी जाएगी, जिसका गठन किसी भी पेंशन कंपनी द्वारा किया जा सकता है। ऐसे में विदेशी पेंशन फंड भी भारत में पेंशन कोष चला सकते हैं और पेंशन ट्रस्ट का गठन कर सकते हैं।

मौजूदा एनपीएस स्व-नियमन वाला संगठन होगा और उसकी सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का अनुपालन सभी पेंशन ट्रस्टों द्वारा किया जाएगा। यह पीआरडीए (नियामक का नया नाम) को रिपोर्ट करेगा।

खबर है कि वित्त मंत्रालय को भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सहित अन्य संबंधित नियामकों से इन सुधारों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।

एटी-1 बॉन्ड पर संकट का साया

जश कृपलानी
मुंबई, 8 मार्च

फीकी पड़ी चमक

येस बैंक के बॉन्ड के बॉन्ड बट्टे खाते में डालने के आरबीआई के प्रस्ताव के बाद एटी-1 बॉन्ड को मिल सकते हैं नए खरीदार

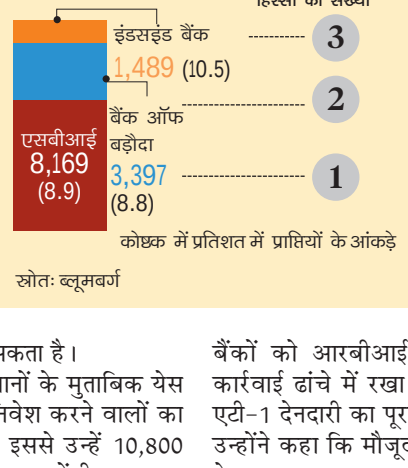

स्रोतः ब्लूमबर्ग

येस बैंक की पुनर्गठन योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग नियमन कानून की धारा 45 का इस्तेमाल करते हुए संकट में फंसे इस बैंक के अतिरिक्त टियर-1 (एटी-1) बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव किया है। इससे एक लाख करोड़ रुपए के एटी-1 बॉन्ड यानी परपेचुअल बॉन्ड बाजार से निवेशकों का मोह भंग हो सकता है।

ऐक्यूट रेटिंग्स के अनुमानों के मुताबिक येस बैंक के एटी-1 बॉन्ड में निवेश करने वालों का पूरा पैसा डूब जाएगा और इससे उन्हें 10,800 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। एजेंसी का कहना है कि आरबीआई के इस कदम से भविष्य में निवेशक बॉन्ड बाजार से दूर हो सकते हैं। येस बैंक के अधिकांश एटी-1 बॉन्ड म्युचुअल बॉन्ड और बैंकों की ट्रेजरी के पास हैं। कई म्युचुअल फंड येस बैंक के बॉन्ड में अपने निवेश को पहले ही बट्टे खाते में डाल चुके हैं। ऐसे में अगर आरबीआई इस मामले में अपना रुख नहीं बदलता है तो इससे बॉन्डधारकों के निवेश पर असर पड़ेगा।

ऐक्सिस एफएम में फंड मैनेजर आर शिवकुमार ने कहा, 'यह योजना अभी प्रारूप में चरण में है और अगर इसे लागू किया जाता है तो यह ऐसे बॉन्ड के बारे में आरबीआई के रुख में बदलाव का संकेत है। इससे इस तरह के बॉन्डों को जारी करने की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। 2017-18 में कुछ कमजोर सरकारी बैंकों को आरबीआई की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे में रखा गया था लेकिन फिर भी एटी-1 देनदारी का पूरा भुगतान किया गया था।' उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थिति में इन बॉन्डों के साथ अलग व्यवहार देखने को मिल रहा है।

फंड मैनेजर और फिक्स्ड इनकम विशेषज्ञों का कहना है कि आरबीआई एटी-1 बॉन्ड के साथ जैसा व्यवहार कर रहा है, वह चिंता की बात है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि अगर नियामकीय हस्तक्षेप बढ़ता है तो भविष्य में इस तरह के बॉन्डों के साथ क्या होगा। (शेष पृष्ठ 7 पर)

दिल खोलकर बांटे कर्ज

आमतौर पर सूट-बूट में दिखने वाले राणा कपूर शनिवार को जब साधारण कपड़ों में पूछताछ के लिए मुंबई में ईडी के कार्यालय पहुंचे तो वह दिग्गज बैंकर से एकदम अलग नजर आ रहे थे। येस बैंक को कपूर की छवि का फायदा मिला जो आक्रामक तरीके से ऋण देना चाहते थे। लेकिन उनकी यह तरकीब हमेशा काम नहीं आई। विश्लेषकों का कहना है कि बैंक ने ऐसे उद्योगपतियों को बहुत पैसा उधार दे दिया था जो चुकाने की स्थिति में नहीं थे। बैंक के पास इस कर्ज को कवर करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी। कपूर पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत लेकर कंपनियों को उधार दिया था। कपूर ने कर्ज देने में जो आक्रामकता दिखाई थी, उससे बैंक को भरोसा बनाने में मदद नहीं मिली। पृष्ठ 7

संस्थान निकले तो खुदरा निवेशकों ने खरीदे शेयर

येस बैंक के वित्तीय आंकड़े पिछले साल से ही दबाव के संकेत दे रहे थे। ऐसे में बैंक के बड़े संस्थागत शेयरधारकों और प्रवर्तकों ने अपने शेयरों की बिकवाली की, लेकिन खुदरा निवेशक 50 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी के साथ बैंक में बने रहे। बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा जुटाए गए आंकड़ों से इसका पता चलता है। प्रवर्तक राणा कपूर के शेयर खुद उन्होंने ही बेचे या गिरवी शेयर ऋणदाताओं ने बेचे। एक अन्य प्रवर्तक गोगिया परिवार ने अपना निवेश बनाए रखा। पिछले साल नवंबर में कपूर ने 142 करोड़ रुपये के अपने बाकी शेयर बेच दिए थे और उनके पास केवल 900 शेयर थे। ऋणदाताओं के कपूर के गिरवी शेयरों को बेचने के बाद उनकी बैंक में शेयरधारिता कम हुई। पृष्ठ 7

बढ़ेगी विवाद से विश्वास की तिथि!

प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना 'विवाद से विश्वास' की 31 मार्च की समयसीमा बढ़ाई जा सकती है। इस योजना की अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है। आयकर विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि ज्यादातर लोगों को इस योजना में हिस्सा लेने के लिए धन की व्यवस्था करने में वक्त की जरूरत होगी और कोरोनावायरस के कारण फैली अफरातफरी की वजह से भारत की कुछ फर्मों के लिए धन का इंतजाम करना मुश्किल होगा। कई फर्मों के वैश्विक मुख्यालयों को बचाव के कदम के तहत अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया था। पृष्ठ 4

उज्ज्वला का होगा कायाकल्प, घर बैठे भरवाएं एलपीजी सिलिंडर

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 8 मार्च

उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को मोबाइल की तरह जल्दी ही रसोई गैस सिलिंडर के लिए टॉप अप कराने का विकल्प मिल सकता है। वे अपने दरवाजे पर ही 50-100 रुपये की गैस भरवा सकेंगे। इसके लिए सरकार देशभर में मोबाइल एलपीजी वैन चलाने की योजना बना रही है।

तेल विपणन कंपनियां प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को सिलिंडरों भरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के कई उपाय शुरू करने पर विचार कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि सिलिंडर भरने के लिए उपभोक्ताओं को आंशिक ऋण देने की भी योजना है।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) के लिए एलपीजी के नियमित इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है क्योंकि उज्ज्वला योजना के लाभार्थी दूसरा सिलिंडर भरवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।

नियंत्रक एवं महोलखा परीक्षक की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2018 में पीएमयूवाई के 1.93 करोड़ उपभोक्ताओं (जिन्हें एक साल से अधिक समय हो चुका था) की सिलिंडर की सालाना औसत खपत केवल 3.66 सिलिंडर थी। योजना के 3.18 करोड़ उपभोक्ताओं पर किए गए विश्लेषण के मुताबिक 2018 में अंत में यह आंकड़ा गिरकर 3.21 सिलिंडर रह गया। एक अधिकारी ने कहा, 'सिलिंडर भरवाने की आदत को बढ़ावा देने के लिए छोटे सिलिंडरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा दूसरे सिलिंडर के लिए ऋण भी दिया जाएगा और सीधे उपभोक्ताओं के घर पर आपूर्ति के लिए रिफिल वैन भी चलाई जाएंगी।' उन्होंने कहा कि सुरक्षा पहलुओं को प्राथमिकता देते हुए मोबाइल वैन शुरू की जाएंगी।

ईंधन की सुगम उपलब्धता

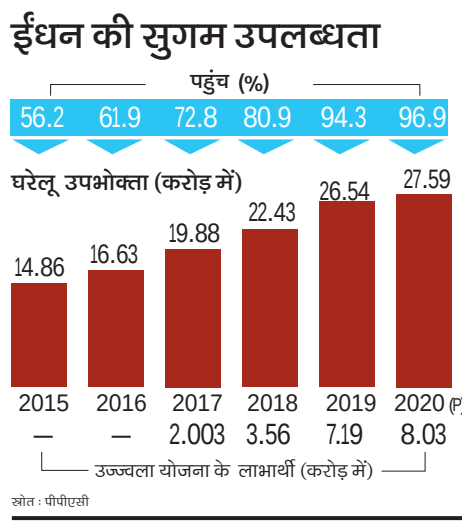

स्रोत : पीपीएसी

उज्ज्वला योजना में दोबारा सिलिंडर भरवाने वाले उपभोक्ताओं की कम संख्या के कारण सरकार को विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ा था। साथ ही सामान्य उपभोक्ताओं के सिलिंडर भरवाने का औसत आंकड़ा घटकर 7 के करीब रह गया है।

उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस सिलिंडर दिया जाता है। इसकी बदौलत देश में एलपीजी कवरेज 55 फीसदी से बढ़कर 97.4 फीसदी पहुंच गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक देश के 27.59 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में से करीब 8 करोड उपभोक्ता उज्ज्वला योजना से जुड़े हैं।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले सप्ताह कहा कि यह मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, व्यवहार में बदलाव, आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत करना और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। हम लोगों को सिलिंडरों को दोबारा भरवाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। भाजपा सरकार के पिछले साल दोबारा सत्ता संभालने के बाद लाभार्थियों को 14.2 किग्रा और 5 किग्रा के सिलिंडरों का विकल्प दिया गया था। अब उन्हें 5 किग्रा के दो सिलिंडरों का विकल्प दिया जा रहा है।

संक्षेप में

एनसीडी से 1,000 करोड़ रुपये जुटाएगी डीएलएफ

रियल्टी कंपनी डीएलएफ ने कहा है कि कंपनी के निदेशक मंडल की तरफ से गठित समिति ने गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र के जरिये 1,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नियामकीय सूचना में कंपनी ने कहा कि निदेशक मंडल की तरफ से गठित वित्त समिति ने इस इश्यू को जारी करने की मंजूरी दे दी, जिसकी मूल रकम 1,000 करोड़ रुपये तक होगी और निजी नियोजन के आधार पर इसे जारी किया जाएगा। यह एनसीडी एक या एक से ज्यादा चरणों में जारी किए जाएंगे। पिछले महीने कंपनी ने दिसंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 24 फीसदी की उछाल के साथ 414.01 करोड़ रुपये रहने की घोषणा की थी। कंपनी की कुल आय इस अवधि में 36 फीसदी घटकर 1,533.34 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 2,405.89 करोड़ रुपये रही थी। कंपनी की शुद्ध बिक्री अप्रैल-दिसंबर में 21 फीसदी बढ़कर 2,156 करोड़ रुपये रही। *एजेंसियां*

होंडा देश में करेगी प्रीमियम मोटरसाइकल का उत्पादन

होंडा मोटरसाइकिल ऐंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) की योजना अगले वित्त वर्ष से अपनी कुछ प्रीमियम मोटरसाइकल का उत्पादन स्थानीय स्तर पर करने की है। इससे कंपनी को अपने ऐसे उत्पाद सस्ता बनाने में मदद मिलेगी। कंपनी अभी देश में इस श्रेणी की केवल सीबी300आर मोटरसाइकल बेचती है। कंपनी देश में अपनी प्रीमियम मोटरसाइकलों का कारोबार बढ़ाना चाहती है। ऐसे में उसकी योजना 500 सीसी इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकल को घरेलू बाजार में उतारने की है। कंपनी अपनी प्रीमियम मोटरसाइकलों के लिए एक अलग बिक्री प्रणाली विकसित करने पर विचार कर रही है। कंपनी इसे अलग कारोबार के तौर पर आगे बढ़ाना चाहती है। कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (बिक्री एवं विपणन) यादविंदर सिंह गुलेरिया ने कहा, अगर हम अपने इस कारोबार का स्वस्थ विस्तार चाहते हैं, तो यह बहुत आवश्यक है कि हमारे पास उत्पादों की व्यापक मौजूदगी हो। केवल ब्रांड बनाने की दृष्टि से नहीं, बल्कि भविष्य में इनकी बिक्री संख्या बढ़ाने के लिए भी यह आवश्यक है। *भाषा*

कोरोनावायरस से अटकेंगे बड़े सौदे

आईटी फर्मों को बड़े सौदे हासिल करने और उसके क्रियान्वयन में हो सकती है देर

देवाशिष महापात्र
बेंगलूरु, 8 मार्च

कोरोनावायरस के प्रसार के कारण इस साल की पहली छमाही में आईटी सेवा फर्मों की तरफ से बड़े सौदे हासिल करने और उनके क्रियान्वयन में देर हो सकती है। आउटसोर्सिंग एडवाइजरी विशेषज्ञों के मुताबिक, मानव संसाधनों की आवाजाही पर लगी कड़ी पाबंदी और क्लाइंटों की तरफ से फैसले लेने में देरी को इसकी मुख्य वजह माना जा रहा है।

आउटसोर्सिंग एडवाइजरी फर्म एवरेस्ट समूह के संस्थापक और सीईओ पीटर बेंडॉर सैमुअल ने कहा, आईटी में कायापलट वाले बड़े सौदों के क्रियान्वयन में काफी वक्त लगता है। कोरोनावायरस के कारण यह स्पष्ट है कि कार्यकारी टीम का ध्यान कम से कम अगली तिमाही तक बंटा रहेगा। ऐसे में राजस्व की रफ्तार की भरपाई करने वाले बड़े सौदों में देर होगी।

सभी आईटी सेवा कंपनियां पहले ही चीन से लेकर कई अन्य देशों मसलन इटली, फ्रांस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान आदि देशों की यात्रा पर पाबंदी लगा चुकी हैं। कुछ मामलों में कई कंपनियों ने तो गैर-जरूरी अमेरिकी यात्रा पर भी पाबंदी लगा दी है, जो भारतीय आईटी सेवा कंपनियों के राजस्व में करीब 60 फीसदी का योगदान करता है।

सैमुअल ने कहा, हम पर्यटन और फैशन आदि क्षेत्रों में परियोजना टलते देख रहे हैं। हम सभी उद्योगों के क्लाइंटों की तरफ से बैठक रद्द करते देख रहे हैं, साथ ही वे यात्रा को सीमित कर रहे हैं और कुछ हद तक अपने कैंपस भी बंद रख रहे हैं। इन अवरोधों का बढ़त पर नकारात्मक असर दिखेगा और अगली तिमाही में नए अनुबंधों पर इसका खासा असर दिखेगा।

हाल के वर्षों में बड़े सौदे प्रमुख आईटी कंपनियों के राजस्व की रफ्तार का अहम हिस्सा बन गए हैं। उदाहरण के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में राजस्व दो अंकों में रहने का अनुमान जताने वाली इन्फोसिस ने इस वित्त वर्ष के पहले नौ महीने में 7.3 अरब डॉलर के बड़े सौदे हासिल किए हैं। बेंगलूरु मुख्यालय वाली फर्म ने वित्त वर्ष 2019 में 6.28 अरब डॉलर के बड़े अनुबंध हासिल किए थे।

इसी तरह बाजार की अग्रणी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने अप्रैल-दिसंबर की अवधि में 18 अरब डॉलर के बड़े सौदे हासिल किए हैं। हालांकि विप्रो बड़े सौदों का खुलासा नहीं करती, लेकिन उसने भी वित्त वर्ष 2019 में अलाइट सॉल्युशंस से 1.5 अरब डॉलर के अनुबंध समेत काफी सौदे हासिल किए हैं।

शुरुआती बातचीत से लेकर इसके अंत तक पहुंचने के लिहाज से बड़े अनुबंधों में काफी वक्त लगता है और इसके तहत क्लाइंट के संगठन व वेंडरों के प्रमुख अधिकारियों से कई दौर की बातचीत होती है। जब सौदे पर हस्ताक्षर होते हैं तो यहां काम के लिए कर्मचारियों की काफी आवाजाही होती है। पारिख कंसल्टिंग के आईटी आउटसोर्सिंग सलाहकार व संस्थापक पारिख जैन ने कहा, जब वैश्विक बढ़त की रफ्तार पर किसी का साया हो तो क्लाइंट अपने खर्च को लेकर सतर्क होंगे। इसके अलावा क्रियान्वयन के लिए क्लाइंट की साइट तक कर्मचारियों की आवाजाही पर पाबंदी से आईटी फर्मों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म ओमडिया के वरिष्ठ विश्लेषक एच आयंगर के मुताबिक, अगर वायरस के प्रसार पर लगाम लगता है तो 2020 की दूसरी छमाही में कारोबार सामान्य हो सकता है।

आईटी सौदे पर पड़ेगा असर

- बड़े सौदे हासिल करने और उसके क्रियान्वयन में देरी से आईटी फर्मों के राजस्व की रफ्तार हो सकती है प्रभावित
- वैश्विक बढ़त की रफ्तार पर पड़ रहे साये से क्लाइंट अपने आईटी खर्च को लेकर हो सकते हैं सतर्क
- अभी यात्रा आदि पर लगी है कड़ी पाबंदी
- अगर गर्मियों में वायरस के प्रसार पर लगाम लगती है तो 2020 की दूसरी छमाही में बहाल हो सकती है रफ्तार

आर्सेलरमित्तल को बिक्री व लाभ पर असर की आशंका

भाषा
नई दिल्ली, 8 मार्च

दुनिया भर में कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच दुनिया की प्रमुख इस्पात कंपनी आर्सेलरमित्तल ने आशंका जाहिर की है कि यूरोप में और खासतौर से इटली में इस वायरस के प्रसार से 2020 में उसकी बिक्री और मुनाफा प्रभावित हो सकता है।

लक्जमबर्ग स्थित यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक है और दुनिया के 18 देशों में इसके इस्पात कारखाने हैं। कंपनी ने हाल ही में भारत में लगभग 42,000 करोड़ रुपये के कर्ज में डूबे एस्सार स्टील का अधिग्रहण पूरा किया है। साथ ही ऐलान किया है कि वह भारत में उत्पादन क्षमता साल 2024 के आखिर तक 85 लाख सालाना पर पहुंचा देगी। आर्सेलरमित्तल ने अपनी ताजा वार्षिक रिपोर्ट में कहा, चीन से बाहर मामले बढ़ने को लेकर चिंता है और वैश्विक महामारी का जोखिम बढ़ गया है और इसका वैश्विक जीडीपी पर कहीं अधिक नकारात्मक असर होगा। कंपनी हालात पर नजर बनाए हुए है, खासतौर से इटली में।

कंपनी ने कहा, वायरस यूरोप में अधिक व्यापक रूप से फैल रहा है, इसलिए आशंका है कि 2020 में कंपनी की बिक्री और मुनाफे पर इसका असर होगा। इटली यूरोप में इस प्रसार का केंद्र है और वहां इससे मरने वालों की संख्या 230 हो गई है, साथ ही इससे ग्रसित लोगों की संख्या 5,800 पर पहुंच गई है। यह आंकड़ा दक्षिण कोरिया और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। कंपनी ने कहा कि यह महामारी आर्सेलरमित्तल का परिचालन कुछ निश्चित इलाकों में प्रभावित कर सकती है और उसने उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे उसकी परियोजना साल 2014 व 2015 में लाइबेरिया में इबोला वायरस के प्रसार के कारण प्रभावित हुई थी।

कंपनी ने कहा, हालिया महामारी कोरोनावायरस समेत अन्य का आर्सेलरमित्तल के मौजूदा परिचालन, उत्पादन लक्ष्य और विस्तार योजना पर असर नहीं होगा, यह कहना मुश्किल है।

एशियाई विकास बैंक ने कोरोनावायरस के प्रसार से दुनिया भर में करीब 156 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान जताया है, जिसमें अकेले चीन की भागीदारी 103 अरब डॉलर की हो सकती है।

कमरों की संख्या दोगुनी करेगी स्टर्लिंग

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 8 मार्च

स्टर्लिंग हॉलिडेज ऐंड रिजॉर्ट्स वर्ष 2024 तक अपने होटल कमरों की संख्या दोगुना कर 5,000 करने और गैर-सदस्यों की संख्या में तेजी से वृद्धि करने की योजना बनाई है। कंपनी की नजर देश के यात्रा बाजार में अपनी मौजूदगी बेहतर करने पर है।

कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक रमेश रामनाथन ने कहा कि कंपनी भारत में तेजी से उभरते घरेलू यात्रा बाजार में गहरी पैठ बनाना चाहती है। उन्होंने कहा, 'हम तेजी से वृद्धि करेंगे और 2024 तक कमरों की संख्या को दोगुना वृद्धि के साथ 5,000 के पार पहुंचा देंगे।'

थॉमस कुक इंडिया की यह सहायक इकाई कुछ वर्ष पहले तक एक टाइम शेयर हॉलिडे कंपनी थी। लेकिन अब वह एक हाइब्रिड मॉडल पर काम करती है जो एक टाइम शेयर एवं होटल कंपनी है। कंपनी के राजस्व में उसके सदस्यों और गैर-सदस्यों का योगदान बराबर है।

हालांकि भारत में कोरोनावायरस के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए रामनाथन काफी सावधान हैं। उन्होंने कहा, 'घरेलू बाजार पर केंद्रित कंपनी होने के कारण अभी हमारे लिए सबकुछ अच्छा दिख रहा है। हमारे किसी भी सदस्य ने बुकिंग रद्द नहीं कराई है। लेकिन यदि इसका प्रकोप बढ़ा तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि लोगों की आवाजाही कम हो जाएगी और वे घर पर रुकना अधिक पसंद करेंगे।'

रामनाथन ने कहा कि लोगों की आवाजाही फिलहाल ठीक है और कंपनी के लगभग सभी होटलों में औसतन 60 से 70 फीसदी कमरों की बुकिंग हुई। कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण लोग भारत से बाहर की यात्रा करने से बच रहे हैं। ऐसे में घरेलू बाजार में होटल कमरों की अधिक बुकिंग और औसत कमरा दर (एआरआर) में तेजी आएगी वशर्ते भारत में कोरोनावायरस का प्रकोप न बढ़े। फरवरी में सालाना आधार पर होटल कमरों के भराव में 5 से 6 फीसदी की वृद्धि हुई और मार्च में भी लगभग ऐसी ही स्थिति रही।

इस बीच, महिंद्रा हॉलिडेज ऐंड रिजॉर्ट्स से प्रतिस्पर्धा करने वाली यह कंपनी हर साल औसतन 3,000 से अधिक सदस्यों को जोड़ती है। रामनाथन ने उम्मीद जताई कि गैर-सदस्यों के मामले में यह अनुपात कहीं अधिक बढ़ सकता है क्योंकि मिलेनियल्स और नए जमाने के लोग सदस्य अथवा स्वामित्व को पसंद नहीं करते हैं।

गैर-सदस्यों की हिस्सेदारी बढ़ने से भी कमरों की संख्या में वृद्धि को रफ्तार मिली है। रामनाथन ने कहा, 'हमें इन कमरों को भरने की जरूरत होगी और हम केवल सदस्यों की संख्या में वृद्धि पर ही निर्भर नहीं रह सकते।' किसी भी विस्तार को प्रबंधन अनुबंध के जरिये आगे बढ़ाया जाएगा। स्टर्लिंग महाराष्ट्र के इगतपुरी और करजत सहित विभिन्न जगहों पर कई होटल मालिकों से बातचीत कर रही है।

स्टर्लिंग नए सिरे से ब्रांडिंग की प्रक्रिया शुरू करने के बाद पिछले तीन वर्षों के दौरान सप्ताहांत, तीर्थाटन और विरासत संबंधी तीन श्रेणियों के तहत विशेष यात्रा जरूरतों पर ध्यान दे रही है।

- कंपनी भारत में तेजी से उभरते घरेलू यात्रा बाजार में गहरी पैठ बनाना चाहती है
- कंपनी 2024 तक कमरों की संख्या को दोगुना वृद्धि के साथ 5,000 के पार पहुंचा देगी
- भारत में कोरोनावायरस के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए कंपनी काफी सावधान है

रॉल्स रॉयस-फोर्स मोटर्स संयुक्त उद्यम की फैक्टरी जल्द होगी शुरू

गिरीश बाबू
चेन्नई, 8 मार्च

रक्षा, नागरिक उड्डयन, पावर सिस्टम आदि क्षेत्रों में काम करने वाली ब्रिटिश कंपनी रॉल्स रॉयस को उम्मीद है कि पुणे के पास चाकण में फोर्स मोटर्स के सहयोग से बन रहा इंजन व जेनसेट विनिर्माण केंद्र अगले कुछ महीनों में परिचालन शुरू कर देगा। रॉल्स रॉयस इंडिया व दक्षिण एशिया के अध्यक्ष किशोर जयरामन ने कहा, भारत में कंपनी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ गठजोड़ किया है और वह ऐसे और सहयोग पर विचार कर रही है।

कंपनी की इकाई रॉल्स रॉयस पावर सिस्टम और पुणे की वाहन विनिर्माता फोर्स मोटर्स ने मार्च 2018 में संयुक्त उद्यम के लिए करार पर हस्ताक्षर किए थे, जो रॉल्स रॉयस के इंजन ब्रांड एमटीयू 10 और 12 सिलिंडर सीरीज 1600 यूनिट्स (खास तौर से बिजली उत्पादन व रेल अंडरफ्लोर ऐप्लिकेशन के लिए उपयुक्त) के विनिर्माण के लिए थे। कंपनी पहले कह चुकी है कि फोर्स मोटर्स के पास 51 फीसदी हिस्सेदारी होगी जबकि रॉल्स रॉयस पावर सिस्टम्स के पास 49 फीसदी हिस्सेदारी।

जयरामन ने कहा, भारत एकमात्र जगह होगी जहां दुनिया भर के रॉल्स रॉयस ग्राहकों के लिए सीरीज 1600 इंजन बनाए जाएंगे। अगर सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो हम अगले कुछ महीने में इस विनिर्माण केंद्र को चालू कर देंगे। उन्होंने कहा, हम हर साल करीब 2,000 इंजन बनाने पर विचार कर रहे हैं और यह निर्यात के अलावा स्थानीय खपत के लिए भी होगा। यह बिजली उत्पादन और रेलवे में होगा, साथ ही हम अन्य क्षेत्रों के बारे में बाद में विचार करेंगे।

आपूर्ति श्रृंखला और इंजीनियरिंग स्थानीय है और पूरा जेनसेट की पैकेजिंग भारत में होगी। शुरू में कुछ कलपुर्जे विदेश से मंगाए जा सकते हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में पूरी तरह स्थानीय कलपुर्जों का ही इस्तेमाल होगा। समय के साथ रॉल्स रॉयस भारत में उत्पादन बेचने से आगे बढ़ते हुए तकनीक के हस्तांतरण, उत्पादों के विकास, लोगों को इससे जोड़ने और क्षमता निर्माण की ओर गई है। उसके बाद कंपनी का इरादा विदेश के लिए भारत उत्पादन करने का है। वैश्विक कारोबार का खासा हिस्सा रॉल्स रॉयस पहले ही भारत से हासिल कर रही है और वह और साझेदारी करने की इच्छुक है।

कंपनी ने कहा, भारत एकमात्र जगह होगी जहां विश्व के रॉल्स रॉयस ग्राहकों के लिए सीरीज 1600 इंजन बनाए जाएंगे

विदेश में सूचीबद्ध नहीं हो रही कंपनियां, देसी बाजार पर नजर

सचिन मामबटा
मुंबई, 8 मार्च

भारतीय कंपनियों के लिए विदेश सूचीबद्धता आसान करने के कदम उठाए गए हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से रकम जुटाने का यह जरिया सुस्त पड़ा हुआ है। वित्त वर्ष 2015-16 के बाद से ऐसा सिर्फ एक उदाहरण देखने को मिला है। एचडीएफसी बैंक ने वित्त वर्ष 2019 में डिपॉजिटरी रिसीट्स के जरिये पूंजी जुटाए।

यह पिछले वर्षों के उलट है। किसी एक वर्ष में सबसे ज्यादा 7.7 अरब डॉलर जुटाए गए थे। वह था वित्त वर्ष 2008, जब 33 इश्यू पेश हुए थे और यह जानकारी प्राइम डेटाबेस से मिली। सबसे ज्यादा इश्यू वित्त वर्ष 2006 में पेश हुए और तब 56 इश्यू के जरिये कुल 3.6 अरब डॉलर जुटाए गए। इस मार्ग से रकम जुटाने का दशक का औसत अभी सबसे कम है। वित्त वर्ष 2020 में समाप्त 10 वर्षों में औसतन 52.1 करोड़ डॉलर जुटाए गए। ऐसे इश्यू पर प्राइम के पास वित्त वर्ष 1993 के आंकड़े हैं।

प्राइम डेटाबेस के प्रबंध निदेशक प्रणव हल्दिया ने कहा, विदेशी पूंजी जुटाने के मामले में पहले काफी प्रोत्साहन उपलब्ध होता था। अब ऐसा नहीं है, जब ज्यादातर विदेशी निवेशक सीधे भारत में निवेश कर रहे हैं।

नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के पास जनवरी 2020 में 30.8 लाख करोड़ रुपये की इक्विटी परिसंपत्तियां थीं।

बीएस बातचीत

मंदी के बाद भी अपनी श्रेणी में हिस्सेदारी बढ़ाएगी बीएमडब्ल्यू

लक्जरी कार बनाने वाली कंपनी बीएमडब्ल्यू ने अपने प्रवेश स्तर के एसयूवी बीएमडब्ल्यू एक्स। के फेसलिफ्ट मॉडल को उतारा है। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि इससे उसकी वृद्धि को रफ्तार मिलेगी। बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्याधिकारी **रुद्रतेज सिंह** ने **टीई नरसिम्हन** और **गिरीश बाबू** से बातचीत में कहा कि कंपनी तमाम बाधाओं के बावजूद प्रतिस्पर्धी बनी रहेगी। पेश हैं मुख्य अंश:

मौजूदा मंदी ने लक्जरी कार श्रेणी को कितना प्रभावित किया है? बीएमडब्ल्यू इससे किस प्रकार निपट रही है?
हमें मंदी से उबरना अभी बाकी है। इस साल आपको सुधार का कोई उल्लेखनीय संकेत नहीं दिख रहा है। हालांकि इस मंदी के बावजूद मात्रात्मक बिक्री के मोर्चे पर बीएमडब्ल्यू पिछले साल के मुकाबले प्रतिस्पर्धी रही। लक्जरी श्रेणी में हमारी बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है। वर्ष 2018 और 2019 के बीच अपनाई गई नई रणनीति के तहत नवीनतम उत्पादों पर जोर दिया गया है। उसका फायदा आपको 2020 में भी दिखेगा। हमें विश्वास है कि 2020 में हम श्रेणीगत हिस्सेदारी में वृद्धि जारी रखेंगे।
मंदी का प्रभाव कुल बाजार के मुकाबले लक्जरी श्रेणी पर कहीं अधिक व्यापक है। इसका कारण काफी दबाव और प्रीमियम श्रेणी में अधिक कराधान है। बीएमडब्ल्यू न केवल लक्जरी है बल्कि यह देश में प्रौद्योगिकी, सुरक्षा मानदंड आदि लाने के लिए संवेदनशील भी है। इसलिए हम अपने उत्पाद और सेवाओं के मानक बेहतर कर रहे हैं। हमारी नजर केवल लक्जरी उत्पादों पर ही नहीं है। हमने 9,000 बीएमडब्ल्यू, 641 मिनी और 2,403 मोटरसाइकिलों की बिक्री की है। हम अपना डीलर नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और मूल्य निर्धारण एवं स्वामित्व लागत संबंधी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं।

आपको कब तक सुधार होने की उम्मीद है?
रोजाना तमाम नई बाधाओं के सामने आने के साथ ही आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्याएं आगे भी दिख सकती हैं। यह अगली कुछ तिमाहियों तक दिख सकती है। बेहतर होने से पहले यह कहीं अधिक बदतर हो सकती है। आपूर्ति के मामले में वृहत स्तर पर सरकार कुछ उपाय कर रही है जिनसे हमें मध्यावधि एवं लंबी अवधि में मदद मिलेगी। लेकिन लघु अवधि में मांग सृजित करने की जिम्मेदारी कंपनियों और विनिर्माताओं की है।

बीएस6 में जाने की तैयारी कैसी है?
बाजार में उपलब्ध हमारे सभी उत्पाद बीएस6 उत्सर्जन मानदंड के अनुरूप है। हालांकि हमारे पास बीएस4 उत्सर्जन मानदंड वाले कुछ मॉडलों के स्टॉक मौजूद है और मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी उसे खरीदना चाहते हैं वे जल्द खरीद लें।

इस श्रेणी में शीर्ष बने रहने के लिए क्या योजना है?
बीएमडब्ल्यू जबरदस्त उथल-पुथल वाले इस बाजार में जबरदस्त प्रतिस्पर्धी बनी रहेगी। हमें विश्वास है कि हम तमाम बाधाओं के बावजूद प्रतिस्पर्धी बने रहेंगे। इस श्रेणी में वृद्धि करने की हमारी क्षमता प्रतिस्पर्धात्मकता का संकेत है। प्रतिस्पर्धा के बल पर हम इस श्रेणी में 5 से 6 फीसदी की वृद्धि दर्ज कर सकते हैं।

सोना बढ़े, चांदी ठहरे तो क्या होगा ?

1 औंस सोने से चांदी खरीद की मात्रा बताता है यह अनुपात, 3 दशक के शीर्ष पर जाने के आसार

राजेश भयानी
मुंबई, 8 मार्च

सोने-चांदी के बीच तुलनात्मक रूप से मजबूती का संकेत देने वाला इन दोनों धातुओं का अनुपात तीन दशक के शीर्ष स्तर 100 पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यह वह स्तर है जो फरवरी 1991 में नजर आया था। फिलहाल यह अनुपात 96.5 है।

जब चांदी सोने से पिछड़ने लगती है, तो यह अनुपात बढ़ जाता है। पहले जब कभी इस अनुपात में काफी अधिक इजाफा हुआ, तो यह कभी भी कायम नहीं रह पाया और इसमें गिरावट आ गई। यह अनुपात बताता है कि एक औंस सोने से कितने औंस चांदी खरीदी जा सकती है। वैश्विक कारोबारियों की तरह भारत में भी कारोबारी इस अनुपात के आधार पर कारोबार करते हैं। अगर उन्हें यह अनुपात बढ़ने की उम्मीद होती है, तो वे सोना खरीदते और चांदी बेचते हैं।

केडिया कमोडिटीज के निदेशक अजय केडिया ने कहा, 'फिलहाल सोने-चांदी का अनुपात 96.5 के स्तर पर है। पिछले छह महीने में इसमें करीब 19 प्रतिशत की उछाल नजर आई है। इस अवधि के दौरान सोने के दाम भी उछलकर 44,960 रुपये (प्रति 10 ग्राम) हो चुके हैं और इसके बाद इनमें नरमी आई है। यह सोने के प्रति साफ तौर पर बाजार की पसंद को बताता है।'

केडिया ने कहा, 'पिछले छह महीने में वैश्विक स्तर पर सोने की मांग अधिक रही है क्योंकि केंद्रीय बैंक सोने की खरीद करते रहे हैं। अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, अमेरिका-पश्चिमी एशिया के भू-राजनीतिक तनाव और कोरोनावायरस के तेज फैलाव से भी सोने के दामों को समर्थन मिला है। बाजार की इन अनिश्चितताओं में सुरक्षित निवेश के रूप में

इस अनुपात के आधार पर कारोबार करते हैं दुनिया भर के कारोबारी

अब भी सोने की खरीद कर रहे हैं। सोने के मुकाबले चांदी स्थिर रही है क्योंकि औद्योगिक मांग कमजोर है। सोने-चांदी का यह अनुपात वर्ष 1991 के 100 के स्तर पर पहुंच सकता है।'

अब तक कारोबारी यही कहते रहे हैं कि यह अनुपात अधिक स्तर पर बरकरार नहीं रहेगा और चांदी सोने से आगे निकलना शुरू कर देगी। अगर सोने में चांदी के मुकाबले ज्यादा तेजी से गिरावट आती है या चांदी में सोने के मुकाबले ज्यादा तेजी आती है तो ऐसा संभव है। हालांकि अब वे ऐसी बात कहने से कतरा रहे हैं क्योंकि मूल धातुओं में कमजोरी के बाद चांदी अब भी मजबूत नहीं दिख रही है। यह बात इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि चांदी की 55 प्रतिशत से अधिक मांग उद्योग की ओर से होती है।

सोने में आगे और इजाफे या चांदी से बेहतर रहने के कई कारण हैं। लंदन स्थित सलाहकार मेटल फोकस ने सोने से संबंधित अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि नए क्षेत्रों में वायरस के प्रसार से नुकसान और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में तीव्र कटौती के अलावा राजनीतिक कोलाहल और भू-राजनीतिक तनाव का असर भी इस धातु के लिए सकारात्मक साबित हुआ है। अन्य दिक्कतों के बीच जो कुछ और दिक्कतें दिखती हैं, उनमें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले अनिश्चितताओं के साथ-साथ ब्रेक्जिट की बातचीत और पश्चिम एशिया में जारी तनाव शामिल हैं।

सोने में और इजाफे का अनुमान लगाते हुए सहालकार कंपनी ने कहा कि हमें यह भी संदेह है कि नीति निर्माताओं द्वारा किए गए राजकोषीय/ मौद्रिक प्रोत्साहन वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए काफी रहेंगे। वायरस के प्रकोप से पहले सभी प्रमुख आरक्षित मुद्राओं की ब्याज दरें ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर नाम मात्र की दर पर रखी गई थीं। केंद्रीय बैंकों की बैलेंस शीट में भी वर्ष 2008 के बाद से इजाफा हुआ है। इसके परिणामस्वरूप निकट अवधि की कुछ बाजार राहत के बावजूद बुनियादी अर्थव्यवस्था के संबंध में ब्याज दरों में अतिरिक्त कटौती और/अथवा मौद्रिक नीति में ढील सीमित की जानी चाहिए। दूसरी तरफ चांदी की कीमतों में किसी भी खास सुधार के संकेत नहीं दिख रहे हैं जो यह बताता है कि निकट अवधि में सोने-चांदी का अनुपात और बढ़ेगा तथा चांदी सोने की तुलना में नरम रहेगी। जनवरी और फरवरी 2020 के दौरान चांदी के 'ईगल' (सिक्के) की संयुक्त बिक्री कुल मिलाकर 45 लाख औंस रही है, जबकि वर्ष 2019 में इसी अवधि के दौरान यह बिक्री 61.8 लाख औंस थी। यह बताता है कि चांदी के सिक्कों की बिक्री कमजोर है।

चिंता की प्रमुख बात चांदी के दामों का रूख है जो इस कैलेंडर वर्ष के पहले पांच से छह सप्ताह में काफी हद तक सीमित थे। किसी निवेशक के दृष्टिकोण से चांदी के दामों का यह प्रदर्शन काफी फीका रहा है, खास तौर पर सोने के दामों में उछाल को देखते हुए।

एक वैश्विक अनुसंधान कंपनी के विश्लेषक के अनुसार कुछ हद तक यह चांदी के दामों की संभावनाओं के मोहभंग को प्रतिबिंबित करता है और यह चिंता प्रकट करता है कि अगर वैश्विक वृद्धि की चिंता गहराती है तो इसे नुकसान होगा।

रत्नाभूषण निर्यात को 5 प्रतिशत झटका

इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी कि कोरोनावायरस देश के रत्नाभूषण निर्यात को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएगा। अब यह आशंका स्पष्ट हो रही है क्योंकि वायरस से प्रभावित ज्यादातर देश वे हैं जिन्हें भारत रत्नाभूषण का ज्यादा निर्यात करता है। उद्योग का अनुमान है कि सामान्य आर्थिक मंदी की वजह से मांग में नरमी के अलावा निर्यात ऑर्डर में पांच प्रतिशत का अतिरिक्त नुकसान हुआ है। अचानक फैली इस महामारी से ऑर्डरों पर असर पड़ा है। हाल ही में वायरस के डर से हॉन्गकॉन्ग में एक प्रमुख प्रोत्साहन कार्यक्रम को भी मई तक टाल दिया गया था। क्रिसमस की मांग के बाद ऐसे बड़े कार्यक्रमों से भारतीय रत्नाभूषण निर्यात के ऑर्डर का बड़ा भाग हथियाने में मदद मिलती है। उद्योग के एक दिग्गज ने कहा कि जिन अधिकांश देशों में हम निर्यात करते हैं, वहां वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। इससे तत्काल रूप से निर्यात में पांच प्रतिशत की गिरावट आएगी।

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जनवरी के बीच पहले 10 महीनों में रत्नाभूषण का सकल निर्यात जनवरी 2020 के दौरान 9.17 प्रतिशत घटकर 296.642 करोड़ डॉलर रह गया है, जबकि जनवरी 2019 में यह 326.588 करोड़ डॉलर था। परिषद के वाइस चेयनमैन कोलिन शाह ने कहा कि परिषद सरकार और बैंकरों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी कि हमारे निर्यातकों की प्राप्ति के ऐवज में क्रेडिट पर असर न पड़े। हमें नए बाजार विकसित करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने होंगे ।

चीन से आयात प्रभावित, कोटेड पेपर की कीमतों में हुआ इजाफा

राजेश भयानी
मुंबई, 8 मार्च

कोरोनावायरस के प्रसार से कोटेड पेपर का निर्माण करने वाली कंपनियां लाभान्वित हुई हैं। इस श्रेणी के कागज के दो कारोबारियों का कहना है कि कोटेड पेपर की बाजार कीमतें 8-10 प्रतिशत तक चढ़ी हैं। चीन से आने वाले कोटेड पेपर की मात्रा में पिछले दो महीनों में भारी गिरावट देखी गई है जिससे घरेलू बाजार को इसका फायदा उठाने और कंपनियों को कीमतें बढ़ाने में मदद मिली है।

बल्लारपुर इंडस्ट्रीज और जेके पेपर भारत में कोटेड पेपर का निर्माण करने वाली दो प्रमुख कंपनियां हैं। लिखने और प्रिंटिंग से संबंधित पेपर- कॉपियर आदि जैसी अन्य श्रेणियों के परिदृश्य में इस तरह का सुधार नहीं देखा गया है। एक महीने पहले 31 जनवरी को सरकार ने सभी श्रेणियों के कागज के लिए 'स्टॉक लॉट' का आयात प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया, जिससे बाजार को कुछ सुधार दर्ज करने में मदद मिली है। स्टॉक लॉट ऐसा आयात है जिसमें अलग-अलग आकार और पेपर के बिना बिके स्टॉक को सस्ती दर पर खरीदा जाता था।

स्टॉक लॉट के तौर पर कागज की आयात सुविधा का उन कुछ कारोबारियों द्वारा भी दुरुपयोग किया जाता रहा है जो स्टॉक लॉट के नाम पर ताजा माल का आयात करते थे। कागज के ताजा स्टॉक की तुलना में स्टॉक लॉट पर कम शुल्क लगता था।

प्रतिबंध के निर्णय से सभी तरह के कागज के स्टॉक लॉट को आयात के लिए प्रतिबंध की सूची में रखा गया है जिससे घरेलू कागज कंपनियों को राहत मिली है, क्योंकि वे अब ताजा स्टॉक बेचने में सक्षम हो गई हैं। जेके पेपर के अध्यक्ष एवं निदेशक ए एस मेहता आयात में कमी के लिए कोरोनावायरस के प्रभाव को कम जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका कहना है, 'पिछले कुछ महीनों में कीमतें कुछ बढ़ी हैं, क्योंकि चीन से कोटेड पेपर का आयात बंदरगाहों पर समस्या की वजह से प्रभावित हुआ। इस वजह से कोटेड पेपर की कीमतें बढ़ गईं, लेकिन कई अन्य श्रेणियों के कागज की कीमतों में नरमी आई है।' कुछ कोटेड पेपर आयात इंडोनेशिया से भी हो रहा है।

कागज बाजार में कोरोनावायरस का नकारात्मक असर भी पड़ा है। फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशंस के पूर्व अध्यक्ष शामजी करिया ने कहा, 'खासकर एमएसएमई क्षेत्रों में परिचालन कर रहे कई छोटे उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति पर दबाव का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए उनका उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, पैकेजिंग के लिए उनकी जरूरत भी काफी हद तक प्रभावित हुई है। इस तरह का एक उदाहरण नकली गहने हैं। हालांकि कुल प्रभाव पैकेजिंग मैटेरियल के लिए इस्तेमाल होने वाले कागज पर दिखा है।' मुंबई के एक अन्य डीलर ने कहा कि यदि चीन से आयात समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे वैकल्पिक स्रोतों से आयात बढ़ सकता है, लेकिन यदि हालात बदतर होते हैं तो कुछ कारोबारी जमाखोरी का कदम उठा सकते हैं।

केयर रेटिंग्स ने कागज उद्योग पर अपने एक ताजा विश्लेषण में कहा, 'चीन में कोरोनावायरस समेत भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं से पैदा हुए सुस्त और विविध कारोबारी हालात से वैश्विक मांग पर प्रभाव बरकरार रहने की आशंका है।'

गैर-धातु खनिज उत्पादन में गिरावट

जयजित दास
भुवनेश्वर, 8 मार्च

खदानों की घटती संख्या के कारण गैर-धातु खानिजों के उत्पादन में गिरावट दर्ज की जा रही है। इन खदानों की संख्या 2018-19 में घटकर 780 रह गई जो 2016-17 में 931 थी। उद्योग में व्यापक इस्तेमाल होने के कारण धातु खनिज हमेशा सुर्खियों में होते हैं, जबकि गैर-धातु खनिज मूल्य के मोर्चे पर इनसे आगे दिखते हैं। वर्ष 2018-19 के अंत में गैर-धातु खनिजों ने 63,011 करोड़ रुपये मूल्य के साथ देश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान किया था। इसके मुकाबले धातु खनिजों का मूल्य 61,009 करोड़ रुपये रहा था।

बेराइट्स, टेल्क, स्टीटाइट, पाइरोफलाइट, केनाइट, एलुसाइट, सिलिमेनाइट और वोलास्टोनाइट जैसे औद्योगिक खनिज के मामले में भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक देश है। फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनिरल इंडस्ट्रीज (फिमी) के उपाध्यक्ष आरएल मोहंती ने हाल में अहमदाबाद में भारतीय औद्योगिक खनिज पर आयोजित सम्मेलन के दौरान कहा था, 'भारत में तमाम औद्योगिक खनिजों का पर्याप्त भंडार मौजूद हैं जिनमें चूना पत्थर, कैल्सियमयुक्त खनिज पदार्थ, बेराइट्स, टेल्क, स्टीटाइट, सिलिका खनिज आदि शामिल हैं। लेकिन एपेटाइट एवं रॉक फॉस्फेट, ग्रेफाइट, एस्बेस्टस, फ्लोराइट और पोटाश जैसे खनिज के उत्पादन में गिरावट आई है अथवा वे दुर्लभ श्रेणी में आ गए हैं। बोरेक्स, डायटोमाइट, पारा और गंधक जैसे औद्योगिक

खदानों की संख्या वर्ष 2018-19 में घटकर 780 रह गई जो 2016-17 में 931 थी

खनिज के लिए घरेलू संसाधन लगभग नगण्य हैं और भारत को आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।'

कुछ औद्योगिक खनिजों के लिए भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर है। जहां तक रॉक फॉस्फेट का सवाल है तो भारत की आयात पर निर्भरता करीब 83 फीसदी है। इसके अलावा ग्रेफाइट, मैग्नेसाइट और गंधक जैसे प्रमुख औद्योगिक खनिजों के लिए आयात पर भारत की निर्भरता 40 फीसदी से अधिक है। मोहंती ने कहा, 'हालांकि यह एक चिंता की बात है कि देश के भीतर मौजूद कई औद्योगिक खनिज संपदा का दोहन नहीं हो पाया है और इसके परिणमस्वरूप गैर-धातु एवं सूक्ष्म खनिजों का वार्षिक उत्पादन लगभग स्थिर है। इसके अलावा वैश्विक बाजारों से भी तगड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है और एक प्रतिस्पर्धी दुनिया में यह जरूरी है कि हमारा उत्पाद आर्थिक तौर पर भी व्यावहारिक हो। उद्योग को अपनी पूरी क्षमता का अवश्य उपयोग करना चाहिए और उसे तकनीकी प्रतिस्पर्धा एवं उत्पादकता के मोर्चे पर आगे बढ़ना चाहिए। घरेलू औद्योगिक खनिज उद्योग को प्रगतिशील बाजार विकास रणनीतियों और उपयुक्त राजकोषीय उपायों से प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि सस्ते आयात का मुकाबला किया जा सके।'

सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों पर जोर और तेजी से शहरीकरण के कार्यक्रमों के मद्देनजर औद्योगिक खनिज की मांग बढ़ने की उम्मीद है। फरवरी 2015 में 31 खनिजों को सूक्ष्म खनिज की श्रेणी में हस्तांतरित कर दिया गया था और इस प्रकार सूक्ष्म खनिज होने के नाते अधिकतर औद्योगिक खनिजों को सरकार की नजर में लाया गया था।

मोहंती ने कहा, 'सरकार को रियायतों, खदानों के विकास में तेजी और अनुकूल कर ढांचे के अलावा अत्याधुनिक तकनीक एवं कौशल विकास के जरिये औद्योगिक खनिज का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुकूलन माहौल तैयार करने की जरूरत है ताकि घरेलू मांग को पूरा करने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी आपूर्ति की जा सके। हमारी गुजरात की खनन कंपनियां वैधानिक मंजूरियां विशेष तौर पर पर्यावरण संबंधी मंजूरियां हासिल करने में काफी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। मंजूरी के लिए तमाम आवेदन राज्य के स्तर पर लंबित हैं।'

अरंडी : 88 प्रतिशत इजाफे के आसार

विनय उमरजी
अहमदाबाद, 8 मार्च

देश में अरंडी का उत्पादन वर्ष 2019-20 के दौरान 88 प्रतिशत तक इजाफे के साथ 20.36 लाख टन रहने की उम्मीद है। एग्रीवॉच के नए सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। पिछले साल देश में 10.82 लाख टन अरंडी का उत्पादन हुआ था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एसईए) की ओर से एग्रीवॉच यानी इंडियन एग्रीबिजनेस सिस्टम लिमिटेड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2019-20 में देश के प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात में अरंडी उत्पादन 96 प्रतिशत तक बढ़कर 17.44 लाख रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यह मौटे तौर पर 8.89 लाख टन था। एसईए ने हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित वार्षिक वैश्विक अरंडी सम्मेलन में इस सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए थे। राज्य सरकार के अनुमान में वर्ष 2019-20 के दौरान गुजरात में अरंडी के तहत कुल रकबा 39 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 7,41,000 हेक्टेयर आंका गया है, जबकि पिछले साल यह लगभग 53,400 हेक्टेयर था। एग्रीवॉच के सर्वेक्षण में यह वृद्धि दर 44 प्रतिशत आंकी गई है।

राज्य सरकार के आंकड़ों की तुलना में एग्रीवॉच के सर्वेक्षण में अनुमान जताया गया है कि वर्ष 2019-20 में अरंडी का रकबा 7,70,150 हेक्टेयर रहेगा। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करने से राज्य में अरंडी उत्पादन 7,53,660 हेक्टेयर रहने का अनुमान है। दिसंबर 2019 में टिड्डी हमले के बावजूद ऐसा होने के आसार है।

एग्रीवॉच का कहना है कि इस साल रकबे में इस बड़े इजाफे की मुख्य वजह पिछले सत्र में किसानों का अरंडी से हुई अधिक आमदनी और उत्पादन करने वाले सभी जिलों में अच्छी मौसमी बारिश है। प्रति हेक्टेयर किलोग्राम उत्पादन के हिसाब से वर्ष 2019-20 में अरंडी का अनुमानित औसत उत्पादन 36 प्रतिशत तक के इजाफे के साथ प्रति हेक्टेयर 2,389 किलोग्राम रहने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल यह औसत 1,751 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। सर्वेक्षण में कहा गया है कि कुल मिलाकर इस वर्ष अच्छे मॉनसून और सिंचाई के लिए पानी की बेहतर उपलब्धता से पैदावार में इजाफे की उम्मीद की जा रही है।

संक्षेप में

धोखाधड़ी जांच करने वाले कर्मचारी बढ़ेंगे

सरकार गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में कार्यबल दोगुना कर 350 करने की तैयारी में है। एसएफआईओ कंपनी में गड़बड़ी पर अंकुश लगाने के प्रयास को और मजबूत करने के लिए कार्यबल की संख्या दोगुना कर रहा है। कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा कि एसएफआईओ को और पेशेवर बनाने और उसे दुरुस्त करने की प्रक्रिया जारी है। श्रीनिवास ने कहा, कंपनियों में धोखाधड़ी काफी जटिल है। हमारी चुनौती एसएफआईओ के लिए क्षेत्र विशेष के जानकारों लोगों को जोड़ने की है। उन्होंने कहा कि कार्यबल की संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़ाई जाएगी। यह संख्या बढ़ाकर 133 से 150 करने का प्रस्ताव है। *भाषा*

डब्ल्यूटीओ में उठेगा विशेष रियायत का मुद्दा

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत जैसे विकासशील देशों के साथ विशेष और अलग व्यवहार के तहत रियायत का मुद्दा प्रमुखता से उठेगा। यह बैठक कजाकिस्तान में जून में होगी। मंत्री स्तरीय सम्मेलन 164 सदस्यीय डब्ल्यूटीओ का निकाय है। बैठक में सभी सदस्य देशों के व्यापार मंत्री भाग लेंगे। 12वां सम्मेलन कजाकिस्तान के नूर-सुल्तान में इस साल 8-11 जून को होगा। *भाषा*

विवाद से विश्वास की बढ़ सकती है तिथि

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 8 मार्च

सरकार की प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान की प्रमुख योजना 'विवाद से विश्वास' की तिथि बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए 31 मार्च अंतिम तिथि तय की गई है। बगैर किसी अतिरिक्त कर के विवादों के समाधान के लिए लाई जा रही इस योजना की अधिसूचना अभी तक नहीं आ सकी है, साथ ही कोरोनावायरस की वजह से भी समस्या हो रही है।

आयकर विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि ज्यादातर लोगों को इस योजना में हिस्सा लेने के लिए धन की व्यवस्था करने में वक्त की जरूरत होगी और कोरोनावायरस के कारण फैली अफरातफरी की वजह से भारत की कुछ फर्मों के लिए धन का इंतजाम करना मुश्किल होगा। कई फर्मों के वैश्विक मुख्यालयों को बचाव के कदम के तहत अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया था। धन विधेयक होने के कारण इसे राज्यसभा में मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। बहरहाल यह उच्च सदन में जाएगा, जो बदलाव की सिफारिश कर सकता है, लेकिन यह लोकसभा पर निर्भर है कि वह इसे स्वीकार करे या न करे। इसके बाद से विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा और स्वीकृति मिलने के बाद इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा।

इसकी वजह से योजना का अधिकतम लाभ पाने के लिए करदाता को बमुश्किल एक पखवाड़े का वक्त मिलेगा।

एक कर अधिकारी ने कहा, 'इस योजना की तिथि बढ़ाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, अन्यथा करदाता को इस योजना में हिस्सा लेने के लिए पर्याप्त मौका नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से यह ज्यादातर के लिए अनुचित होगा। इसके अलावा कोविड 19 जैसी उचित चिंता भी है, जिस पर विचार किए जाने की जरूरत है।'

एक और कर अधिकारी ने कहा कि कंपनियां उनके पास विदेश स्थित कंपनी मुख्यालय से मंजूरी मिलने में देरी जैसी समस्या को लेकर आ रही हैं, जो पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे हैं, वहीं कई को अभी यह फैसला करना है कि उन्हें योजना में शामिल होना है या नहीं।

इस तरह के 4,00,000 से ज्यादा मामले हैं, जिनमें कम से कम 9.3 लाख करोड़ रुपये का विवाद है और वे इस योजना में शामिल हो सकते हैं।

अगर योजना का ज्यादातर लाभ लेना है तो कर का भुगतान 31 मार्च तक करना होगा। अन्यथा यह योजना 30 जून तक खुली रहेगी, लेकिन बकाये पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करना होगा, अगर यह भुगतान 31 मार्च के बाद किया जाता है। ऐसी स्थिति में योजना आकर्षक नहीं रह जाती।

इसके पहले 2016 में आई विवाद समाधान योजना में 7 महीने का वक्त दिया गया था और 31 दिसंबर को अंतिम तिथि बीतने के बाद एक महीने का अतिरिक्त विस्तार दिया गया। इसी तरह पुराने सेवा कर और उत्पाद कर के मामलों के लिए पेश की गई सबका विश्वास उत्तराधिकार विवाद समाधान योजना की अंतिम तिथि भी एक महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 की गई थी।

एकेएम ग्लोबल के पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा, 'तमाम मामलों में फैसला करना आसान नहीं है, खासकर उन मामलों में, जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल थीं। ऐसे में इसमें वक्त लगेगा। हाल ही में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल जारी किए गए थे और हम समय से इसे करने की दौड़ लगा रहे हैं।'

उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस भी भारत के कार्यालयों के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वैश्विक व एशिया में स्थित मुख्यालयों में होने वाले कामकाज पर असर डाल रहा है, ऐसे में समय सीमा का विस्तार स्वागत योग्य कदम होगा।

एएमआरजी एसोसिएट्स के पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि करदाताओं को इस पर विचार, चर्चा व फैसला करने के करने के लिए बहुत कम वक्त दिया गया है, जबकि विवाद विभिन्न मंचों पर चल रहे हैं और बहुत ज्यादा तकनीकी मसले भी हैं। ऐसे में 31 मार्च तक भुगतान का वक्त देना उन्हें इससे दूर करेगा। उन्होंने कहा, 'इससे यह योजना अपना आकर्षण खो रही है। भुगतान की तिथि बगैर किसी ब्याज जैसे जुर्माने के 3 महीने तक बढ़ाए जाने से तमाम करदाताओं को इस योजना की तरफ आकर्षित किया जा सकता है।'

घोषणा की प्राप्ति की तिथि के 15 दिन के भीतर प्राधिकृत अधिकारी (डीए) को भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण करना होगा और भुगतान की जाने वाली राशि का प्रमाणपत्र जारी करना होगा। उसके बाद घोषणा करने वाला विवादित कर की राशि कर देयता तय किए जाने के 15 दिन के भीतर करेगा। इस स्पष्टीकरण के हिसाब से करदाता को 31 मार्च तक बहुत कम वक्त मिलेगा क्योंकि अभी भी विधेयक आना बाकी है।

31 मार्च है अंतिम तिथि

- कोरोनावायरस और देर से अधिसूचना की वजह से तिथि बढ़ने की संभावना
- कम वक्त मिलने से कंपनियों को धन जुटाने में आएगी दिक्कत

2019-20 में प्रत्यक्ष कर संग्रह

	लाख करोड़ रु.	% वृद्धि
बजट अनुमान	13.35	17.30
संशोधित अनुमान	11.7	2.80
संग्रह (अप्रैल-जन.)	7.45	-6.25
शेष संग्रह (फर.-मार्च)	4.25	20

स्रोतः सीजीए, बजट

फंड प्रबंधकों को मिलेगा बेमियादी लाइसेंस

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 8 मार्च

पेंशन फंड नियामक अगले 2 महीने में आवेदन प्रस्ताव (आरएफपी) जारी करेगा और बेमियादी आधार पर फंड प्रबंधकों का चयन करेगा। इस समय फंड प्रबंधकों को इस तरह के लाइसेंस 5 साल के लिए जारी किए जाते हैं।

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के नव नियुक्त चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'अगले 2 महीने में हम नए आरएफपी ला रहे हैं और लाइसेंस बेमियादी आधार पर जारी किए जाएंगे।' उन्होंने कहा कि पीएफआरडीएफ को उम्मीद है कि मौजूदा 7 फंड प्रबंधक और कुछ अन्य इस आरएफपी में आवेदन करेंगे।

बेमियादी लाइसेंस का मतलब यह हुआ कि यह लाइसेंस तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक कि फंड प्रबंधक खुद बाहर न होना चाहें या वह लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन न करें। फंड प्रबंधकों को सिर्फ लाइसेंस के नवीकरण के शुल्क का भुगतान करना होगा।

पीएफआरडीए ने फंड प्रबंधकों की अधिकतम सीमा 10 तय कर रखी है। इस पर फिर से विचार किया जाना है कि यह संख्या बढ़ाई जाए या नहीं।

बंद्योपाध्याय ने स्पष्ट किया कि लाइसेंस बेमियादी होगा, लेकिन इन्हें टैप पर जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ किया, 'टैप का मतलब है कि आप कुछ योग्यता की शर्तें रखते हैं और कोई भी अगर शर्त पूरी करता है तो वह आवेदन कर सकता है और आरएफपी जारी हुए बगैर वह लाइसेंस हासिल कर सकता है।'

पीएफआरडीए टैप लाइसेंस का विकल्प क्यों नहीं अपना रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि प्राधिकरण आरएफपी प्रक्रिया में फंड प्रबंधन शुल्क के बारे में भी फैसला करता है। उन्होंने कहा, 'टैप लाइसेंस के मामले में हम ऐसा नहीं कर सकते।'

नियामक इस शुल्क में भी मौजूदा की तुलना में मामूली बढ़ोतरी करने पर विचार कर रहा है। बंद्योपाध्याय ने कहा, 'इस समय फंड प्रबंधन शुल्क बहुत मामूली है। यह महज एक आधार अंक है, जिसका मतलब यह है कि हर 100 रुपये पर आप सिर्फ 1 पैसे शुल्क लेते हैं। हमें लगता है कि इसे बढ़ाए जाने की संभावना है, जिसे पेंशन फंड को पेशेवर रूप दिया जा सके।'

अभी फंड प्रबंधन शुल्क के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, 'हम यह जानने की कवायद करेंगे कि आदर्श शुल्क क्या हो सकता है।' यह पूछे जाने पर क्या पीएफआरडीए बाद में टैप पर लाइसेंस जारी करने का फैसला करेगा, उन्होंने कहा, 'देखते हैं कि हमारे आरएफपी में क्या प्रतिक्रिया आती है।'

इस समय 7 फंड प्रबंधक- एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड, एसबीआई पेंशन फंड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस और आदित्य बिड़ला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट हैं।

निजी क्षेत्र के पेंशन फंड प्रबंधक

- एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट
- कोटक महिंद्रा पेंशन फंड
- एलआईसी पेंशन फंड
- एसबीआई पेंशन फंड
- यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस
- आदित्य बिड़ला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट

सार्वजनिक क्षेत्र के पेंशन फंड प्रबंधक

- एलआईसी पेंशन फंड
- एसबीआई पेंशन फंड
- यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस

किराये पर कम उठेंगे कार्यालय

देश के 7 प्रमुख शहरों में 2020 के दौरान कार्यालय स्थलों को किराए पर लिए जाने की स्थिति में 14 प्रतिशत तक गिरावट आने की संभावना है।

वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी जेएलएल के अनुसार समीक्षावधि में यह शुद्ध तौर पर 4 करोड़ वर्गफुट क्षेत्रफल रह सकता है। वर्ष 2019 में कार्यालय स्थल किराए पर उठने की वृद्धि दर 40 प्रतिशत रही और 4.65 करोड़ वर्गफुट का कार्यालय स्थल किराए पर लिया गया। वर्ष 2018 में यह मात्र 3.32 करोड़ वर्गफुट था। इसी तरह नए कार्यालय स्थल की आपूर्ति 2019 में 45 प्रतिशत बढ़कर 5.16 करोड़ वर्गफुट रही जो 2018 में 3.57 करोड़ वर्गफुट थी।

जेएलएल इंडिया देश के सात बड़े संपत्ति बाजार दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलूरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता पर नजर रखती है।

जेएलएल इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में शुद्ध तौर पर करीब 4 करोड़ वर्गफुट का कार्यालय स्थल किराए पर उठने की संभावना है। जबकि इस क्षेत्र में नए कार्यालय स्थल की आपूर्ति 4.75 करोड़ वर्गफुट रहने का अनुमान है। *भाषा*

रियल्टी, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में खरीद अन्य क्षेत्रों से ढाई गुना

राघवेंद्र कामत
मुंबई, 8 मार्च

ऑडिट और सलाहकार फर्म ईवाई और इंडियन वेंचर कैपिटल ऐंड प्राइवेट इक्विटी एसोसिएशन (आईवीसीए) की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अन्य संपत्ति श्रेणी की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा नियंत्रणकारी खरीद हुई है। 2019 में रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे में खरीद 11.6 अरब डॉलर रही, जबकि अन्य संपत्तियों में खरीद 4.6 अरब डॉलर रही है।

बदली स्थिति

इसमें कहा गया है, 'पीई/वीसी निवेश में पिछले तीन साल के दौरान खरीद में स्थिर बढ़ोतरी कुल मिलाकर वृद्धि में अहम रही है, वहीं 2019 में सौदों की प्रकृति में थोड़ा अंतर रहा है। 2017 और 2018 के विपरीत, जब पीई/वीसी संपत्ति श्रेणी में खरीद गतिविधियों में वृद्धि हुई, 2019 में बुनियादी ढांचा और रियल एस्टेट संपत्ति श्रेणी में खरीद की गतिविधियों में वृद्धि देखी गई।'

इसमें कहा गया है कि 2019 में रियल एस्टेट में निवेश के कुल मूल्य का 59 प्रतिशत खरीद थी। 2019 में रियल एस्टेट में निवेश 33 प्रतिशत बढ़कर 6.1 अरब डॉलर हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'इसमें से बड़ा हिस्सा खरीद सौदों का था, जो पहले की धारणा से अलग है, जब रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़े निवेश कर्ज के निवेश होते थे।' रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट में खरीद 2015 के 0.4 प्रतिशत से बढ़कर 3.6 प्रतिशत हो गई है। 2016, 2017 और 2018 के बड़े हिस्से में रियल एस्टेट के आवासीय और वाणिज्यिक विकास में बड़े पैमाने पर निवेश कर्ज के माध्यम से हुआ था।

एनबीएफसी क्षेत्र में नकदी के संकट और बैंकों का एनपीए बढ़ने के साथ रियल एस्टेट क्षेत्र में इन क्षेत्रों से वित्तपोषण कम हुआ है। इसमें कहा गया है, 'बहरहाल 2018 और 2019 में बदलाव आने लगा और खरीद का जोर बढ़ने लगा। ब्लैकस्टोन और अन्य बड़े खरीद फंड वाणिज्यिक रिटेल, गोदाम और औद्योगिक रियल एस्टेट क्षेत्र में अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया।'

येस संकट से छोटे कारोबारी भी मुश्किल में

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 8 मार्च

येस बैंक संकट से छोटे कारोबारियों में हड़कंप मच गया और उन्हें कारोबार प्रभावित होने का डर सता रहा है। कारोबारियों के बीच अपने चालू खाते अब निजी बैंक के बजाय सरकारी बैंकों में रखने की चर्चा जोर-शोर से होने लगी है।

येस बैंक के साथ चालू खाता रखने वाले पुरानी दिल्ली के एक कारोबारी ने बताया,' मुझे बैंक ने 50 लाख रुपये की लिमिट दी हुई है। लिमिट लेने वाला कारोबारी किसी दूसरे बैंक के साथ खाता नहीं रख सकता है। येस बैंक संकट के कारण अब मैं माल देने वाले को भुगतान नहीं कर सकता और न इस खाते में भुगतान ले सकता हूं। ऐसे में आगे राहत नहीं मिलने पर कारोबार ही ठप हो जाएगा'। दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने कहा कि संगठन ने सदस्यों से देश में निजी बैंकों के घोटालों को देखते हुए अपने बैंक खाते सरकारी बैंकों में स्थानांतरित करने और गाड़ियों का बीमा भी सरकारी बीमा कंपनियों से ही कराने की अपील की है। ऑटोमेटिव पार्ट्स मर्चेंट एसोसिएशन (अपमा) के कोषाध्यक्ष उमेश सेठ ने कहा कि येस बैंक के साथ चालू खाता रखने वालों के रोजमर्रा के कारोबारी लेन देन प्रभावित होंगे। इस वित्त वर्ष का अंतिम महीना होने के कारण जिन कारोबारियों के खाते येस बैंक के साथ उन्हें कर जमा करने के साथ वित्त वर्ष की समाप्ति पर होने वाले काम काज प्रभावित होंगे।

इस बीच, कारोबारियों को मुद्रा नोट से भी कोरोनावायरस जैसे संक्रामक रोग फैलने के खतरे से कारोबार प्रभावित होने का डर सता रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स(कैट) के महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि विभिन्न अध्ययनों और मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि मुद्रा नोटों से संक्रामक रोग फैलते हैं। कारोबारी इन नोटों का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। इसलिए कैट ने केंद्रीय वित्त मंत्री, स्वास्थ्य व वाणिज्य मंत्री को पत्र लिखकर मुद्रा नोटों से कोरोना जैसे संक्रामक नोट फैलने की संभावना का आकलन करने की अपील की है। सरकार को नोटों के विकल्प डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देना चाहिए।

अफरातफरी की स्थिति

- चालू खाते पर लिमिट सुविधा लेने वाले कारोबारियों को भुगतान में दिक्कत
- कारोबारियों के बीच निजी के बजाय सरकारी बैंक में खाते रखने की चर्चा
- कारोबारियों में नोटों से कोरोना फैलने का डर, सरकार से जांच की मांग

कारोबार सुगमता की रैंकिंग होगी जिलावार

बीएस संवाददाता
लखनऊ, 8 मार्च

उत्तर प्रदेश में अब जिलावार कारोबार सुगमता (ईज आफ डूइंग बिजनेस) की रैंकिंग की जाएगी और निवेश करारों की ट्रैकिंग भी की जाएगी। जिन जिलों में निवेश के ज्यादा प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं वहीं से इसकी शुरुआत होगी।

प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) आलोक टंडन के मुताबिक राज्यों के लिए बिजनेस एक्शन रिफॉर्म एक्शन प्लान (ब्रैप) की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के जिलों में कारोबार सुगमता सुधारों को लागू किया जाएगा। फिर इन सुधारों के कार्यान्वयन के आधार पर जिलों की रैंकिंग की जाएगी। आईआईडीसी ने कहा कि पहले चरण में उन 5 या 6 जिलों का चयन किया जाएगा, जहां निवेश के आवेदनों की संख्या 5,000 से अधिक है। जिलों के स्तर पर कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर उद्योग विभाग के साथ सहयोग के लिए समर्पित मानव संसाधन तैनात किए जाएंगे।

प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने कहा कि पहले चरण में पांच जिलों में जिला सुधार कार्य योजना लागू की जाएगी, जहां निवेश मित्र, एमओयू ट्रैकर और प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली के कुशल कार्यान्वयन और प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त जनशक्ति की तैनात की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन सुधारों के कार्यान्वयन में जिलों के प्रदर्शन के मुताबिक उनकी रैंकिंग की जाएगी। उद्योग बंधु, निवेशकों और उद्योगपतियों को विभिन्न नीतियों के तहत प्रोत्साहन, उद्यमों की मंजूरी व अन्य सहूलियतों के लिए एक ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली विकसित कर रहा है। नई ऑनलाइन सुविधा, निवेश मित्र सिंगल विंडो पोर्टल के साथ एकीकृत की जाएगी। पोर्टल यह भी सुनिश्चित करेगा कि आवेदन की स्थिति संबंधित विभाग द्वारा प्रत्येक चरण पर अपडेट की गई है, जिससे आवेदक अपने आवेदनों की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकें। इन सुविधाओं में एक ऑनलाइन एमओयू ट्रैकर, प्रभावी और पारदर्शी ऑनलाइन भूमि आवंटन के लिए जीआईएस के साथ-साथ मौजूदा 125 निवेश मित्र सेवाओं में लगभग 30 और सेवाओं को जोड़ने की योजना शामिल है।

आलोक कुमार ने बताया कि जल्द ही व्यावसायिक और अन्य भवन मानचित्रों के अनुमोदन भी निवेश मित्र के जरिए ऑनलाइन दिए जाएंगे। अभी तक निवेश मित्र के जरिए केवल औद्योगिक उद्देश्य के लिए भवन निर्माण योजना अनुमोदित की जा रही थी।

आईआईडीसी ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में दो साल पहले हुए निवेशक सम्मेलन में घोषित की गई निवेश परियोजनाओं में से लगभग 38,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाली 90 निवेश परियोजनाओं में वाणिज्यिक कामकाज शुरू हो गया है। इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जनवरी तक 16,691.18 करोड़ रुपये के निवेश के साथ उत्तर प्रदेश में कुल 1.26 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और भारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई थी।

बीएस सूडोकू 3684 | परिणाम संख्या 3683

9		7	4			3		6
6				9		8		
	8	1	3	7	6	4		
				5	3		8	2
5								3
3	1		6	2				
		5	8	3	7	6	4	
		3		6				8
8		6			2	5		7

3	6	4	5	1	7	2	8	9
8	2	5	4	9	6	7	1	3
1	7	9	3	2	8	5	4	6
7	3	1	2	8	4	9	6	5
6	4	2	9	5	3	8	7	1
5	9	8	7	6	1	3	2	4
9	8	7	1	4	5	6	3	2
4	5	6	8	3	2	1	9	7
2	1	3	6	7	9	4	5	8

कैसे खेलें?

हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत मुश्किल ★★★★★

नकदी का इस्तेमाल नोटबंदी के पहले के स्तर पर

अरूप रायचौधरी
नई दिल्ली, 8 मार्च

भारत में नकदी का इस्तेमाल दिसंबर 2017 से दिसंबर 2019 के बीच 23 प्रतिशत बढ़ा है। कैश लॉजिस्टिक्स फर्म सीएमएस इन्फो सिस्टम्स की शुक्रवार को आई एक रिपोर्ट के मुताबिक नकदी का इस्तेमाल नोटबंदी के पहले के स्तर पर आ गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉजिस्टिक्स और आभूषण जैसे उद्योगों में पिछले 2 साल के दौरान नकदी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बढ़ा है, जबकि ई-कॉमर्स और बैंकिंग में इसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई है।

सीएमएस की रिपोर्ट सीएमएस कैश इंडेक्स में अप्रैल 2016 से दिसंबर 2019 तक के आंकड़े लिए गए हैं। सीएमएस कैश इंडेक्स में प्रचलन में नकदी, कंपनी के एटीएम में नकदी और खुदरा नकदी प्रबंधन चैनलों को शामिल किया जाता है। रिपोर्ट में कंपनी ने कहा है, 'हमारा विश्लेषण भारत के 2,300 से ज्यादा स्थलों पर आधारित है, इसमें 98 प्रतिशत जिले और 11,090 पिन कोड शामिल हैं।' पिछले दिसंबर में सूचकांक 120 पर पहुं गया, जो अक्टूबर 2016 से भी ऊपर था।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'हमने पाया कि पिछले 2 साल में एटीएम चैनलों के माध्यम से नकदी की मांग 16 प्रतिशत बढ़ी है। प्रति व्यक्ति नकद निकासी वाले प्रमुख राज्यों में उन राज्यों के नाम शामिल हैं, जहां आर्थिक विकास ज्यादा हुआ है। इनमें दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक आदि शामिल हैं। बीमारू राज्यों बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में प्रति व्यक्ति नकद निकासी कम है।'

रिपोर्ट में कहा गया है, 'जिन राज्यों में नकद निकासी में तेज वृद्धि हुई है, उनमें असम, छत्तीसगढ़ और केरल शामिल हैं, जबकि सुस्त नकद निकासी वाले राज्यों में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बिहार शामिल हैं।' इसमें कहा गया है कि त्योहारी सीजन में नकद निकासी 15 से 20 प्रतिशत बढ़ी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आभूषण, टोल और राजमार्ग, युटिलिटी और पेट्रोलियम में नकदी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जबकि कम नकदी इस्तेमाल करने वाले क्षेत्रों में फुटवीयर, ड्यूरेबल्स और टेलीकॉम शामिल हैं।

उम्मीद से इतर

- दिसंबर 2017 से दिसंबर 2019 के बीच नकदी का इस्तेमाल 23 प्रतिशत बढ़ा
- लॉजिस्टिक्स और आभूषण उद्योगों में नकदी का इस्तेमाल बढ़ा
- ई-कॉमर्स व बैंकिंग में नकदी का इस्तेमाल कम

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 19

न्याय में देरी

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में अपने उद्बोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि के शासन के महत्त्व की बात की। इतना ही नहीं उन्होंने इस संदर्भ में तीव्र गति से न्याय प्रदान करने की भूमिका को भी रेखांकित किया।

प्रधानमंत्री का यह कहना सही है कि खासतौर पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का, भले ही वे विवादास्पद क्यों न हों, सरकार की शाखाओं और आम जनता द्वारा खूब सम्मान किया जाता है। अत्यधिक हाई प्रोफाइल मामलों का अत्यंत तेज गति से निपटारा करना और विधि के शासन का सम्मान करना भी एक अहम पहलू है।

ऐसे में यह खेद की बात है कि हालिया अतीत में देश की सबसे बड़ी अदालत कुछ गहन संवैधानिक और राजनीतिक महत्त्व के मसलों को सुगमतापूर्वक निपटाने में विफल रही है।

मौजूदा दौर के सबसे विवादास्पद मसलों में से एक मसला है राष्ट्रीय राजधानी के शाहीन बाग जैसे स्थानों पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन करने के अधिकार का। सर्वोच्च न्यायालय ने अब इस विषय पर सुनवाई 23 मार्च तक टाल दी है।

यह अपने आप में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली में हालिया हिंसा का कुछ संदर्भ इस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ नाराजगी से भी जुड़ा है। ऐसे में सुनवाई टाला जाना और खेदजनक है। अदालत भी निष्क्रिय नहीं बैठी है। उसने अदालत की ओर से प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए दो प्रतिष्ठित लोगों को वार्ताकार नियुक्त किया। परंतु अधिक तेज गति से निस्तारण शायद दिल्ली में हाल में उपजे तनाव को कम करने में मदद करता। एक अन्य अहम संवैधानिक और राजनीतिक मसला चुनावी बॉन्ड से ताल्लुक रखता है। ऐसे मामलों में इतनी भी देरी नहीं की जानी चाहिए कि वे विवादित हो जाएं।

संविधान के अनुच्छेद 370 के समाप्त होने से उपजे मसलों और इसके कारण पूर्व जम्मू कश्मीर प्रांत में कठोर सैन्य नीति को लेकर भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे गंभीर संवैधानिक मसलों को जल्द से जल्द निपटाना चाहिए।

आखिर सर्वोच्च न्यायालय का उद्देश्य भी तो यही है। आखिरकार न्यायालय ने इंटरनेट बंदी के व्यापक विषय पर निर्णय दिया। उसने ऐसे प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया पर कुछ प्रतिबंध लगाए।

इसके बावजूद कश्मीर पर लगे प्रतिबंधों का विशिष्ट प्रश्न लंबे समय तक टाला गया। इसके अलावा एक बुनियादी सवाल बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार का है। विधि के शासन वाले देशों में सदियों से न्यायपालिका के बुनियादी कामों में से एक बंदी बनाने की वैधता के नियम से जुड़ा है। परंतु हाई प्रोफाइल मामलों में भी मसलन पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद फारुख अब्दुल्ला को बंदी बनाए जाने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उतनी तेजी से काम नहीं किया जितना उसे करना चाहिए था। इस विषय में नोटिस छह दिन बाद जारी किया गया। इस अंतराल का इस्तेमाल सरकार ने अब्दुल्ला पर जन सुरक्षा अधिनियम की धारा लगाने में किया। ऐसा न्यायिक हस्तक्षेप में देर होने की वजह से हो सका।

इसमें दो राय नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में अंतिम और सही निर्णय पर पहुंचने से पहले पूरा समय लेना चाहिए। खासतौर पर ऐसे मामलों में जो राष्ट्रीय महत्त्व के हैं। बहरहाल, यदि न्यायिक निर्णय बहुत देरी से आता है तो उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। यदि ऐसा होता है तो खुद न्यायिक प्रक्रिया की प्रासंगिकता के लिए ही जोखिम उत्पन्न हो जाती है।

अजय मोहंती

मजबूत नेता की आर्थिक सफलता जरूरी नहीं

मोदी सरकार के छह वर्ष के कार्यकाल के बाद आंकड़े तथा आम अहसास यही साबित करते हैं कि आवश्यक नहीं कि मजबूत नेता निर्णायक आर्थिक नीति सुनिश्चित कर सके।

अब वक्त आ गया है कि भारतीय राजनीति के हम जैसे विश्लेषक दो स्वीकारोक्तियां करें। पहली, हम पिछले कुछ समय से गलत प्रश्न पर बहस कर रहे हैं। और दूसरी यह कि हम गलत जवाब का साथ देते रहे।

सन 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से ही यह सवाल बना रहा है कि क्या अच्छी अर्थनीति अच्छी राजनीति की राह बनाती है? दूसरे शब्दों में क्या आप आर्थिक सुधार करके, सरकार और अफसरशाही का आकार घटाकर, कुछ ताकत बाजार को देकर, वृद्धि मजबूत बनाकर दोबारा चुनाव जीत सकते हैं? यदि नहीं तो इसके लिए क्या करना होगा? इसका उत्तर यह रहा है कि एक मजबूत नेता चुनें जो राजनीतिक जोखिम उठाने से डरता नहीं हो। केवल ऐसा करके ही अच्छी अर्थनीति हासिल की जा सकती है। ऐसे मजबूत नेता में यह राजनीतिक पूंजी होगी कि वह आर्थिक सुधारों के अलोकप्रिय दुष्परिणाम मसलन असमानता में इजाफा और पूंजीवाद का रचनात्मक विनाश आदि को गौण बना सके। जाहिर है वह और उसके साथ हम सभी विजेता होंगे।

हालिया राजनीतिक इतिहास यह दर्शाता है कि हम दोनों ही मोर्चों पर गलत रहे। हम इंदिरा गांधी के दौर के बाद के सबसे मजबूत नेतृत्व के छठे वर्ष में हैं। कुछ लोग, खासतौर पर नरेंद्र मोदी के समर्थक यह भी कह सकते हैं कि मोदी उनसे भी मजबूत हैं। आखिर उन्होंने ऐसे जोखिम उठाए और निर्णय लिए जो वह अपने शिखर दिनों में भी नहीं कर पाईं, भले ही वह ऐसा चाहती रही हों। मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना। या फिर जैसा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर (मौजूदा कैबिनेट में एक दुर्लभ विद्वान हैं) ने इस सप्ताह नई दिल्ली में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन में कहा था, कई विवादास्पद मुद्दों को यूंही टाला जा रहा था, मोदी सरकार ने उन पर निर्णय लेने की ताकत दिखाई है। यह सब ठीक है और अगर आप मोदी के वफादार हैं (बड़ी तादाद में भारतीय उनके वफादार हैं भी जिन्होंने भाजपा को दोबारा सत्ता सौंपी है) तो यह बहुत अच्छा लगेगा। परंतु कुछ सवाल बाकी हैं। पहला तो यही कि यदि देश का सबसे मजबूत और साहसी नेता अभी भी अच्छी राजनीति कर रहा है तो क्या इसने अच्छे अर्थशास्त्र का मार्ग प्रशस्त किया? या फिर अपने कमजोर पूर्ववर्ती से कुछ बेहतर कर पाए हैं? हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप ने जिसे चुना है उस निर्णय पर आप पछताएं। आपके मतदान के पीछे सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि कई तरह के कारण होते हैं। मजबूत और शक्तिशाली नेता के चुनाव के पीछे भी यही तर्क होते हैं। संस्कृति, राष्ट्रवाद, धर्म, वाक कला, करिश्मा आदि तमाम बातें शामिल हो सकती हैं। परंतु प्रश्न यही है कि क्या मजबूत नेता का अर्थ मजबूत अर्थनीति भी होता है? सन 2019 की गर्मियों में मोदी दोबारा और बड़े बहुमत से चुनकर आए तो दो बातें साबित हुईं। पहली बात, उन्होंने अच्छी राजनीति की और दूसरा वृद्धि में ठहराव, बढ़ते घाटे और बेरोजगारी के बावजूद मतदाताओं ने उन्हें वोट दिया।

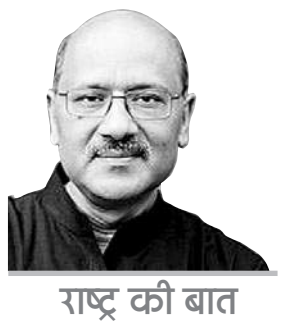

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि इन तमाम वर्षों के दौरान हम पहला प्रश्न ही गलत पूछते रहे: क्या अच्छी अर्थनीति अच्छी राजनीति को जन्म देती है? सवाल यह होना चाहिए था: क्या अच्छी और सफल राजनीति को अर्थव्यवस्था की परवाह करने की जरूरत है? उत्तर एकदम स्पष्ट है: यदि आप अपनी राजनीति को समझते हैं, सही भावनात्मक पहलुओं को स्पर्श कर सकते हैं, पर्याप्त तादाद में लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं तो वे बेरोजगारी, वृद्धि कृषि आय में ठहराव जैसी बातों की अनदेखी कर देंगे।

मोदी के कई मतदाता तो आर्थिक आंकड़ों की ओर देखते भी नहीं। खासतौर पर तब जबकि अन्य उपायों की मदद से लोगों को 'बेहतर' महसूस कराया जा सकता हो। 'बेहतर' महसूस करने की इसी भावना पर सवार होकर वाजपेयी सरकार ने सन 2004 के चुनाव में दोबारा जीत हासिल करने का विफल प्रयास किया था। इसके लिए उसने 'इंडिया शाइनिंग' का नारा दिया था। यह मानते हुए कि हमारा बुनियादी सवाल गलत था, हम अगले सवाल का रुख करते हैं। मजबूत नेता हमें वह देता है जिसकी हमें आकांक्षा होती है: बिना तात्कालिक राजनीतिक नुकसान का आकलन किए निर्णायक आर्थिक नेतृत्व, जो सबके लिए लाभदायक हो। परंतु आज कोई आंकड़ा या अहसास हमें वह राहत नहीं प्रदान करता।

पिछले कुछ समय से तमाम आर्थिक संकेतक नकारात्मक हो चुके हैं: वृद्धि, घाटा, व्यापार (निर्यात और आयात), निवेश, बचत, रोजगार आदि, आदि। इकलौती अच्छी खबर बुनियादी ढांचा क्षेत्र से आ रही है। सन 1991 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था कभी भी इतने लंबे समय तक स्थायी गिरावट या ठहराव पर नहीं थी। तो क्या मजबूत नेतृत्व अच्छी और साहसी अर्थनीति की गारंटी नहीं है? किसी वैचारिक विश्लेषण को आंकड़ों के माध्यम से पूर्वग्रह ग्रस्त या उपयुक्त साबित करना अत्यंत कठिन है। बहरहाल, हम खुशनसीब हैं कि क्वार्ट्जडॉटकॉम की भूराजनैतिक रिपोर्टर एनालिसा मेरेली ने स्टेफनी रिजियो और अहमद सकाली द्वारा रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी ऐंड विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के लिए किए गए अध्ययन की रिपोर्ट के रूप में हमें यह अनमोल चीज दी है। यह अध्ययन लीडरशिप क्वार्टर्ली नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ था।

इन शोधकर्ताओं ने 133 देशों के सन 1858 से 2010 (152 वर्ष) के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि मजबूत नेता अपनी अर्थव्यवस्थाओं के लिए नुकसानदेह रहे या बेमानी। ऐसे में आप सवाल कर सकते हैं कि सिंगापुर के ली क्वान यू अथवा रवांडा के पाल कागामे जैसे 'उदार तानाशाहों' को क्या मानें? अध्ययन कहता है कि ऐसे ताकतवर नेताओं में इक्कादुक्का संयोग से अच्छे भी निकलते हैं लेकिन मोटे तौर पर तो उनका अपने देश की अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक असर पड़ता है। मेरेली अपने अध्ययन में कहती हैं, 'अधिकतकर शक्तिशाली नेताओं ने अपने देश की अर्थव्यवस्थाओं को उससे भी बुरी हालत में छोड़ा जिस हालत में वह उन्हें मिली थी। या फिर उन्होंने उस आर्थिक लहर की सवारी की जिसे आना ही था।' ये सारे नेता तानाशाह नहीं थे। इनमें से कई लोकतांत्रिक देशों में उत्पन्न हुए और लगातार चुनावों का सामना किया। प्रश्न यह है कि मतदाताओं ने उन्हें दंडित क्यों नहीं किया? मतदाता ऐसे नेताओं की तुलना में कमजोर नेताओं को जल्दी दंडित क्यों करते हैं? भारतीय संदर्भ में बात करें तो आपातकाल के कारण इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर करने के बाद मतदाता तीन वर्ष से भी कम समय में उन्हें वापस सत्ता में ले आए। मजबूत नेता के प्रति यह कैसा खिंचाव है? उपरोक्त शोध इस बारे में वानरों के दृष्टांत का सहारा लेते हुए कहता है कि कठिन समय में वे सबसे मजबूत नर वानर का नेतृत्व स्वीकारते हैं। इससे साबित होता है कि पहले सवाल की तरह हम उसका जवाब भी गलत तलाश रहे थे। यानी यह सही नहीं है कि मजबूत नेता आर्थिक मोर्चे पर भी बेहतर होगा। मोदी के कार्यकाल पर नजर डालिए।

मेरी नजर में उनका सबसे साहसी और सुधारवादी कदम था नया भूमि अधिग्रहण विधेयक। वह इकलौता ऐसा कदम है जिससे वह पीछे हटे। अपनी सत्ता और लोकप्रियता के शिखर पर वह यह जोखिम लेने से पीछे हट गए। छह साल में ऐसा केवल एक बार हुआ। सबसे बुरे और बिना सोचे समझे लिए गए नोटबंदी के निर्णय पर वह टिके रहे।

इससे उन्हें राजनीतिक लाभ भी मिला। कम से कम उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो नोटबंदी के तत्काल बाद हुए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे उनकी निर्णायक नेता की छवि और मजबूत हुई थी। मुक्त बाजार सुधार, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, कम शुल्क दरों, मुक्त व्यापार, कम कर दर और न्यूनतम सरकार का समर्थक होते हुए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी दलील के समर्थन में थॉमस पिकेटी का सहारा लेना पड़ेगा। मैं उनकी पहली किताब को सतही मानता हूं लेकिन अपनी दूसरी किताब कैपिटल ऐंड आइडियोलॉजी में उन्होंने समझदारी की बात की है। वह लिखते हैं, 'असमानता न तो आर्थिक है और तकनीकी। यह वैचारिक और राजनैतिक है।' उनके मुताबिक यह तब तक बनी रहेगी जब तक मजबूत नेता इसके बावजूद अपनी प्रभुताशाली राजनीति और विचारधारा के साथ फलते-फूलते रहेंगे।

विजेता टीम के चयन में वेल्च की कारगर सोच

वर्ष 2005 में हार्परकॉलिंस से प्रकाशित पुस्तक 'विनिंग' ने जैक वेल्च की शिखर यात्रा के बारे में काफी कुछ बताया था। वेल्च का गत सप्ताह निधन हो गया। जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) से सेवानिवृत्त होने के बाद भी वेल्च 'मुख्य कार्याधिकारियों (सीईओ) के सीईओ' के रूप में जाने जाते रहे। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उनसे यह पूछा गया था कि 'वह कौन सी बात है जिसे आपको साक्षात्कार में किसी व्यक्ति से पूछना चाहिए ताकि आप तय कर सकें कि वह नौकरी पर रखने लायक है या नहीं।' वेल्च अपनी हाजिर-जवाबी के लिए मशहूर थे लेकिन इस सवाल ने उन्हें भी लाजवाब कर दिया। इसका जवाब उन्हें कुछ साल बाद जाकर मिल पाया।

'विनिंग' में वेल्च कहते हैं कि अगर किसी साक्षात्कार में वह किसी एक क्षेत्र को परखना चाहेंगे तो वह यह होगा कि उसने पिछली नौकरी और उससे भी पहले की अपनी नौकरी किन कारणों से छोड़ी थी? वेल्च ने लिखा था, 'क्या वह कारण दफ्तर का माहौल था? या फिर बॉस के कारण नौकरी छोड़ी? कहीं टीम की वजह से तो उसने नौकरी नहीं छोड़ी थी? आखिर किस कारण से नौकरी छोड़ी थी? इन सवालों के जवाब में काफी जानकारियां होती हैं। गहराई तक कुरेदने पर बहुत कुछ निकलेगा। हो सकता है कि उम्मीदवार किसी भी नौकरी या कंपनी से बहुत ज्यादा अपेक्षा रखता है। शायद वह ऐसा बॉस चाहता है जो एकदम दखल न देता हो या फिर उसके टीम मेंबर हमेशा सहमत ही हों। संभव है कि वह अपनी नौकरी से बहुत ज्यादा और बहुत जल्द इनाम चाहता है। या फिर वह अपनी नौकरी इसलिए छोड़ रहा है कि उसके पास वह सब है जिसकी आपको अपेक्षा है: ऊर्जा से भरपूर, अधिक लोगों का प्रबंधन करने की काबिलियत, किसी नखरेबाज नियोक्ता को सहने की क्षमता और अधिक चुनौतियों पर खरा उतरने के लिए सशक्त क्षमता से लैस।'

वेल्च की इन बातों का सारांश यह है कि किसी व्यक्ति के अपनी नौकरी छोड़ने की वजह जानने से आपको उसके बारे में किसी भी दूसरे माध्यम से कहीं अधिक जानकारियां मिलती हैं। दुनिया भर में प्रबंधकों के चयन में इस

इंसानी पहलू
श्यामल मजूमदार

सलाह से मदद मिलेगी जबकि साक्षात्कार प्रक्रिया में अमूमन इस प्रवृत्ति को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसकी वजह यह है कि अच्छे लोगों की भर्ती करना मुश्किल है और बेहतरीन लोगों की भर्ती तो और भी मुश्किल काम है।

एक चयन साक्षात्कार में पूछे जाने वाले उनके कुछ अन्य पसंदीदा सवाल इस तरह हैं: आपका प्रतिस्पर्द्धी परिवेश किस तरह का नजर आता है? पिछले तीन वर्षों में आपके प्रतिस्पर्द्धियों ने क्या किया है? इस दौरान आपने क्या कुछ किया है? वेल्च की यह मजबूत राय थी कि किसी भी काबिल अगुआ या प्रबंधक को इन सवालों के जवाब देने के लायक होना चाहिए।

हाल के वर्षों में कई लोगों ने वेल्च की रणनीति, नेतृत्व शैली और विरासत पर सवाल उठाए हैं। वह हर साल 10 फीसदी कर्मचारियों को हटाने की अपनी नीति के तहत हजारों लोगों की छंटनी करने की वजह से 'न्यूट्रॉन जैक' के नाम से भी काफी मशहूर रहे। लेकिन यह सच है कि वह भर्ती के तौर-तरीकों में कई क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए और उनके भीतर सही लोगों को चुनने की विलक्षण प्रतिभा थी। वह 'अधिक अगुआई, कम प्रबंधन' के अपने नजरिये के तहत अपने प्रबंधकों को निखरने का पूरा मौका देते थे।

भर्ती के बारे में वेल्च की सोच ने 'फोर ई ऐंड वन पी' के चर्चित सिद्धांत को जन्म दिया। इसमें एनर्जी (ऊर्जा), एनर्जाइज (जोश भरना), एज (उकसाना) और एक्जीक्यूशन (क्रियान्वयन) के साथ पैशन (जुनून) पर जोर रहता है। इन बिंदुओं का मतलब इस तरह है:

ऊर्जा: वेल्च का मानना था कि ऊर्जा से भरपूर लीडर में यह अहसास जगेगा कि यथास्थिति पर्याप्त नहीं है और अगर पिछले साल की ही तरह इस साल भी प्रदर्शन रहता है तो वह नाकाफी है। एक अंक वाली वृद्धि दर काफी नहीं है और हमेशा जैसा कारोबार उतना पर्याप्त नहीं है।

जोश भरना: जोश से भरपूर लोग अपनी टीम के भीतर असंभव लगने वाले लक्ष्य को भी हासिल करने और उसका लुत्फ उठाने को प्रेरित कर सकते हैं। जोश भरने की क्षमता उन लोगों में साफ नजर आती है जिन्हें अपने कारोबार की गहरी समझ होती है। ऐसे लोग व्यक्तिगत तौर पर सशक्त उदाहरण पेश करते हैं और उनमें दूसरों को अपनी बात मानने के लिए राजी करने की खास क्षमता भी होती है।

उकसाना: दूसरों को बेहतर प्रदर्शन के लिए उकसाने की क्षमता से लैस लोग सही समय पर फैसले लेते हैं और नए नवाचारों, नए बाजार एवं अवसरों की पहचान रखते हैं। उनमें सोच-समझकर जोखिम लेने की क्षमता होती है और वे दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं।

क्रियान्वयन: साक्षात्कारकर्ता इस पहलू को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। किसी व्यक्ति के पास बेहतरीन विचार हो सकते हैं लेकिन क्या वह इसे क्रियान्वित भी कर सकता है? बढ़िया क्रियान्वयन दक्षता वाले लोग आसानी से कोई वादा नहीं करते हैं। और अगर एक बार वादा कर लेते हैं तो शीर्ष प्रबंधन या बोर्ड को भी पता होता है कि इस काम को पूरा माना जा सकता है।

जुनून: यही वह पहलू है जो चारों अन्य बिंदुओं को एक साथ जोड़े रखता है। किसी भी लीडर में अपने काम को लेकर जुनून होना चाहिए क्योंकि ऐसा होने पर ही वह उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना सबकुछ दे सकता है।

वेल्च इस बात को लेकर पूरी तरह स्पष्ट थे कि इस भर्ती प्रक्रिया को अपनाने पर आपको ऐसे प्रबंधक मिलते हैं जो किसी भी दूसरे व्यक्ति से बेहतर ढंग से अपना काम पूरा कर सकते हैं। इस तरीके से वे न केवल कर्मचारियों में एक दृष्टि विकसित करने के साथ प्रोत्साहित कर पाएंगे बल्कि अपने उपभोक्ताओं को भी इस नजरिये में यकीन दिला पाएंगे।

कानाफूसी

केरल भाजपा में असंतोष

भारतीय जनता पार्टी ने सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर छिड़े आंदोलन का चेहरा बन चुके नेता के सुरेंद्रन को केरल प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही पार्टी और उसके मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच के मतभेद पूरी तरह सतह पर आ गए। दरअसल राज्य में पार्टी के जो चार महासचिव हैं, सुरेंद्रन भी उनमें से एक हैं और उन्हें केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के खेमे का सदस्य माना जाता है। मुरलीधरन को पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। वहीं प्रदेश भाजपा का एक और खेमा है जिसके नेता पी के कृष्णदास हैं जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इतना ही नहीं दास को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आशीर्वाद हासिल है। शायद यही वजह थी कि सुरेंद्रन को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के एक दिन बाद ही केरल प्रदेश भाजपा के दो महासचिवों ए एन राधाकृष्णन और एम टी रमेश ने केंद्रीय नेतृत्व से यह आग्रह किया कि उनको पदमुक्त कर दिया जाए। जाहिर है राज्य इकाई में असंतोष पनप रहा है।

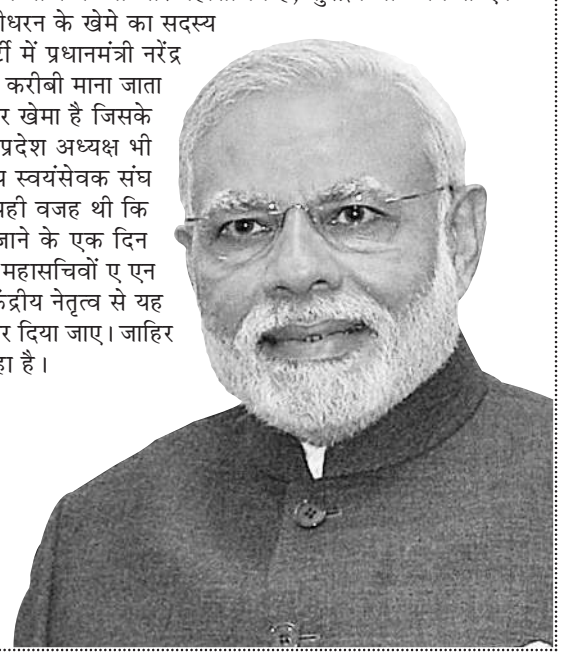

आपका पक्ष

भारतीय महिलाओं ने लहराया परचम

आज भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। महिला वैज्ञानिक पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही हैं। नासा से लेकर इसरो तक, मंगल से लेकर चंद्रयान-2 तक में इनका बड़ा योगदान है। लेकिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी उम्मीद से काफी कम है। पुरुषों की तुलना में इनकी संख्या न सिर्फ कम है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था में बाधाओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिक शोध एवं अनुसंधान ऐसा ही एक क्षेत्र है, जिसमें महिलाओं का उत्कृष्ट योगदान और क्षमता के बावजूद उन्हें समुचित प्रोत्साहन और अवसर नहीं मिल रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह पढ़ाई छोड़ देना है। इसके अलावा महिलाएं घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती हैं। असल में घर चलाने का जिम्मा महिलाओं के कंधे पर डाल दिया जाता है। महिलाओं ने विज्ञान के क्षेत्र में काफी योगदान दिया है, लेकिन महिला वैज्ञानिकों को कभी

वह सम्मान नहीं मिल सका जिसकी वे हकदार थीं। 19वीं सदी में चिकित्सक आनंदीबाई जोशी से शुरू हुई यात्रा बीसवीं सदी में जानकी अम्माल, कमला सोहोनी, अण्णा मणि, असीमा चटर्जी, राजेश्वरी चटर्जी, दर्शन रंगनाथन, मंगला नारलीकर जैसी अनेक वैज्ञानिकों के जरिये मौजूदा सदी में यमुना कृष्णन, शुभा तोले, प्रेरणा शर्मा, नीना गुप्ता आदि तक पहुंची है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर महिला वैज्ञानिकों के नाम पीठ बनवाने का निर्णय लेकर महिलाओं को एक नई दिशा प्रदान की है। इससे न केवल उन वैज्ञानिकों को सम्मान मिला है, बल्कि विज्ञान जगत के इस क्षेत्र में महिलाओं को बढ़-चढ़ कर आगे बढ़ने के हौसले को भी प्रोत्साहन मिला है। भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में अपना शत प्रतिशत देती रही हैं। भारत सरकार ने 11 महिलाओं को सम्मान देने का सराहनीय कदम उठाया है। इनमें डॉ इरावती कर्वे, डॉ जानकी अम्मल, डॉ राजेश्वरी चटर्जी, डॉ रमन परिमला, कमल रणदिवे, डॉ दर्शनरंगनाथन, मुतैया वनीता, रितु करिधल, अनुराधा टीके, मिनल संपत, डॉ सीता सोमासुंदरम, टेसी थॉमस हैं। महिला वैज्ञानिकों ने चिकित्या विज्ञान, इंजीनियरिंग, वनस्पति विज्ञान, आनुवांशिकी और गणित क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। जब भी महिलाओं को मौका मिला है उन्होंने परचम लहराया ही है।

महिला दिवस पर राष्ट्रपति से नारी शक्ति पुरस्कार लेतीं कौशिकी चक्रवर्ती *-पीटीआई*

अनु मिश्रा, सीवान

अमेरिका-तालिबान के बीच समझौता

हाल में अमेरिका और तालिबान के बीच करीब 19 साल के बाद शांति समझौता हुआ है। समझौते के मुताबिक 14 माह में अमेरिकी और नाटो सैनिक अफगानिस्तान से वापस लौट जाएंगे। लेकिन तालिबान अपनी आदतों से बाज नहीं आया और अफगानिस्तान की सेना के अलग-अलग अड्डों पर हमला किया। कुल 16 प्रांतों में किए गए तैंतीस हमले में कई आम नागरिकों सहित कम से कम 21 लोगों की जान चली गई और 29 से ज्यादा लोग घायल हो गए। शांति समझौते के एक सप्ताह में ही तालिबान ने हिंसात्मक गतिविधियों को दोहराना शुरू कर दिया। इसके बावजूद तालिबान से शांति समझौते की उम्मीद कैसे की जा सकती है। जाहिर सी बात है कि तालिबान अपने रुख में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और इसी तरह हमला करता रहेगा। इसलिए अमेरिकी सेना का अफगानिस्तान में रहना जरूरी है।

गौतम एसआर, खंडवा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

कोरोना से मचा है हाहाकार, अब भारत बढ़ाए अपना व्यापार

दीपक शर्मा

देसी कारोबार को झटका

कोरोनावायरस ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला है। आयात-निर्यात के साधन इससे प्रभावित हुए हैं कुछ तो लगभग बंद ही हैं। ट्रांसपोर्ट, मनोरंजन और कच्चे माल की उपलब्धता इससे प्रभावित हुई है। देसी कारोबारी पूर्वआयातित कच्चे माल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। आयात पर निर्भर देसी कारोबारियों का व्यापार इससे प्रभावित होगा। खासकर छोटे उद्यमी इससे काफी प्रभावित होंगे क्योंकि उनके पास कच्चे माल के सीमित साधन होते हैं। कई क्षेत्रों के व्यापारी इससे परेशान हैं लेकिन चिकित्सा क्षेत्र को इससे लाभ होगा। मास्क और दस्तानों की मांग में भारी वृद्धि आई है।

पंकज चौहान
बैतूल, मध्य प्रदेश

देसी कारोबार के लिए अवसर भी

कोरोनावायरस का देसी कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना आरंभ हो गया है। चीन से कच्चे माल का आयात बाधित होने के कारण दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के मूल्य लगभग 45 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। ऐसे में कोरोनावायरस भारत के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। सरकार को इस मौके का फायदा उठाने के लिए मेक इन इंडिया पर और अधिक जोर देना होगा जिससे कि वाहन कलपुर्जा से लेकर कपड़ा, स्टील, उपभोक्ता वस्तु आदि की रिक्तता भरी जा सके।

मो. मंसूर आलम
चंदौली, उत्तर प्रदेश

कच्चे माल के लिए दिक्कत

कोरोनावायरस के प्रकोप से सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि चीन से व्यापारिक संबंध रखने के कारण भारत में एक ओर आर्थिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो दूसरी ओर भारत में घरेलू उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहित भी किया जा सकता है। भारत चीन पर मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक, चिकित्सा, सर्जिकल उपकरण, फार्मास्युटिकल और मोबाइल आदि के उत्पादन में प्रयोग होने वाले कच्चे माल के लिए निर्भर है जिनका स्टॉक खत्म होने की स्थिति में भारत की घरेलू कंपनियों को संभवत: कच्चे माल के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

रोली श्रीवास्तव
नई दिल्ली

व्यवसाय पर मंडराया खतरा

देसी कारोबार पर कोरोनावायरस का प्राथमिक असर यह होगा कि आपूर्ति शृंखला में विचलन और घरेलू मांग भी कमजोर होगी। चीन के उत्पाद भले ही गुणवत्ता में खरे न हों पर सस्ती होने के कारण वैश्विक बाजार में इनकी लोकप्रियता है। भारत में चीन के उत्पाद सबसे ज्यादा खपाये जाते हैं। कोरोनावायरस फैलने का असर अभी हाल में ही विनिर्माण गतिविधियों पर देखा गया। पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स फरवरी 2020 में 54.5 पर रहा। यह आंकड़ा जनवरी के 55.3 अंक की तुलना में कम है। देसी कारोबारों में चीन के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, खिलौने, सौंदर्य प्रसाधन व खाद्य पदार्थ आदि का एक बड़ा बाजार भारत है और चीन ही क्यों अन्य देश जैसे ईरान, कोरिया, सिंगापुर आदि देशों से भी भारत के देसी कारोबार पर असर पड़ेगा।

डॉ रसिकेश नवजात
जौनपुर, उत्तर प्रदेश

कारोबार पर नजर आ रहा असर

वित्तीय बाजार में उतार चढ़ाव का सिलसिला चीन में इस महामारी के फैलने के साथ ही साफ दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ अन्य सभी मंत्रालय स्थिति से निपटने के लिए भरपूर सहयोग कर रहे हैं। बैंकिंग नियामक द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उनसे नकदी प्रवाह बेअसर रहने के भी संकेत हैं। जहां दुनिया भर के कारोबार में असर दिखाई दे रहा हो, वहां भारत का अंदरूनी व्यापार इससे अछूता कैसे रह सकता है? कोरोनावायरस से प्रभावित देसी कंपनियों/इकाइयों को कर्ज भुगतान में रियायत मिलने के आसार भी हैं। एहतियात के तौर पर बंदरगाह, हवाई अड्डे, देसी कार्गो भंडार आदि को आगाह कर 24 घंटे आपूर्ति शृंखला कार्यरत रहने के आदेश भी मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए हैं।

हिम्मत जोशी
नागपुर, महाराष्ट्र

देसी सामान की बिक्री को मजबूती

चीन में फैक्टरियों में छुट्टियों से भारत में आयात किए जा रहे सस्ते चीनी सामान अब महंगे हो गए हैं। कोरोनावायरस की वजह से सूरत के हीरा उद्योग को अगले दो महीने में करीब 8,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। कोरोनावायरस से संक्रमण का असर होली के बाजार में भी देखने को मिल रहा है। दिसंबर तक जितना भी चीनी सामान बाजार में आया, उसे छोड़कर पूरे बाजार में देसी सामान देखने को मिल रहे हैं। लोग संक्रमण के कारण चीनी सामान को खरीदने से भी बच रहे हैं। भारतीय दवा कंपनियों को कच्चे माल का डर सता रहा है। देश का शेयर बाजार भी बुरी तरह सहम गया है। चीन में निर्मित स्मार्टफोन की भारत में अब कमी होने लगी है। वायरस का असर फरवरी में भारत की विनिर्माण गतिविधियों की रफ्तार कुछ सुस्त पड़ने के रूप में देखने को मिला है।

सुधीर कुमार सोमानी
देवास, मध्य प्रदेश

पहली छमाही में रहेगी सुस्ती

भारत में इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी, मैकेनिकल उपकरण, कार्बनिक रसायनों, प्लास्टिक और सर्जिकल उपकरण आदि का चीन से बड़े पैमाने पर आयात होता है। देश के कुल आयात में इन चीजों की हिस्सेदारी 28 फीसदी है। इनकी आपूर्ति बाधित होने से ये महंगे भी हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर चीन में स्थिति नहीं सुधरती है तो इन चीजों की आपूर्ति पर असर पड़ेगा। चीन में कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण भारत से कॉटन निर्यात पर विपरीत असर पड़ने की संभावना है। कोरोनावायरस का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ रहा है। निवेशकों का मानना है कि आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ने से कंपनियों के नतीजे पर विपरीत असर पड़ रहा है। कोरोनावायरस के वैश्विक कारोबार पर असर और विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में भारत के इस साल के शुरुआती 6 महीने सुस्त रहने के आसार है।

अंकित जोशी
दिल्ली

नुकसान के साथ फायदे भी

चीन में फैले कोरोनावायरस का असर अब धीरे धीरे उद्योग धंधों पर भी दिखने लगा है। कई क्षेत्रों के उद्योगों का कच्चा माल चीन से आता है। पिछले कुछ दिनों से उद्यमियों का कच्चा माल नहीं आया है लिहाजा अब वे परेशान नजर आ रहे हैं और उनके उद्योग पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों को कच्चे माल की कमी होने लगी है जिसका निर्यात और घरेलू उद्योग दोनों पर ही विपरीत असर होगा। खासकर घरेलू फार्मा कंपनियों द्वारा इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का एक बड़ा हिस्सा चीन से आयात किया जाता है लेकिन चीन में विनिर्माण क्षेत्र ठप होने से भारतीय कंपनियों पर असर पड़ सकता है। भले ही आयाततित कच्चे माल की कमी हो रही है लेकिन इससे कई भारतीय उद्योगों को लाभ मिल सकता है। मेक इन इंडिया को ज्यादा फायदा हो सकता है।

साक्षी पांडे
ग्वालियर, मध्य प्रदेश

मंदी में घरेलू कारोबार

चीन में इस महामारी से निपटने की सारी व्यवस्थाएं फीकी पड़ती जा रही हैं और वहां की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। चीन एक बहुत बड़ा उत्पादक देश है और भारत में उसका व्यापार व्यापक रूप से फैला है। कम मूल्य पर वस्तु तैयार कर वैश्विक बाजार पर आधिपत्य जमाने वाला चीन आज इस महामारी की गिरफ्त में है। ऐसे में वैश्विक व्यापार मंदा पड़ने से देशी व्यापार भी सुस्त हो गया है। शेयर बाजार भी धड़ाम से गिर रहा है। इस वैश्विक समस्या से जूझने के लिए विश्व के सभी देशों तथा नागरिकों को एक दूसरे के साथ मिलकर आगे आना होगा अन्यथा चीन ही नहीं पूरा विश्व आर्थिक मंदी के बुरे दौर से गुजरने को मजबूर हो जाएगा।

विवेकानंद मिश्र
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

सहमा सहमा भारतीय बाजार

भारत में विभिन्न तरह के त्योहार मनाए जाते हैं और इन त्योहारों को कारोबार के लिहाज से हमेशा मुफीद माना जाता है पर इस बार कोरोनावायरस का खमियाजा व्यपापारियों को भरना होगा। जैसा कि ये कारोबारी भी मानते हैं कि चीन निर्मित उत्पाद बेचने में लाभ 50 फीसदी से ज्यादा होता है पर अब व्यापारी वर्ग उस लाभ से वंचित है। भारत जैसे देश में जहां कोई भी उत्पाद की सफलता उसकी कीमतों पर निर्धारित होती है, उस लिहाज से चीन में और अन्य देशों में कोरोनावायरस के खौफ का असर भारत के बाजारों में साफ दिख रहा है।

डॉ राम हर्ष गुप्ता
मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश

घरेलू कारोबार पर भी आंच

कोरोनावायरस ने चीन को तो अपनी चपेट में लिया ही है, उससे कारोबारी संबंध रखने वाले देश भी व्यापारिक संकट से जूझने लगे हैं। भारत प्रमुख रूप से दवा, कीटनाशक, वाहन, मोबाइल पुर्जे चीने आयात से करता है। चीन में इस वायरस के कारण उद्योगों की गति ठहर गई है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में कारोबारियों को आयातित सामान का भंडार समाप्त होने की चिंता सता रही है। इनकी कमी देश के कारोबार पर सीधे असर डालेगी जिसका प्रभाव बाजार व देश की अर्थव्यवस्था पर भी होगा। कोरोनावायरस का प्रभाव बाजार के लिए कठिनाई भरा है जो वैश्विक महामारी के रूप में भी परिलक्षित हो सकता है। इसके प्रभाव से देसी कारोबार अछूता रह पाएगा, इसमें संशय ही है।

प्रदीप माथुर
अलवर, राजस्थान

अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा

कोरोनावायरस चीनी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर ही चुका है। यह विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा खतरा बन गया है। चीन में बन रहे हर तरह के उत्पाद दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद चीन में बनते हैं क्योंकि वहां कच्चा माल और श्रम सस्ता है। कई भारतीय कंपनियां भी कच्चे माल और कलपुर्जों के लिए चीन पर ही निर्भर हैं। भारत में चीन से आयात होने वाले सामान की किल्लत के कारण अनेक वस्तुओं और दवाओं के दाम बढ़ने की आशंका है। ऑटोमोबाइल, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियां चीन से ही कच्चा माल मंगाती हैं। होली के खिलौने की आपूर्ति नहीं होने से इस बार होली फीकी ही रहेगी। इस प्रकार चीनी उत्पादों ने भारतीय बाजार पर कब्जा कर रखा है तो स्वाभाविक ही है कि चीन में फैला यह वायरस भारत के देसी कारोबार को प्रभावित किए बना नहीं रहेगा।

अनिल कोथुलकर
इंदौर, मध्य प्रदेश

पर्यटन उद्योग पर पड़ रही मार

सघन आबादी क्षेत्र होने के कारण हमारे देश में कोरोना का खतरा ज्यादा है। सुस्त अर्थव्यवस्था के बीच इस संक्रामक बीमारी की मार हमारे देश के व्यापार पर बड़ी चोट कर सकती है। पिछले तीन माह में चीन जैसी बड़ी और निरंतर विकसित हो रही आर्थिक ताकत को इस वायरस ने तहस नहस कर दिया है। चीनी अर्थव्यवस्था में गिरावट का असर भारत पर पड़ना लाजमी है। चीन से निर्यात रुक जाने के कारण भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कोरोना के प्रसार के भय से अनेक देशों के नागरिकों के वीजा निलंबित कर दिए गए हैं। इससे भारत में पर्यटन गतिविधियां ठप पड़ रही है।

रवींद्र प्रकाश
मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव

भारत दवा बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर है। यद्यपि बाजार में अभी भी बड़ा जोखिम उत्पन्न नहीं हुआ है। लेकिन बुनियादी जरूरत वाली वस्तुओं के भंडारण में कमी आने से इनकी कीमतों में वृद्धि हो सकती है। भारत इस अवसर का लाभ उठाकर घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में कमी का लाभ भारतीय बाजार को मिल सकता है। यदि निवेशक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत में निवेश करते हैं तो भारतीय बाजार को लाभ हो सकता है। जो कंपनियां आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भर हैं या जिनका चीन के बाजार में निवेश है, वे सबसे अधिक प्रभावित हैं।

दीप्ति विश्वास
ई-मेल से

बकौल विश्लेषक

देसी कारोबार पर मार, निर्यातकों के लिए मौका भी

चीन से फैले कोरोनावायरस का चीन के साथ ही वैश्विक कारोबार पर भी बुरा असर पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है क्योंकि भारत में चीन से बड़े पैमाने पर कई उद्योगों के लिए कच्चा माल आता है। साथ ही तैयार सामान भी आयात होते हैं। चीन में कोरोनावायरस से भारतीय उद्योग जैसे फार्मा, इस्पात, ऊर्जा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक व रत्न एवं आभूषण आदि को कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित होने से नुकसान होगा। लेकिन कच्चे माल की इस कमी को देसी निर्माताओं के लिए अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है। सरकार को इन कच्चे माल को बनाने वाली देसी कंपनियों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि ये कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकें। कच्चे माल के अलावा चीन से देश में रोजमर्रा की जरूरत के सस्ते तैयार उत्पाद मसलन खिलौने, लाइटिंग सामान, त्योहारों पर पिचकारी, राखी, दिए आदि भी बड़े पैमाने पर आयात होते हैं। इन तैयार उत्पादों को एकदम से नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए कोरोनावायरस का इस देसी कारोबार पर सबसे ज्यादा असर हो सकता है। देश में कोरोनावायरस के मामले आने के बाद पर्यटन, होटल, थोक व खुदरा बाजार समेत अन्य क्षेत्रों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। कोरोनावायरस से देसी कारोबार पर बुरे असर के साथ ही निर्यात के मामले में मौका भी है। भारत ऐसे कई देशों को निर्यात करता है, जिनमें चीन भी निर्यात कर रहा है। कोरोनावायरस के कारण इन देशों को चीन का निर्यात थमेगा। यहीं भारत के लिए मौका है। चूंकि भारत पहले से इन देशों को निर्यात कर रहा है। इसलिए बाजार तैयार करने जैसी दिक्कत नहीं आएगी। भारत को सिर्फ इन देशों को निर्यात होने वाले उत्पादों की देश में उत्पादन क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को भी उद्योग की मदद करनी चाहिए। भारत को 10 प्रमुख निर्यात बाजार मसलन अमेरिका, यूके, यूएई, हान्ग कान्ग, सिंगापुर, जर्मनी आदि को निर्यात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर कोरोनावायरस से देसी कारोबार पर चोट तो पड़ेगी, लेकिन यह देश के निर्यातकों के लिए अपना कारोबार बढ़ाने का एक अच्छा मौका भी साबित हो सकता है।

बातचीत: रामवीर सिंह गुर्जर

डॉ. एस पी शर्मा
मुख्य अर्थशास्त्री, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री

कोरोनावायरस से देसी कारोबार पर मार, आगे राहत की आस

कोरोनावायरस का देसी कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। पहले चीन में नए साल की छुट्टियों के कारण कारखाने बंद थे, फिर इस वायरस का प्रकोप बढ़ने के कारण तय समय पर कारखाने न खुलकर 20-25 दिन बाद अब खुलने शुरू हो गए हैं। कारखाने देर से खुलने के कारण चीनी सामान की आपूर्ति भारत में प्रभावित होने से इनके दाम बढ़े हैं। चीन से आयातित कच्चे माल की आपूर्ति बाधित होने से देसी कारखानों पर भी बुरा असर पड़ा है। अब हालांकि चीन में कारखाने खुलने लगे हैं, जिनसे अगले 15-20 दिन में माल की आवक शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में आगे हालात सुधरने की संभावना है। लेकिन इस समय देश में भी कोरोनावायरस के मामले बढ़ने के कारण एक नई समस्या खड़ी हो गई है जिससे देश के बाजारों में खरीदार आने से कतरा रहे हैं। दिल्ली जैसे व्यापार के अहम वितरण केंद्र से बाहरी राज्यों के कारोबारी फिलहाल दूरी बनाते दिख रहे हैं। देश के होटल, पर्यटन उद्योग पर भी कोरोनावायरस का इस समय बुरा प्रभाव देखा जा रहा है। कोरोनावायरस से देश में खिलौने, मोबाइल, इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, दवा, सोलर पैनल आदि के कारोबार पर मार पड़ी है। सरकार को भविष्य में ऐसी स्थिति से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए लंबी अवधि की नीति बनानी चाहिए। सरकार को ऐसे देसी उत्पाद बनाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जो तैयार उत्पाद चीन से बड़े पैमाने पर आयात किए जाते हैं। सरकार को चीन से आयातित कच्चे माल के देश में निर्माण को भी बढ़ावा देना चाहिए। कुल मिलाकर कोरोनावायरस का देसी कारोबार पर बुरा असर तो हुआ है, लेकिन अब चीन में कारखानों में उत्पादन की शुरुआत के साथ आगे चीनी सामान की आपूर्ति सुधरने की उम्मीद है। भारत में कोरोनावायरस नियंत्रित होने के बाद देश में बाजारों से दूर हो रहे खरीदार भी लौटने लगेंगे। लिहाजा आगे कोरोनावायरस का देसी कारोबार पर बुरा असर दूर होने की उम्मीद है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

बातचीत: रामवीर सिंह गुर्जर

देवराज बवेजा
चीनी सामान आयातक व अध्यक्ष, दिल्ली व्यापार महासंघ

पुरस्कृत पत्र

देसी कारोबार पर मार और मौका

चीन से फैले कोरोनावायरस के वैश्विक स्तर पर तेजी से पांव पसारने से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। भारत चीन से वाहन के पुर्जों, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी इत्यादि का आयात करता है। कोरोनावायरस की वजह से इन वस्तुओं का आयात बाधित हो रहा है लिहाजा आगे चलकर देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ सकती है। कोरोनावायरस से भारत में विदेशी पर्यटकों की आवक प्रभावित होने से कमाई घटेगी। विकल्प के तौर पर भारत दो ही चीजें कर सकता है पहला किसी दूसरे देश से वस्तुओं का आयात शुरू किया जाए। देश में आयात की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण के उपाय हों। अगर भारत खुद ही वस्तुओं को बनाने लगे तो चीन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी और देश में रोजगार भी बढ़ेंगे। शुरुआत के एक दो साल को छोड़ दें तो आने वाले पांच दस साल में इसका फायदा भारत में देखने को मिलेगा।

अमन कुमार मरांडी
दिल्ली

पुरस्कार राशि
500 रुपये

श्रेष्ठ पत्र

अनिल कुमावत
भीलवाड़ा, राजस्थान

कारोबारी मौके भी

यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोनावायरस के कारण भारत का 34.8 करोड़ डॉलर का व्यापार प्रभावित होने का अनुमान है। भारत अपने कुल आयात का लगभग 16 फीसदी केवल चीन से आयात करता है। कोरोनावायरस का असर चीन के साथ होने वाले आयात व निर्यात दोनों पर होगा। पिछले 2 महीनों से भारत का चीन से आयात बहुत कम हो चुका है। भारत के बहुत सारे उद्योग कच्चे माल और कलपुर्जों के लिए चीन पर निर्भर है। भारत में रोजमर्रा की चीजें महंगी होने की संभावना है। भारतीय पर्यटन उद्योग की स्थिति भी चरमरा गई है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत के पास निर्यात और घरेलू उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने का मौका भी है ताकि वह वैश्विक आपूर्ति शृंखला में अपनी भागीदारी बढ़ा सकें।

राजेश कुमार चौहान
जालंधर, पंजाब

मिला जुला असर

कोरोनावायरस से होली का कारोबार प्रभावित हो सकता है। कुछ व्यापारियों के अनुसार होली पर चीनी सामान की कमी है और इनके दाम भी बढ़ चुके हैं। पिचकारी पर सीमा शुल्क 20 से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दी गई। चीन में फैले कोरोनावायरस से देश में स्वदेशी वस्तुओं और इससे जुड़े कारोबार के बेशक अच्छे दिन आने की उम्मीद है। लेकिन देश में कुछ उत्पाद या कारोबार ऐसे भी हैं, जिनका कच्चा माल चीन से आयात होता है। इसलिए देश में उन वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि होने की आशंका है। जो सामान देश से चीन को निर्यात होता है, वह भी प्रभावित होगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कोरोनावायरस देसी कारोबार पर थोड़ा अच्छा तो थोड़ा बुरा असर डालने वाला है। देश को कोरोनावायरस से व्यापार को प्रभावित होने से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

अनुराधा
दिल्ली

अच्छा बुरा दोनों

चीन में कोरोना के प्रकोप के बाद पूरे विश्व में 50 अरब डॉलर के वैश्विक आयात पर असर होगा। भारत पहले ही आर्थिक वृद्धि में पिछले कई महीनों से गिरावट से जूझ रहा है। कोरोना के कारण वैश्विक बाजार में दबाव के बाद भारत की चिंता और बढ़ गई है। शेयर बाजार गिरने के साथ रुपया भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। देसी एवं विदेशी निवेशकों की धारणा पर बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारत का 70 फीसदी से ज्यादा फार्मा सामग्री, एक चौथाई कार के पुर्जे और बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री चीन से आती है। होली के समय बाजार में भारी मात्रा में चीन की सामग्री बेची जाती है। खिलौने से लेकर सजाने की वस्तुएं, चीनी सामानों की किसी भी त्योहार में भारी मांग होती है।

डॉ. महेश बंसिया
उज्जैन, मध्य प्रदेश

सकारात्मक असर

कोरोनावायरस का सबसे ज्यादा प्रभाव भारत के चार क्षेत्रों विनिर्माण, वाहन कलपुर्जा, इलेक्ट्रिकल और फार्मा पर पड़ा है। चीन वैश्विक स्तर विभिन्न जिंसों का सबसे बड़ा खरीदार है। लेकिन चीन की तरफ से मांग में कमी के कारण विश्व स्तर पर कच्चे तेल, सोयाबीन व पोर्क जैसे कई उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। आपूर्ति शृंखला प्रभावित होने से कई चीजों के लिए कच्चे माल की कमी हो सकती है तो कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। इस विपदा को अवसर के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। यदि हम घरेलू उत्पादन क्षेत्र जैसे विनिर्माण, वाहन कलपुर्जा, इलेक्ट्रिकल कलपुर्जा और फार्मा क्षेत्र को और अधिक उन्नत बनाते हैं तो इससे हमारी चीन पर निर्भरता तो कम होगी ही साथ ही साथ प्रतिकूल भुगतान संतुलन में भी सुधार आएगा।

... और यह है अगला मुद्दा

हर सोमवार को हम सम-सामयिक विषय पर व्यापार गोष्ठी नाम का विशेष पृष्ठ प्रकाशित करते हैं। इसमें आपके विचारों को प्रकाशित किया जाता है। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की राय।

इस बार का विषय है – **बैंकिंग में जमाकर्ताओं का भरोसा कैसे बढ़े?**

अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें: बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002

फैक्स नंबर- 011-3720201 या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in

राणा कपूर: किसी को नहीं कहा 'ना'

कमजोर अनुपालन, खराब संचालन और लालच के कारण हुई दुर्गति, उन लोगों को भी ऋण दिया जो चुकाने में समर्थ नहीं थे

सचिन मामबटा
मुंबई, 8 मार्च

प्रवर्तन निदेशालय ने राणा कपूर को रविवार को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया

चश्मा और आम कपड़े पहने राणा कपूर शनिवार को जब पूछताछ के लिए मुंबई के बलार्ड एस्टेट स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय पहुंचे तो वह उस दिग्गज बैंकर से एकदम अलग नजर आ रहे थे जिसने येस बैंक को देश के अग्रणी बैंकों की जमात में शामिल किया।

येस बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। कपूर उस वक्त रैबो इंडिया फाइनैंस से जुडे थे और उन्हें येस बैंक का प्रमुख नहीं बल्कि सह-प्रवर्तक निदेशक बनना था। बैंक ने अपना पहला प्रमुख खोजने की जिम्मेदारी एक्जीक्यूटिव सर्च फर्म कॉर्न फेरी को सौंपी। आखिरकार प्रवर्तक समूह के बीच हुई चर्चा में यह तय हुआ कि राणा कपूर को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी बनना चाहिए। एक अन्य सह-प्रवर्तक अशोक कपूर को चेयरमैन बनाने का फैसला हुआ। कपूर ने रैबो से इस्तीफा दे दिया और उसने भी भारत में अपने नए मुख्य कार्यकारी की तलाश शुरू कर दी। कपूर ने अमेरिका में पढ़ाई की थी और बैंक ऑफ अमेरिका तथा एएनजेड ग्रिंडलेज इनवेस्टमेंट बैंक सहित कई विदेशी बैंकों में काम किया था। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि उन्हें एक विदेशी बैंक में आरामदायक नौकरी छोड़कर एक नए बैंक में काम करने का फैसला क्यों किया? इसका उत्तर उन्होंने दो शब्दों में दिया, 'उद्यमशीलता का मजा।'

यही जुनून था कि जुलाई 2005 में जब मुंबई मूसलाधार बारिश से पानी-पानी हो गई थी तो वह अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे थे। बोर्ड बैठक से पहले उन्होंने सारा लंबित काम निपटाया। लेकिन बोर्ड की बैठक को टालना पड़ा क्योंकि शहर में मची अफरातफरी के कारण बोर्ड के दो सदस्य इसमें हिस्सा नहीं ले पाए। संयोग से उसी वक्त कंपनी सूचीबद्ध हुई थी।

बैंक की सूचीबद्धता शायद ही इससे बेहतर हो सकती थी। 50 शेयरों के लिए पहला कारोबार 65 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से हुआ। यह कीमत इश्यू की कीमत से 44 फीसदी अधिक थी। शेयर की कीमत में इसके बाद आई बढ़त के साथ बैंक नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी 50 सूचकांक में शामिल हो गया। इसके बाद उसे 30 शेयरों वाले बीएसई सेंसेक्स में भी जगह मिल गई। इन दो सूचकांकों में देश की जानी मानी कंपनियां शामिल हैं। सितंबर 2017 में बैंक का मूल्य 80,000 करोड़ रुपये से अधिक था।

बीच के वर्षों में बैंक ने दिन दोगुना रात चौगुना उन्नति की। उसे बैंकर के रूप में राणा कपूर की छवि का फायदा मिला जो आक्रामक तरीके से ऋण देना चाहते थे। जब दूसरे बैंकों को कुछ प्रवर्तकों से अपना पैसा लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, कपूर उनसे अपना पैसा लेने में सफल रहे। लेकिन उनकी यह तरकीब हमेशा काम नहीं आई। बैंक की इस प्रवृत्ति से बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक खुश नहीं था।

हाल ही में सरकार ने येस बैंक के बोर्ड को भंग करने और उस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी जिससे बीएसई में इसका बाजार पूंजीकरण 4,132 करोड़ रुपये रह गया। इसके बाद तो बैंक की शाखाओं पर पैसा निकालने के लिए जमाकर्ताओं की लाइन लग गई। उनसे कहा गया है कि बैंक के संकट का समाधान होने तक वे 50 हजार रुपये से अधिक रकम नहीं निकाल सकते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि बैंक ने ऐसे उद्योगपतियों को बहुत पैसा उधार दे दिया था जो इसे चुकाने की स्थिति में नहीं थे। बैंक के पास इस कर्ज को कवर करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी। ईडी ने रविवार सुबह कपूर को गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि कपूर परिवार ने उन कंपनियों से रिश्वत ली थी जिन्हें येस बैंक ने उधार दिया था।

आरबीआई के राणा कपूर को बर्खास्त करने के बाद रवनीत गिल को येस बैंक का नया मुख्य कार्याधिकारी बनाया गया था। डॉयचे बैंक से आए गिल पिछली कुछ तिमाहियों से अतिरिक्त फंडिंग के लिए हाथपांव मार रहे थे। कई निवेशकों के नाम हवा में तैर रहे थे लेकिन इनमें से किसी ने भी बैंक में निवेश नहीं किया। कपूर ने कर्ज देने में जो आक्रामकता दिखाई थी, उससे बैंक को भरोसा बनाने में मदद नहीं मिली।

लंबे समय तक बैंक की उधारी वृद्धि दोहरे अंकों में रहे। 2019 में ही इसकी रफ्तार में कुछ कमी आई। बैंक के उपलब्ध पिछली तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक उसकी उधारी में पिछले साल के मुकाबले 6.1 फीसदी की गिरावट आई।

इससे एक साल पहले से ही बैंक का तिमाही शुद्ध मुनाफा घटना शुरू हो गया था और सितंबर 2018 से हर तिमाही में उसे नुकसान हुआ है। सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का अनुपात यानी कुल उधारी की तुलना में फंसे कर्ज का प्रतिशत 1.6 फीसदी से बढ़कर सितंबर, 2019 तिमाही में 7.4 फीसदी पहुंच गया।

दिलचस्प है कि बैंक का कुल जमा भी पहली बार सितंबर, 2019 में घट गया। शायद जमाकर्ताओं को बैंक की स्थिति का अहसास हो गया था। बैंक ने दिसंबर, 2019 के तिमाही आंकड़ों की घोषणा में देरी की है जो अच्छा संकेत नहीं है।

बैंकों ने कपूर के गिरवी शेयर बेच दिए। नवंबर 2019 की एक खबर के मुताबिक कपूर के पास केवल 900 शेयर रह गए थे जिनकी कीमत 60 हजार रुपये थी। सितंबर 2018 में उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि वह कभी भी अपने शेयर नहीं बेचेंगे। उन्होंने अपने शेयरों की तुलना हीरे से करते हुए कहा कि वह उन्हें अगली पीढ़ी को सौंपेंगे। आखिरकार उन्हें प्रमुख और अहम शेयरधारक के रूप में बैंक से निकलना पड़ा।

अपनी इस यात्रा में येस बैंक कोई कई अन्य दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। इसमें दिवंगत सह-संस्थापक अशोक कपूर की पत्नी मधु कपूर के साथ बोर्ड में प्रतिनिधित्व को लेकर हुआ विवाद भी शामिल है। इस मामले ने बहुत तूल पकड़ा था। बंबई उच्च न्यायालय ने मधु कपूर के पक्ष में फैसला सुनाया था। दोनों प्रवर्तक परिवारों के बीच सुलह की अफवाहें थी लेकिन शेयरों की कीमत में इसका कोई संकेत नहीं दिखा। बैंक में जिस तरह से चीजें हो रही थीं, उससे आरबीआई खुश नहीं था और उसने राणा कपूर को अपना कार्यकाल आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी।

बैंक के शुरुआती विज्ञापनों में दिखाया गया था कि एक उद्यमी फंड की तलाश में हैं और बैंक उसे 'येस' कहता है। बैंक का संचालन शुरू होने से पहले बिज़नेस स्टैंडर्ड ने राणा कपूर से पूछा था कि उन्होंने बैंक का नाम येस बैंक क्यों रखा है। तब उन्होंने कहा था, 'यह सकारात्मक है और इसमें भरोसा तथा विश्वास की भावना है।' लेकिन निवेशकों और बैंक की शाखाओं के बाहर खड़े जमाकर्ताओं की भावना शायद कुछ अलग ही होगी।

आईपीओ आवेदन पर संशय बरकरार

समी मोडक
मुंबई, 8 मार्च

एसबीआई कार्ड्स ऐंड पेमेंट्स सर्विसेज के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में करीब 1,500 करोड़ रुपये के निवेश के लिए येस बैंक के ग्राहकों के आवेदनों का भाग्य अधर में लटकता दिख रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा येस बैंक को निगरानी में रखे जाने के बाद इस संकटग्रस्त बैंक के जरिये बोली जमा कराने वाले तमाम कॉरपोरेट एवं व्यक्तिगत निवेशकों के लिए अनिश्चितता बढ़ गई है कि आवंटन के लिए उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा अथवा नहीं। हालांकि निवेशकों के पास पर्याप्त रकम है जो उनके येस बैंक खाते में जमा है लेकिन येस बैंक को आरबीआई द्वारा निगरानी में रखे जाने से उनकी रकम फंस जाएगी। ऐसे में वे जारीकर्ता कंपनी को अपने खाते से रकम हस्तांतरित नहीं कर पाएंगे। देश की दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी एसबीआई कार्ड्स ऐंड पेमेंट्स सर्विसेज का आईपीओ गुरुवार को बंद हो गया और उसके कुछ ही घंटे बाद आरबीआई ने येस बैंक को एक महीने के लिए निगरानी में रखने का निर्देश दिया। इस आईपीओ के जरिये 10,300 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है।

सूत्रों का कहना है कि एसबीआई कार्ड्स के आईपीओ का संचालन करने वाले बैंकरों बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के सामने यह मुद्दा उठाया है। एक निवेश बैंकर ने कहा, 'जो कुछ भी घटित हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए हमने बाजार नियामक से पूछा है कि क्या आवंटन के लिए येस बैंक खातों से समर्थित आवेदनों पर विचार किया जाना चाहिए अथवा नहीं।'

इस मुद्दे के समाधान के लिए एसबीआई कार्ड्स का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों, आईपीओ की देखरेख करने वाले निवेश बैंकरों, सेबी और आबीआई की बैठक सोमवार को हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल दो विकल्प मौजूद हैं। पहला, इस आईपीओ के लिए आवेदन से संबंधित रकम हस्तांतरण के लिए आरबीआई मंजूरी दे क्योंकि येस बैंक को निगरानी में रखने की घोषणा से पहले तथाकथित एएसबीएस प्रक्रिया के तहत आईपीओ के लिए आवेदन रकम को पहले ही अलग किया जा चुका है। जबकि दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि आवंटन प्रक्रिया को सामान्य रखा जाए लेकिन आवंटन हासिल करने वाले येस बैंक के ग्राहकों को वैकल्पिक बैंक के जरिये भुगतान के लिए कहा जाए। बाजार के जानकारों का कहना है कि आरबीआई पहले विकल्प को संभवत: मंजूरी नहीं देगा और ऐसे में दूसरे विकल्प पर विचार किया जा सकता है। उनका कहना है कि दूसरा विकल्प कहीं अधिक व्यावहारिक दिखता है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे विकल्प से भी परिचालन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

खुदरा निवेश खरीदते रहे, संस्थागत निकल लिए

देव चटर्जी
मुंबई, 8 मार्च

- खुदरा निवेशक 50 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी के साथ बैंक में बने रहे
- संस्थागत निवेशकों की बैंक में हिस्सेदारी जून 2018 में 43 फीसदी थी, जो घटकर 18.24 फीसदी पर आ गई
- सार्वजनिक हिस्सेदारी 9.58 फीसदी से बढ़कर 53.24 फीसदी पर पहुंच गई
- स्थानीय संस्थानों की हिस्सेदारी जून 2018 में 25 फीसदी थी, जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में घटकर 14.21 फीसदी पर आ गई

येस बैंक के वित्तीय आंकड़े पिछले साल से ही दबाव के संकेत दे रहे थे। ऐसे में बैंक के बड़े संस्थागत शेयरधारकों और प्रवर्तकों ने अपने शेयरों की बिकवाली की, लेकिन खुदरा निवेशक 50 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी के साथ बैंक में बने रहे। बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा जुटाए गए आंकड़ों से इसका पता चलता है।

प्रवर्तक राणा कपूर के शेयर खुद उन्होंने ही बेचे या गिरवी शेयर ऋणदाताओं ने बेचे। एक अन्य प्रवर्तक गोगिया परिवार ने अपना निवेश बनाए रखा। पिछले साल नवंबर में कपूर ने 142 करोड़ रुपये के अपने बाकी शेयर बेच दिए थे और उनके पास केवल 900 शेयर थे। ऐसा कपूर के यह ट्वीट करने के कुछ सप्ताह के भीतर हुआ कि येस बैंक के शेयर हीरों की तरह हैं और वह अपने हीरों को कभी नहीं बेचेंगे। ऋणदाताओं के कपूर के गिरवी शेयरों को बेचने के बाद उनकी बैंक में शेयरधारिता कम हुई। संस्थागत निवेशकों की बैंक में हिस्सेदारी जून 2018 में 43 फीसदी थी, जो घटकर 18.24 फीसदी पर आ गई। वहीं सार्वजनिक हिस्सेदारी 9.58 फीसदी से बढ़कर 53.24 फीसदी पर पहुंच गई। स्थानीय संस्थानों की हिस्सेदारी जून 2018 में 25 फीसदी थी, जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में घटकर 14.21 फीसदी पर आ गई। एक विदेशी ब्रोकरेज के विश्लेषक ने कहा, 'अनाम स्रोतों से लगातार ये गलत खबरें आ रही थीं कि बड़े निवेशक येस बैंक के शेयर खरीदना चाहते है। इस वजह से खुदरा निवेशकों की इस शेयर में रुचि बनी रही।'

प्रॉक्सी एडवाइजरी कंपनी इनगवर्न के संस्थापक और सीईओ श्रीराम सुब्रमण्यम कहते हैं कि खुदरा निवेशकों ने कई चेतावनियों की अनदेखी की। रेटिंग कंपनियां बैंक की निवेश योजनाओं की रेटिंग घटा रही थीं। उन्होंने कहा, 'प्रवर्तक खुद अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकल रहा है, जिसे देखते हुए खुदरा निवेशकों को ज्यादा सतर्क होना चाहिए था।'

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) येस बैंक को बचाने आगे जरूर आ रहा है, लेकिन खुदरा खेयर निवेशकों को कोई खास लाभ नहीं मिलता दिख रहा है। एसबीआई ने यह कदम जमाकर्ताओं के हितों को ध्यान रखकर उठाया है। बैंक को नियंत्रण में लेने की आरबीआई की घोषणा के बाद जे पी मॉर्गन ने इसका शेयर मूल्य घटाकर 1 रुपये प्रति शेयर कर दिया। जे पी मॉर्गन ने कहा कि येस बैंक की खुद्ध परिसंपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है,इसलिए उसे लक्ष्य मूल्य घटाकर 1 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।

एटी-1 बॉन्ड पर संकट

पृष्ठ 1 का शेष...

फिक्स्ड इनकम विशेषज्ञों का कहना है कि ये बॉन्ड बैंकों के लिए फंड जुटाने का अहम जरिया रहे हैं, खासकर ऐसे बैंकों के लिए जो इक्विटी की कम कीमत के कारण इक्विटी बाजार से पैसे जुटाने में सक्षम नहीं हैं।

एक डेट फंड मैनेजर ने कहा, 'पहले ही अधिकांश सरकारी बैंकों के लिए इक्विटी पूंजी बाजार के रास्ते बंद हैं। इस तरह के कदम से उनके लिए डेट बाजार के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। यह पश्चगामी कदम है। पहली बार इक्विटी के बजाय एटी-1 बॉन्ड को बट्टे खाते में डाला जा रहा है। इक्विटी शेयरधारकों के पास पुनर्गठित बैंक में 51 फीसदी हिस्सेदारी होगी लेकिन एटी-1 बॉन्डधारकों को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इससे एटी-1 बाजार में फंड जुटाने की प्रक्रिया पर विराम लग जाएगा।' शिवकुमार ने कहा, 'यहां दो विरोधाभासी मामले हैं। कई ऐसे मामले हैं जहां नियम कहते हैं कि एटी-1 बॉन्ड को इक्विटी पर तरजीह दी जाएगी जबकि इस मामले में बॉन्ड के बजाय इक्विटी को तवज्जो दी जा रही है।' आरबीआई के मास्टर परिपत्र में उल्लेखित बेसल-तीन कैपिटल रेग्युलेशंस के मुताबिक एटी-1 बॉन्ड इक्विटी से बेहतर हैं। लेकिन इस तरह के बॉन्ड से जुडे जानकारी ज्ञापनों में कहा गया है कि अगर बैंक के वित्तीय संकट में आने की स्थिति में बॉन्ड को बट्टे खाते में डाला जा सकता है या इन्हें इक्विटी में बदला जा सकता है। बाजार सूत्रों के मुताबिक बैंक एटी-1 बॉन्ड के जरिये पूंजी जुटाने की योजना पर पुनर्विचार कर रहे हैं और अगर बाजार में इस तरह की आशंकाएं बरकरार रहती हैं तो वे अपी योजना को टाल भी सकते हैं।

कपूर ने ली 4,300 करोड़ रु. रिश्वत : ईडी

पृष्ठ 1 का शेष...

ईडी ने अदालत में कहा, 'कपूर को वित्तीय अनिश्मितताओं और निजी बैंक के परिचालन में कुप्रबंधन तथा निजी हित के लिए कई कंपनियों को संदिग्ध ऋण आवंटित करने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है।'

बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि कपूर को ईडी द्वारा लक्षित किया जा रहा है जबकि वह जांच एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी डीएचएफएल के साथ उनके संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रही है क्योंकि वह इसके प्रवर्तकों के साथ सामाजिक तौर पर करीब से जुड़े हुए हैं। दिलचस्प है कि कपूर की बेटी रोशनी कपूर रविवार को देश छोड़कर जाने का प्रयास कर रही थी लेकिन आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें वापस भेज दिया क्योंकि उनके और कपूर परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ ईडी ने लुक आउट नोटिस जारी किया हुआ है। सूत्रों ने कहा कि येस बैंक के मामले को सीबीआई के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा देखा जा रहा है।

भाजपा, कांग्रेस ने एक-दूसरे पर लगाए आरोप-प्रत्यारोप

एजेंसियां
नई दिल्ली, 8 मार्च

- सत्तारूढ़ पार्टी ने इस मामले का ताल्लुक गांधी परिवार से बताया
- विपक्षी दल ने कहा कि बैंक के ऋणों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है
- कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री पर उठाया सवाल

येस बैंक संकट को लेकर रविवार को भाजपा और कांग्रेस ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए। सत्तारूढ़ पार्टी ने इस मामले का ताल्लुक गांधी परिवार से बताया। वहीं विपक्षी दल ने कहा कि बैंक के ऋणों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, जिससे सवाल पैदा होता है कि क्या प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की भी इसमें संलिप्तता थी।

भाजपा की सूचना एवं तकनीकी इकाई के प्रभारी अमित मालवीय ने एक समाचार चैनल की रिपोर्ट की एक क्लिप ट्विटर पर पोस्ट की। इस क्लिप में दिखाया गया है कि येस बैंक के गिरफ्तार संस्थापक राणा कपूर ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से एक पेंटिंग खरीदी थी। मालवीय ने आरोप लगाया कि भारत में हर वित्तीय अपराध के गांधी परिवार के साथ गहरे तार जुड़े हुए हैं।

कांग्रेस ने इस आरोप को 'झूठा' बताया है। पार्टी ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पिता की मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग कपूर को दो करोड़ रुपये में बेची थी और यह पूरी राशि उन्होंने 2010 में अपने आयकर रिटर्न में दिखाई थी।

मालवीय ने ट्वीट किया, 'भारत में हर वित्तीय अपराध का गांधी परिवार से गहरा नाता है। माल्या सोनिया गांधी को फ्लाइट अपग्रेडेड टिकट भेजता था। उसका एमएमएस (मनमोहन सिंह) और पीसी (पी चिदंबरम) से संपर्क था। अब वह भगोड़ा है। राहुल ने नीरव मोदी के ब्राइडल ज्वैलरी क्लेक्शन का उद्घाटन किया था, उसने डिफॉल्ट किया। राणा ने प्रियंका वाड्रा की पेंटिंग खरीदी।'

इन आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह सरकार की मुद्दे से ध्यान भटकाने की तिकड़म है। उन्होंने कहा कि जिस साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस साल (मार्च 2014) में बैंक की लोन बुक 55,633 करोड़ रुपये थी, जो मार्च 2019 में बढ़कर 2,41,499 करोड़ रुपये हो गई।

निवेशकों को दूर रहने की सलाह

श्रीपाद ऑटे
मुंबई, 8 मार्च

- येस बैंक के शेयर की कीमत में भारी गिरावट के बावजूद इक्विटी निवेशकों के लिए कुछ भी नहीं बदलने के आसार हैं
- येस बैंक के शेयर में गिरावट के बावजूद विशेषज्ञ निवेशकों को तेजी में बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को येस बैंक के लिए पुनर्गठन योजना का खाका पेश किया था। इससे भले ही जमाकर्ताओं को राहत मिली हो, लेकिन गुरुवार को निकासी की सीमा तय किए जाने से ग्राहकों में चिंता पैदा हो गई थी।

येस बैंक के शेयर की कीमत में भारी गिरावट के बावजूद इक्विटी निवेशकों के लिए कुछ भी नहीं बदलने के आसार हैं। येस बैंक का शेयर गुरुवार को 56 फीसदी गिरकर 16.2 रुपये पर बंद हुआ, जो एक समय 5.55 रुपये तक गिर गया था। इस गिरावट के बावजूद विशेषज्ञ निवेशकों को तेजी में बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं।

आईसीआईसीआई डायरेक्ट में विश्लेषक काजल गांधी के मुताबिक, 'अभी यह साफ नहीं है कि येस बैंक में कितनी नई पूंजी की दरकार है, लेकिन प्रस्तावित धनराशि जुटाने के बावजूद बैंक के लिए नया कारोबार हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। हमें येस बैंक की बैलेंस शीट में बढ़ोतरी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं।'

आईसीआईसीआई डायरेक्ट के विश्लेषकों ने कहा कि येस बैंक में 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने वाले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के शेयर की भी रेटिंग निकट भविष्य में कम हो सकती है क्योंकि येस बैंक का मुश्किल दौर से गुजर रहे क्षेत्रों में कर्ज फंस हुआ है। इस ब्रोकरेज का मानना है कि इससे छोटे शेयरधारकों को नुकसान है और यह उन्हें निकासी की सलाह दे रही है।

एक अन्य घरेलू ब्रोकरेज कंपनी के विश्लेषक ने भी ऐसे ही विचार जाहिर किए। उन्होंने कहा, 'पुनर्गठन के बाद भी येस बैंक की हालत में सुधार बहुत मुश्किल है। हमें नहीं लगता कि यह बैंक कम से कम मध्यम अवधि में अच्छा प्रदर्शन करेगा।' पुनर्गठन की अंतिम योजना तैयार होने के बाद भी बैंक को पटरी पर लाने और उसकी बैलेंस शीट को साफ-सुथरा बनाने में एक या दो साल लगेंगे। येस बैंक की ताजा उपलब्ध रिपोर्ट दर्शाती हैं कि उसके 31,400 करोड़ रुपये के ऋणों की रेटिंग बीबी या उससे नीचे है, जो आम तौर पर डिफॉल्ट के अधिक जोखिम को दर्शाता है।

ये संभावित जोखिम वाले ऋण सितंबर 2019 में बैंक के नेट वर्थ का 1.7 गुना थे। हालांकि बैंक के लिए सबसे बड़ी समस्या अपने कारोबार के लिए पर्याप्त जमाएं हासिल करना है। विश्लेषकों का मानना है कि हाल के घटनाक्रम के बाद बैंक को अच्छी मात्रा में जमाएं नहीं मिलने के आसार हैं क्योंकि यह ग्राहकों का भरोसा खो चुका है। इसके अलावा पुनर्गठन योजना मुख्य रूप से मौजूदा जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है।

येस बैंक की मौजूदा शेयर पूंजी में भारी कमी आएगी। योजना के मुताबिक बैंक की अधिकृत पूंजी बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये हो जाएगी, जिसमें प्रत्येक 2 रुपये के 2,400 करोड़ शेयर होंगे। इसकी तुलना में दिसंबर 2019 में 255 करोड़ शेयर थे।

रिलायंस सिक्योरिटीज की विश्लेषक मोना खेतान का मानना है कि मौजूदा शेयरधारकों की इक्विटी में करीब 90 फीसदी आएगी। हालांकि अतिरिक्त टियर-1 बॉन्डों पूरी तरह बट्टे खाते में डाल दिए गए हैं।

उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ समय से बीएफएसआई शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट आई है, इसलिए निवेशकों के पास येस बैंक में बने रहने के बजाय अच्छे फंडामेंटल वाले बेहतर शेयरों में निवेश करने का मौका है।'

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम निकालेगा 38 करोड़ रुपये

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 8 मार्च

येस बैंक संकट के उजागर होने के मद्देनजर उत्तर प्रदेश पथ परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने निजी क्षेत्र के इस बैंक में करीब 38 करोड़ रुपये की अपनी सावधि जमा को निकालने की प्रक्रिया शुरू की है। इस संदर्भ में निगम ने लखनऊ में येस बैंक की स्थानीय शाखा के प्रबंधक को एक आधिकारिक पत्र लिखा है।

उत्तर प्रदेश पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक राज शेखर ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि निगम ने ब्याज के साथ अपनी सावधि जमा को भुनाने के लिए येस बैंक की स्थानीय शाखा के प्रबंधक को पत्र लिखा है। वास्तव में पिछले दो वर्षों के दौरान येस बैंक में यूपीएसआरटीसी द्वारा निवेशित कुल रकम करीब 423 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। लेकिन करीब तीन महीने पहले निगम ने 385 करोड़ रुपये निकालकर अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश किया था।

शेखर ने कहा, 'हमने येस बैंक में अपनी सावधि जमा को पहले ही सुरक्षित कर रखा है और उसमें परिपक्वता से पहले निकासी का प्रावधान है। हालांकि 38 करोड़ रुपये की सावधि जमा अभी भी येस बैंक के पास है क्योंकि उसके लिए परिपक्वता पूर्व निकासी का प्रावधान नहीं है।' हालांकि शेखर ने कहा कि निगम ने येस बैंक ने इस रकम को भी सुरक्षित कराने के लिए संबंधित स्थानीय शाखा से संपर्क किया था। यूपीएसआरटीसी के अधिकारियों ने कथित तौर पर निजी ब्रोकरेज अथवा लोगों के साथ मिलकर येस बैंक में यह निवेश कराया था। परिपक्वता पूर्व निकासी का प्रावधान न होने के संदर्भ में उन अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा सकती है।

इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने येस बैंक को पहले ही एक महीने के लिए निगरानी में रख दिया है और जमाकर्ताओं के लिए मासिक निकासी की सीमा 50,000 रुपये प्रति खाता निर्धारित की है। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कहा है कि वह इस संकटग्रस्त बैंक में 49 फीसदी तक हिस्सेदारी खरीद सकता है। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने शनिवार को मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा था कि येस बैंक में 49 फीसदी तक हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को एसबीआई के बोर्ड से हरी झंडी मिल चुकी थी।

घटते भरोसे से निजी बैंकों के लिए कठिन राह

ज्यादातर निजी बैंकों के शेयर इस साल अब तक 10-33 प्रतिशत गिरे हैं जिससे इस क्षेत्र में कमजोर धारणा का संकेत मिलता है

हंसिनी कार्तिक

निजी बैंकों के शेयर शायद इसका उदाहरण हैं कि किस तरह से मजबूत और दृढ़ विश्वास भी संक्षिप्त अवधि में नकारात्मक परिदृश्य में बदल सकता है। आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, ऐक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, और आईसीआईसीआई बैंक जैसे सभी आकार के शेयर कुछ समय पहले तक सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाले शेयरों में शुमार थे। लेकिन एयू स्मॉल फाइनैंस बैंक एयू (एसएफबी) को छोड़कर इन शेयरों में इस साल अब तक 10-33 प्रतिशत के बीच गिरावट देखी गई है, जबकि समान अवधि के दौरान सेंसेक्स में 8.9 प्रतिशत की गिरावट आई है।

शायद एक दशक में यह पहली बार देखा जा रहा है कि निजी बैंकों को उनकी ताकत के स्तंभों - वृद्धि एवं निवेशक विश्वास के संदर्भ में चुनौती मिल रही है। येस बैंक की विफलता के साथ, निवेशकों के एक तबके का मानना है कि यह समय इन शेयरों से कुछ रकम निकालने का है। एक प्रमुख फंड प्रबंधक का कहना है कि जब भारत का चौथा सबसे बड़ा निजी बैंक विफल साबित होसकता है तो इससे निवेशक अपने पोर्टफोलियो पर पुनर्विचार करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। उन्होंने कहा, 'हम में से ज्यादातर (फंड प्रबंधक) चार वर्षों के दौरान निजी बैंकों में खरीदारी को लेकर उत्साहित रहे हैं और अब जब भी मौका मिलेगा हम इनमें मुनाफावसूली करेंगे।' कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज

में विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि तीन वित्तीय संस्थानों की विफलता (आईएलऐंडएफएस, पीएमसी बैंक और येस बैंक) से कंपनियों को पूंजी जुटाना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा।

नोमुरा में मुख्य अर्थशास्त्री सोनल वर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा, 'येस बैंक की विफलता से निजी निजी क्षेत्र के छोटे बैंकों से जमाएं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर आकर्षित हो सकती हैं।' वह कहती हैं कि इससे अपनी ऋण बुक बढ़ाने में निजी क्षेत्र के बैंकों की क्षमता प्रभावित होगी। दिसंबर तिमाही में 5.5-5.8 प्रतिशत (कोष की कुल लागत 6.2-6.5 प्रतिशत) की जमा लागत के साथ कोष के सस्ते स्रोत के साथ निजी बैंकों को यह पूंजी बनाए रखने के लिए कुछ दबाव का सामना करना पड़ सकता है। एक विश्लेषक ने कहा, 'इसकी संभावना है कि खुदरा ग्राहकों को बनाए रखने के लिए कुछ बैंक अपनी जमा दरों में कुछ इजाफा करते हैं।' इस सबसे वृद्धि की मौजूदा समस्याओं में इजाफा ही होगा।

बैंकों को भारत की जीडीपी वृद्धि पर दांव के तौर पर देखा जाता है, जिसमें पिछली तीन तिमाहियों के दौरान बड़ी कमी देखी गई है। जहां ऐक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक खासकर खुदरा के संदर्भ में अपनी पिछली वृद्धि दर 15-18 प्रतिशत पर बनाए रखने में सफल रहे, वहीं इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे अन्य बैंक अपनी 25 प्रतिशत से अधिक की ऐतिहासिक दर (खासकर, खुदरा के मोर्चे पर) में बड़े अंतर से विफल रहे। आरबीएल बैंक भी दिसंबर तिमाही में अपने 35-40 प्रतिशत के आंकड़े से दूर बना हुआ है। एसएमसी कैपिटल के सिद्धार्थ पुरोहित का कहना है, 'वृद्धि की रफ्तार में और नरमी आ सकती है, क्योंकि बैंकों के लिए अब ज्यादा जोखिम वाली स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, खुदरा ऋण आधारित वृद्धि हमेशा बरकरार नहीं रह सकती।'

वर्मा का मानना है कि दूरसंचार क्षेत्र और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से दबाव (रियल एस्टेट और छोटे व्यवसाय ऋणों से संबंधित एनपीए) से बैंकिंग क्षेत्र की परिसंपत्ति गुणवत्ता पर चिंता बनी हुई है। वह कहती हैं, 'हम व्यवस्थित परिसंपत्ति गुणवत्ता पर विपरीत परिस्थितियां देख रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में सकल एनपीए बढ़ने की आशंका है, क्योंकि वृद्धि से संबंधित मंदी की वजह से ऋण जोखिम से बचना मुश्किल हो गया है।' इसके अलावा, वैश्विक रूप से और भारत में कोविड-19 के तेजी से फैल रहे प्रभाव से विश्लेषक जून तिमाही के लिए जीडीपी लक्ष्य घटाने को बाध्य हुए हैं। नोमुरा ने अपना अनुमान 4.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है। निवेशकों के लिए, ये स्पष्ट रूप से उम्मीदें कम करने के संकेत हैं। भले ही एचडीएफसी बैंक, ऐक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे अच्छी गुणवत्ता वाले शेयरों में गिरावट आई है, लेकिन इनमें ताजा निवेश से पहले मार्च तिमाही के वित्तीय परिणामों का इंतजार करना फायदेमंद साबित होगा।

गिरावट पर एक नजर

	कीमत रु. में	बदलाव (%) 1-दिन	वर्ष में अब तक
येस बैंक	16.2	-56.0	-65.5
आरबीएल बैंक	259.1	-14.1	-24.9
उज्जीवन एसएफबी	44.4	-11.0	-17.6
आईडीबीआई बैंक	27.2	-9.2	-26.6
इंडसइंड बैंक	1,014.3	-5.6	32.9
सीएसबी बैंक	161.5	-5.2	-25.5
बंधन बैंक	403.9	-4.6	-20.5
आईसीआईसीआई बैंक	486.3	-3.7	-9.7
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक	36.3	-3.6	-19.6
ऐक्सिस बैंक	657.9	-2.9	-12.7
एचडीएफसी बैंक	1,134.9	-1.5	-10.8

चुने गए इन प्रमुख निजी बैंका का आंकड़ा 6 मार्च 2020 का है, स्रोतः एक्सचेंज
आंकड़ेः बीएस रिसर्च ब्यूरो द्वारा एकत्रित

बाजार हलचल

एसबीआई काड्र्स आईपीओ का गणित

एसबीआई काड्र्स ऐंड पेमेंट सर्विसेज के 10,300 करोड़ रुपये का आईपीओ सेकंडरी बाजार में बिकवाली के बावजूद 2 लाख करोड़ रुपये के आवेदन आकर्षित करने में सफल रहा। क्रेडिट कार्ड कंपनी ने इस निर्गम के लिए 755 रुपये की कीमत तय की। अमीर निवेशकों (एचएनआई) के लिए, खरीद लागत ब्याज खर्च को देखते हुए 870 रुपये रही है। एचएनआई इस निर्गम से कमाई कर सकें जिसे देखते हुए सूचीबद्धता के दिन, शेयर में निर्गम कीमत की तुलना में कम से कम 15 प्रतिशत की तेजी जरूरी होगी। पिछले सप्ताह बाजार में आई गिरावट के बाद ग्रे बाजार में इस शेयर की तेजी घटकर 10 प्रतिशत रह गई है। इस बीच, आईपीओ को लगभग 31 लाख खुदरा आवेदन मिले हैं। आवेदनों की संख्या के आधार पर, निर्गम को 1.37 गुना का अभिदान मिला। *- समी मोडक*

येस बैंक के लिए ईटीएफ गतिरोध

येस बैंक के शेयर को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) से लगातार बिकवाली दबाव का सामना करना पड़ सकता है। यह शेयर 27 मार्च तक निफ्टी सूचकांक का हिस्सा रहेगा और उसके बाद इसकी जगह श्री सीमेंट को शामिल किया जाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि इस बदलाव से शेयर पर बिकवाली दबाव बढ़ेगा। येस बैंक का शेयर बैंक निफ्टी और कुछ मिड-कैप सूचकांकों का हिस्सा बना रहेगा। वैल्यू रिसर्च से प्राप्त आंकड़े के अनुसार, ईटीएफ और इंडेक्स फंडों ने निजी क्षेत्र के इस बैंक में निवेश कर रखा है। एक डीलर ने कहा, 'पैसिव फंडों से बिकवाली से शेयर कीमत पर दबाव पड़ेगा, भले ही इसे सरकार या आरबीआई से संभावित राहत मिली हो।' *- जश कृपलानी*

एयरलाइन शेयरों के लिए कच्चे तेल से राहत

घरेलू विमानन शेयरों स्पाइसजेट और इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में गिरावट आई है। पिछले सप्ताह इन दोनों शेयरों ने एक साल में अपना सबसे निचला स्तर छुआ। स्पाइसजेट का शेयर अपनी 52 सप्ताह की ऊंचाई से 60 प्रतिशत गिर गया है, जबकि इंटरग्लोब में 37 प्रतिशत तक की कमी आई है। इस गिरावट के बाद, कुछ निवेशक यह मान रहे हैं कि ये दोनों शेयर वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट को देखते हुए खरीदारी का अच्छा अवसर हैं। कच्चे तेल की कीमत घटकर 50 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई है। एक फंड प्रबंधक ने कहा, 'जहां विमानन क्षेत्र कोरोनावायरस से प्रभावित हुआ है, वहीं तेल कीमतों में गिरावट सकारात्मक है। स्पाइसजेट और इंटरग्लोब काफी हद तक घरेलू बाजार पर केंद्रित हैं। हमारा मानना है कि यदि कोरोनावायरस से जुड़ी चिंताएं घटती हैं तो तेल कीमतें अनुकूल बदलाव साबित होंगी।' *- सुंदर सेतुरामन*

बाजार पूंजीकरण-जीडीपी अनुपात दीर्घावधि औसत से नीचे

ऐश्ली कुटिन्हो

मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज की एक रिपोर्ट के अनुसार बाजार के मूल्यांकन में उतार-चढ़ाव के निर्धारण में इस्तेमाल होने वाला भारत का बाजार पूंजीकरण-जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 2020 के जीडीपी अनुमानों के आधार पर 70 प्रतिशत है और अपने 76 प्रतिशत के दीर्घावधि औसत से नीचे है।

पिछले चार वर्षों में यह अनुपात सबसे कम है। वित्त वर्ष 2010 में 95 के साथ यह अनुपात सर्वाधिक था।

भारतीय इक्विटी का मूल्यांकन अब उनके दीर्घावधि औसत से नीचे है। ब्रोकरेज फर्म के अनुसार निफ्टी 12 महीने के 16.8 गुना के पी/ई मल्टीपल पर अपने 18.1 गुना के दीर्घावधि औसत के मुकाबले 7 प्रतिशत गिरावट पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी का प्राइस-टु-बुक (पी/बी) अनुपात 2.5 गुना पर है, जो उसके 2.6 गुना के ऐतिहासिक औसत से नीचे है। हालांकि भारत का मूल्यांकन उभरते बाजार (ईएम) प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले लगातार ऊंचा बना हुआ है। एमएससीआई इंडिया का पी/ई कारोबार एमएससीआई ईएम के पी/ई के मुकाबले 62 प्रतिशत की तेजी पर कारोबार कर रहा है, जो 52 प्रतिशत की उसकी ऐतिहासिक औसत तेजी से ज्यादा है। पिछले 12 महीनों के दौरान एमएससीआई इंडिया सपाट बना रहा, जबकि एमएससीआई ईएम 1.5 प्रतिशत फिसला। इस अवधि में दुनिया का बाजार पूंजीकरण 3.3 प्रतिशत बढ़कर 2.5 लाख करोड़ डॉलर हो गया, जबकि भारत का बाजार पूंजीकरण 2.5 प्रतिशत के साथ सपाट रहा।

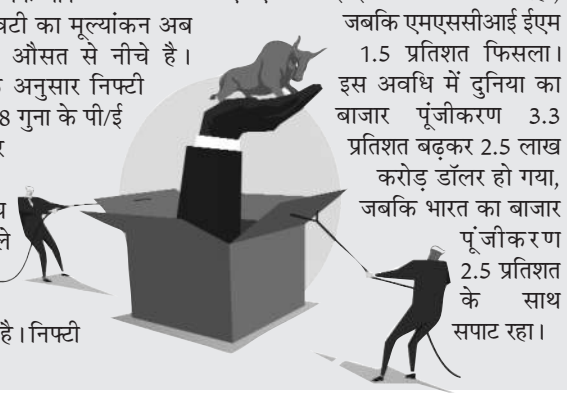

बाजार में 9 साल में सबसे खराब शुरुआत

सुंदर सेतुरामन

इक्विटी बाजार में वर्ष 2011 के बाद से सबसे खराब वर्ष की शुरुआत हुई है। इस साल अब तक निफ्टी 9.7 प्रतिशत गिर चुका है। पिछली बार 2011 में इस सूचकांक में इतनी बड़ी गिरावट आई थी, जब यूरोपीय ऋण संकट से वैश्विक निवेशक धारणा प्रभावित हुई थी। शुक्रवार को 50 शेयर वाला सूचकांक 10,989 पर बंद हुआ। यह सूचकांक 17 जनवरी के 12,352 की रिकॉर्ड ऊंचाई से 11 प्रतिशत नीचे आ गया है। तकनीकी विश्लेषकों का कहना है कि बाजार में और गिरावट के आसार हैं।

पिछली बार 2011 में शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आई थी

मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज के रिटेल शोध प्रमुख सिद्धार्थ खेमका कहते हैं, 'निफ्टी ने साप्ताहिक चार्ट पर मंदी का संकेत दिया है। सूचकांक के लिए प्रतिरोध स्तर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब 11,250-11,430 का स्तर इस सूचकांक के लिए तेजी की स्थिति में बाधा होगा। इसके लिए 11,800-11,650 पर समर्थन हासिल है। जब तक उतार-चढ़ाव शांत नहीं हो जाता, और कीमतें स्थिर नहीं होतीं, तब तक हम आंकड़ों में मजबूत सुधार के संकेत नहीं देखेंगे, कारोबारियों को फिलहाल गिरावट पर खरीदारी से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है।'

बाजार कारोबारियों का कहना है कि घरेलू निवेशक दोहरी समस्या (येस बैंक संकट और कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों) से प्रभावित हुए हैं। कारोबारियों का कहना है कि ये दो घटनाक्रम बाजार की दिशा तय करेंगे।

कोटक सिक्योरिटीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (इक्विटी तकनीकी रिसर्च) श्रीकांत चौहान ने कहा, 'कोरोनावायरस के मामलों पर स्पष्ट जानकारी अगले कुछ कारोबारी सत्रों के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा, येस बैंक की समाधान योजना भी घरेलू मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। अल्पावधि रुझान कमजोर है और 10,900 निफ्टी के लिए प्रमुख समर्थन के तौर पर काम कर सकता है। इसके ऊपर कारोबार के साथ हम इसके बढ़कर 11,200-12,250 पर पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि 10,900 से नीचे जाने की स्थिति में इसमें और गिरावट आ सकती है और यह 10,800-10,750 तक आ सकता है।'

शुक्रवार को निफ्टी दिन के कारोबार में गिरकर 10,827 अंक पर आ गया था और इसमें उस स्तर से कुछ सुधार आया और आखिर में यह 11,000 से नीचे बंद हुआ।

आईसीआईसीआई डायरेक्ट के विश्लेषकों का मानना है कि बाजार मौजूदा सतरों पर आधार तैयार कर सकता है। ब्रोकरेज का कहना है, 'बाजार एक छोटे सप्ताह में प्रवेश कर रहा है और यदि निफ्टी 11,000 से ऊपर बना रहा तो मामूली उतार-चढ़ाव के दायरे में बना रह सकता है। हालांकि कोरोनावायरस को लेकर आशंका बनी हुई है और किसी बड़े शॉर्ट कवरिंग रुझान के सफल होने के आसार नहीं हैं।'

अजय मोहंती

कोरोना के कहर से शेयरों में निवेश कम

कोरोनावायरस के कारण शेयर बाजार में उथलपुथल जारी रह सकती है

जयदीप घोष और संजय कुमार

- **फरवरी के अंतिम शुक्रवार को सेंसेक्स 1,448 अंक फिसल गया जिससे साफ है कि शेयर बाजार में उथलपुथल जारी रह सकती है**
- **इससे पिछले सप्ताह सेंसेक्स में 7 प्रतिशत गिरावट आई, जिससे निवेशकों को 12 लाख करोड़ रुपये की चपत लगी**
- **चीन का मैन्युफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स फरवरी में कम होकर 35.7 रह गया, जो जनवरी में 50 था**
- **2008 के बाद इस सूचकांक में आई यह सबसे बड़ी गिरावट रही और गैर-विनिर्माण पीएमआई भी कम होकर 29.6 प्रतिशत रह गया**

घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से भारी बिकवाली के बावजूद फरवरी के अंतिम शुक्रवार को सेंसेक्स 1,448 अंक फिसल गया। इससे इतना तो साफ है कि आगे कुछ और समय तक शेयर बाजार में उथलपुथल जारी रह सकती है। सोमवार 2 मार्च को बाजार कुछ अंतराल के बाद खुला क्योंकि शुक्रवार को कारोबार बंद होने से पहले निवेशकों ने आक्रामक बिकवाली की थी।

निवेशकों को यह बिल्कुल मान कर नहीं चलना चाहिए कि बुरा दौर खत्म हो चुका है। निवेश सलाहकार अर्जुन केजरीवाल का कहना है कि पस्थितियां सुधरने में थोड़ा और समय लग सकता है। पिछले सप्ताह बीएसई के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में 7 प्रतिशत गिरावट आई, जिससे निवेशकों को सीधे 12 लाख करोड़ रुपये की चपत लग गई। पहले ऐसा माना जा रहा था कि कोरोनावायरस का संक्रमण चीन तक ही सिमट कर रह जाएगा। एडलवाइस म्युचुअल फंड की मुख्य कार्याधिकारी राधिका गुप्ता ने कहा, 'कोरोनावायरस के चीन के बाद दुनिया के दूसरे देशों में फैलने से निवेशकों का उत्साह ठंडा पड़ गया है।' खबरों के अनुसार अब तक कम से कम 70 देशों में इस खतरनाकम वायरस से लोग प्रभावित हो चुके हैं। वैलिडस वेल्थ ने अपनी एक टिप्पणी में कहा कि अच्छी बात यह है कि यह महामारी नियंत्रण में लाई जा सकती है। अगर वायरस छह महीने बाद या इससे अधिक समय में नियंत्रण में आता है तो इससे विकसित बाजारों में उपभोक्ताओं एवं कंपनियों के व्यवहार में काफी बदलाव आ सकता है। ऐक्सिस म्युचुअल फंड में इक्विटी प्रमुख जिनेश गोपानी कहते हैं, 'दरअसल इस बात का डर है कि अगर संक्रमण पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो इस कैलेंडर वर्ष के पहले छह महीने में दुनिया की आर्थिक वृद्धि दर को तगड़ा झटका लग सकता है।'

शनिवार को चीन का मैन्युफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) फरवरी में कम होकर 35.7 रह गया, जो जनवरी में 50 रहा था। 2008 के बाद इस सूचकांक में आई यह सबसे बड़ी गिरावट रही। गैर-विनिर्माण पीएमआई भी कम होकर 29.6 प्रतिशत रह गया।

कोरोनावायरस का असर

मौजूदा स्थिति में निवेशक सीमित मात्रा में कर सकते हैं। अगर दुनिया भर के बाजारों में बिकवाली की बयार बही तो भारतीय बाजारों पर भी असर पड़ेगा। विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) तेजी से उभरते बाजारों से रकम निकालकर उन्हें सुरक्षित समझे जाने वाली परिसंपत्तियों में लगा रहे हैं, इसलिए भारतीय बाजार पर भी इसका असर होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। जमीनी हकीकत यह है कि कई भारतीय कंपनियां चीन से कच्चे माल एवं अर्द्ध-निर्मित वस्तुओं का चीन से आयात करती हैं। अगर इनका आयात बाधित हुआ तो इन कंपनियों की कमाई प्रभावित हो सकती है। गोपानी कहते हैं,'अगर चीन में आर्थिक गतिविधियां लंबे समय तक अस्थिर रहीं तो ऐसी कंपनियों की कमाई कम हो सकती है, जो चीन से आयात पर निर्भर हैं।' चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कमाई सुधरने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।

कुछ और कहें आंकड़े

हालांकि यह उथल-पुथल अधिक समय तक जारी नहीं रह सकती है। आंकड़े दिखाते हैं कि ऐसी मुश्किलों का भारत के शेयर बाजार पर लंबे समय तक असर नहीं पड़ा है। उदाहरण के लिए एच1एन1 का संक्रमण फैलने से पहले महीने में सेंसेक्स 13 प्रतिशत तक नीचे चला गया था, लेकिन अगले कुछ महीनों में यह दोबारा अपनी जगह लौटा आया। दूसरे मामलों में बाजार उतना ऊपर नहीं गया। केजरीवाल कहते हैं, 'बाजार में और गिरावट दिख सकती है, लेकिन ज्यादातर नकारात्मक बातों का असर हो चुका है।' यह भी सच है कि भारतीय बाजार इस समय घरेलू आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहा है।

इन क्षेत्रों पर असर

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां एयर कंडीशनर के लिए कंप्रेशर जैसे कल-पुर्जे का चीन से आयात करती हैं। फिलहाल उनके पास पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन अगर अगले 10-15 दिनों में आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, रसायन और फार्मा उद्योग भी चीन से कच्चे माल एवं कल-पुर्जों का आयात करते हैं। कोरोनावायरस पर जल्द ही नियंत्रण नहीं पाया गया तो इन सभी क्षेत्रों पर असर हो सकता है। पर्यटन उद्योग भी मौजूदा संकट से बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

अवसर पर भी रहें सतर्क

इसमें कोई शक नहीं कि निवेश के कई अवसर सामने आएंगे। हालांकि, जल्दबाजी दिखाने से बचें क्योंकि बाजार कभी भी गिरावट का शिकार हो सकता है। केजरीवाल का कहना है कि निवेशक सीमित मात्रा में अच्छे शेयरों की खरीदारी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हड़बड़ी में और तत्काल निर्णय लेने से बचना चाहिए। गुप्ता कहते हैं,'पिछली घटनाओं- जैसे सार्स- के प्रभाव के अध्ययन से पता चला है कि इन बातों से बाजार में तेज गिरावट आती है। हालांकि चिंताएं धीरे-धीरे दूर होने के साथ ही बाजार वापस पटरी पर आने लगता है। दीर्घ अवधि के निवेशकों को अक्सर ऐसे उतार-चढ़ावों से रूबरू होना पड़ता है।

ऐसी बातें खरीदारी का अवसर भी देती हैं, जिनका लाभ समझदार निवेशक आसानी से उठा सकते हैं। इक्विरियस वेल्थ मैनेजमेंट के मुख्य कार्याधिकारी अंकुर माहेश्वरी ने कहा,'कई निवेशकों ने पूरी तरह सोच-विचार कर उन शेयरों की फेहरिस्त तैयार की होगी, जो उन्हें आकर्षित कर रहे होंगे। अगर मौजूदा गिरावट के बीच इन शेयरों की कीमतें उनके हिसाब से फिट बैठती हैं तो उन्हें इन्हें तुरंत झटक लेना चाहिए।' विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हालात में निवेशकों को अपनी अधिशेष रकम चरणबद्ध तरीके से निवेश करना चाहिए। एक ही बार में सारी रकम निवेश करने से बचें क्योंकि अचानक आई गिरावट में यह दांव महंगा साबित हो सकता है। हालांकि बाजार की चाल मापने में मूकदर्शक बन कर भी न रह जाएं। अगर बाजार अचानक वापसी करता है तो आप खरीदारी के अच्छे अवसरों से हाथ धो बैठेंगे। इसके साथ ही तुरंत मुनाफा अर्जित करने की भी उम्मीद नहीं पालें। गोपानी कहते हैं,'अगर चरणबद्ध तरीके से तीन से पांच वर्षों का लक्ष्य लेकर निवेश किया जाए तो मुनाफे की उम्मीद बढ़ जाती है।'

म्युचुअल फंड निवेशकों को दीर्घ अवधि के अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) जारी रखना चाहिए। इसी तरह, अगर उनके पास अतिरिक्त रकम है तो उन्हें अपना मौजूद परिसंपत्ति आवंटन टटोलना चाहिए, क्योंकि बाजार में भूचाल से उनके निवेश का ताना-बना बिगड़ गया होगा। मिड- एवं स्मॉल-कैप फंड में हाल में आई तेजी मौजूदा गिरावट के कारण समाप्त हो गई होगी। कोरोनावायरस जैसे संक्रमण विविधता भरे पोर्टफोलियो का महत्त्व कम कर देते हैं। मौजूदा उथल-पुथल से सोना में लोगों ने जमकर निवेश किया है। अगर आपके पोर्टफोलियो में अब तक सोने में 10-15 प्रतिशत निवेश नहीं किया गया है तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों में निवेश कर सकते हैं। सोने में निवेश धीरे-धीरे बढ़ाना बेहतर रहेगा।

क्या बीमा कवर में शामिल है कोरोनावायरस ?

बिंदिशा सारंग

कोरोनावायरस फैलने के बाद हवाई यात्रा के किराये में कमी आई

दुनिया के कई देशों के कोरोनावायरस की चपेट में आने से आज कई लोगों में मन में यह दुविधा है कि विदेश यात्रा करें या नहीं? कई लोग महीनों पहले की विदेश जाने की योजना बना चुके थे और उनकी बुकिंग पहले ही हो चुकी है। अगर आप ऐसे लोगों में शामिल हैं तो कुछ चीजें आपको सही निर्णय लेने में मदद कर सकती हैं।

अगर नहीं जाना चाहते हैं

अगर आप अपनी यात्रा रद्द करते हैं तो आपके टिकट का क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने इसे कहां से खरीदा था। कुछ कंपनियां पूरा रिफंड दे रही हैं। इजीगो के सह-संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी आलोक बाजपेयी कहते हैं, 'हम कोई सवाल पूछे बिना कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित देशों के टिकट का पूरा रिफंड दे रहे हैं, चाहे इस बारे में विमानन कंपनी की जो भी नीति हो।'

लेकिन हर कंपनी की इस तरह की नीति नहीं है। इसलिए इस बारे में विमानन कंपनी की नीति की जांच करें। उदाहरण के लिए विस्तारा ने कहा है कि वह मार्च में 54 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर रही है और उपभोक्ता इन उड़ानों का पूरा रिफंड ले सकते हैं। स्पाइसजेट ने भी 28 मार्च तक नई दिल्ली और हॉन्ग कॉन्ग की उड़ानों को रद्द कर दिया है। कंपनी भी पूरा रिफंड या फीस में छूट दे रही है। लब्बोलुबाब यह है कि हवाई यात्री पूरा रिफंड ले सकते हैं या बुकिंग राशि का भविष्य में यात्रा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि विमानन कंपनियां रिफंड दे सकती हैं। साथ ही अगर वे अपनी उड़ानें रद्द कर रही हैं तो भविष्य में मुफ्त उड़ान की पेशकश कर सकती हैं। पर अगर आप अपनी यात्रा उड़ान रद्द करते हैं तो आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी।

अगर आप टिकट रद्द करते हैं तो क्या आपको रिफंड मिलेगा? यहां कुछ ऐसे सुझाव हैं, जो आपको सही फैसला लेने में मदद करेंगे

अगर जाना चाहते हैं

कोरोनावायरस फैलने के बाद कई अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर हवाई यात्रा के किराये में उल्लेखनीय कमी आई है। बाजपेयी ने कहा, 'कोरोनावायरस से सर्वाधिक प्रभावित देशों को जाने वाले यात्रियों की संख्या में कमी आई है लेकिन दूसरे देशों में अब भी मांग बरकरार है।' अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको कुछ एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। विदेश यात्रा के विशेषज्ञ मुंबई के मुकुल लालका ने कहा, कम से कम सामान के साथ यात्रा कीजिए। डिस्पोजेबल मास्क पहनें और अपने साथ ले जाएं। साथ ही उस तरह के प्लास्टिक के दस्ताने पहनें जैसे शेफ किचन में पहनते हैं। चेहरे पर क्रीम लगाएं, नियमित रूप से चेहरा साबुन से धोएं और बार-बार क्रीम लगाएं। जब भी हाथ दस्तानों से बाहर निकालें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के दस्तानों से आप वायरस से प्रभावित चीजों के संपर्क में आने से बच जाएंगे। अनजाने संपर्क से बचने के लिए जितना संभव हो, अपने हाथों को मोड़कर रखें।

जहां तक नई बुकिंग का संबंध है, तो कुछ कंपनियां यात्रियों के बीच जारी अनिश्चितता को देखते हुए विशेष योजनाएं ला रही हैं। एसओटीसी ने भी नए ग्राहकों के लिए 'अल्ट्रा फ्लेक्सी स्कीम' शुरू की है। एसओटीसी ट्रैवल के प्रेजिडेंट और कंट्री प्रमुख (लीजर) डेनियल डिसूजा ने कहा, 'इस योजना के तहत ग्राहकों यात्रा की तिथि में विकल्प दिया जाएगा और कोविड-19 के कारण टिकट रद्द होने की स्थिति में वास्तविक वीजा शुल्क ही वसूल किया जाएगा।' क्या बीमा आपको बचाएगा? अगर आपके पास स्वास्थ्य बीमा है तो देश में भीतर यात्रा करने पर ही आप इसके दायरे में आएंगे। एको जनरल इंश्योरेंस में उत्पाद विकास के प्रमुख और मुख्य जोखिम अधिकारी बीरेश गिरि ने कहा, 'इस तरह के संक्रमण हमारी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं के दायरे में हैं। कोरोनावायरस जैसी नई बीमारियां पहले से मौजूद बीमारी की श्रेणी में नहीं आती हैं, इसलिए उनके साथ कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं होगी।'

बीमारी से जुड़े विशेष बीमा कवर भी अब उपलब्ध हैं। आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर्स के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट प्रवीण सिन्हा ने कहा, 'डिजिट इंश्योरेंस ने एक नई नीति शुरू की है जो खासतौर पर कोरोनावायरस के इलाज से जुड़े खर्च को कवर करती है। लेकिन केवल भारत में ही इलाज इसके दायरे में आएगा।'

खास बीमारी से संबंधित कवर व्यापक स्वास्थ्य पॉलिसी से कम खर्चीला होता है और जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है, वे इसे खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप विदेश जा रहे हैं तो? सिन्हा ने कहा, 'यह बीमारी विदेश यात्रा बीमा पॉलिसी के तहत आएगी क्योंकि अब तक खासतौर पर कोविड-19 को बाहर रखने का कोई प्रावधान नहीं है।' हालांकि उन्होंने साथ ही सुझाव दिया कि अगर आप किसी ऐसे देश की यात्रा पर जा रहे हैं जहां की यात्रा से परहेज करने के लिए सरकार ने परामर्श जारी किया है, तो आपको इस बारे में बीमा कंपनी से पूछताछ करनी चाहिए।

मार्च महीना बीतने से पहले ये कदम उठाएं और अपना कर बचाएं

यदि आपके पोर्टफोलियो में कोई संपत्ति पिछड़ रही है तो घाटा उठाने और कर का बोझ कम करने का यही सही मौका है

सर्वजित के सेन

मार्च महीना गुजरने वाला है। ऐसे में वेतनभोगियों और कारोबारियों को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कर के मामले में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए उन्होंने सही जगह निवेश किया है, बीमा पॉलिसी खरीद ली है और दावे भी कर दिए हैं। इनमें से कुछ अहम कदम इस तरह हैं:

पूंजीगत लाभ की योजना

यदि आप शेयर बाजारों में रकम लगाते रहे हैं और आपको अपने निवेश पर अल्पावधि अथवा दीर्घावधि पूंजीगत लाभ या नुकसान हुआ है तो उनका जोड़घटाव करें और देखें कि आप पर कितना कर बनता है। यदि आप पूंजीगत लाभ के बदले अपना पूंजीगत नुकसान दिखा देते हैं तो आपका कर बोझ कम हो सकता है। यदि आपको पिछले वर्षों में पूंजीगत नुकसान हुआ है तो आप उसे भी पूंजीगत लाभ के बदले निपटा सकते हैं।

अगर आपके निवेश पोर्टफोलियो में कमी है तो घाटा दिखाने और कर का बोझ कम करने का यह एकदम माकूल वक्त है।

क्लियरटैक्स के मुख्य कार्य अधिकारी और संस्थापक अर्चित गुप्ता की सलाह है, 'इसे टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग कहते हैं। कई करदाता अपना कर का बोझ कम करने के लिए यह तरीका अपनाते हैं। शेयर कारोबार में 1 लाख रुपये से अधिक का पूंजीगत लाभ होने पर 10 फीसदी दीर्घावधि पूंजीगत लाभ कर लगने के कारण खास तौर पर ऐसा किया जाता है।

शेयर किसी वित्त वर्ष के अंत में बेचे जा सकते हैं और अगले वित्त वर्ष की शुरुआत होते ही उन्हें वापस खरीदा जा सकता है। इससे किसी एक वित्त वर्ष में कर की देनदारी कम करने में मदद मिलती है और निवेश की रणनीति में किसी तरह का बदलाव भी नहीं करना पड़ता है। पोर्टफोलियो में ऐसे शेयरों पर भी दोबारा नजर डालनी चाहिए, जो अच्छा लाभांश देते हैं क्योंकि निवेशक पर कर अगले साल से लागू होगा।'

जमा योजनाओं पर रिटर्न

आय	वार्षिक रिटर्न
वरिष्ठ नागरिक जमा योजना	8.6
सुकन्या समृद्धि खाता	8.4
पीपीएफ	7.9
एनएससी	7.9
बाजार संबद्ध	**5 वर्ष रिटर्न सीएजीआर**
एनपीएस- टियर 1- स्कीम ई	5.66-7.83
एनपीएस- टियर 1- स्कीम सी	8.53-9.10
एनपीएस- टियर 1- स्कीम जी	8.65-9.89
इक्विटी लिंक्ड जमा योजना	-0.64-11.17

स्रोत- इंडियापोस्ट, एनपीएस ट्रस्ट्स, म्युचुअलफंड इंडिया

अग्रिम कर चुकाएं

यदि आप उस श्रेणी में आते हैं, जिसे अग्रिम कर देना होता है तो अपनी देनदारी का हिसाब लगा लीजिए। अग्रिम कर की आखिरी किस्त 15 मार्च को जानी है। अग्रिम कर देर से चुकाने पर ब्याज वसूलने का प्रावधान है। गुप्ता बताते हैं, 'जिस करदाता की कुल कर देनदारी 10,000 रुपये से अधिक हो, उसे अग्रिम कर देना ही चाहिए।'

अनिवार्य निवेश

हो सकता है कि आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत निवेश की जरूरत आपके मौजूदा निवेश या आवास ऋण के भुगतान से पूरी हो गई होगी। लेकिन यदि आप अनिवार्य निवेश सीमा वाली कुछ खास योजनाओं में निवेश करना शुरू कर चुके हैं तो उन्हें पूरा कीजिए। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना में कम से कम 1,000 रुपये का निवेश

31 दिसंबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक आप 10,000 रुपये के विलंब शुल्क के साथ रिटर्न दाखिल कर सकते हैं

अनिवार्य है, सार्वजनिक भविष्य निधि में हर साल कम से कम 500 रुपये और सुकन्या समृद्धि योजना में कम से कम 250 रुपये का निवेश करना ही होता है। यह रकम 31 मार्च से पहले जमा करा दीजिए वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

ग्रो के मुख्य परिचालन अधिकारी और सह-संस्थापक हर्ष जैन समझाते हैं, 'सरकार इसके जरिये यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि जो लोग बचत के लिए इन योजनाओं का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कर बचाने का फायदा भी मिले। निष्क्रिय खाते धीरे-धीरे बंद कर दिए जाते हैं।'

रीइंबर्समेंट का दावा करें

यदि आप कर्मचारी हैं और आपने ऐसा कोई खर्च किया है, जो आपके दफ्तर से आपको वापस मिल सकता है यानी रीइंबर्स हो सकता है तो रीइंबर्समेंट के लिए फौरन दावा कर दें। जितनी जल्दी हो सकता है दावा कीजिए ताकि रीइंबर्समेंट के आवेदन में किसी तरह की गलती होने पर आपको उसे सुधारने का पर्याप्त समय मिल जाए। यात्रा अवकाश भत्ता (एलटीए) और दूसरे तरह के रीइंबर्समेंट के लिए अगर आप आवेदन नहीं करते हैं तो आपका दफ्तर तय आयकर काटने के बाद ही उनकी रकम आपके खाते में भेजेगा।

देर से रिटर्न

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए यानी आकलन वर्ष 2019-20 के लिए अगर आप रिटर्न दाखिल नहीं कर सके थे तो जुर्माने के बगैर उसे दाखिल करने का आपके पास यह आखिरी मौका है। पिछले वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न देर से दाखिल करना हो तो मार्च के अंत तक का समय होता है।

31 दिसंबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक आप 10,000 रुपये के विलंब शुल्क के साथ रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। लेकिन उसमें कई नियम-शर्तें शामिल हैं। इसलिए अगर आप वित्त वर्ष के आखिरी महीने का अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से फौरन बात करें।

क्रिप्टोकरेंसी के नियमन की जटिल गुत्थी

विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से बढ़ती इस तकनीक को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र तथा रिजर्व बैंक को नए नियम बनाने चाहिए

गीतिका श्रीवास्तव और सुदीप्त दे

देश में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग तथा नियमन को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय के बाद 'क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध तथा सरकारी डिजिटल करेंसी का नियमन विधेयक 2019' नामक मसौदा विधेयक पर बहस छिड़ गई है। मसौदा विधेयक में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को दंडनीय बनाया गया है जिसके लिए दस वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। फिलहाल सरकार तथा बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक, दोनों को नई तकनीक पर अपने विचारों में बदलाव लाने के लिए एक बार फिर गहन विचार विमर्श करना होगा।

सिरिल अमरचंद मंगलदास में पार्टनर अरुण प्रभु ने कहा, 'इस निर्णय के बाद इस क्षेत्र में नवोन्मेष बढ़ेगा और ब्लॉकचेन तथा डीएलटी तकनीक पर आधारित नई परियोजनाएं विकसित होंगी।' इसके चलते केंद्र सरकार तथा नियामकों के सामने अपने निर्णयों पर एक बार फिर विचार करने तथा क्रिप्टोकरेंसी के लिए नियमों को बनाकर इस परिवेश को तेजी से बढ़ने में मदद करने का अवसर मिलेगा।

एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तथा 'क्रिप्टोकरेंसीज इन इंडिया: नॉट इल्लीगल बट नॉट क्वाइट लीगल' पुस्तक के लेखक दिनकर कालरा कहते हैं, 'देश में आधारभूत संरचना तथा प्रतिभाएं शानदार आर्थिक अवसर प्रदान करती हैं।'

विशेषज्ञों का कहना है कि अब कई तरह के परिदृश्य देखे जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि क्रिप्टोकरेंसी आरबीआई के तहत आती हैं और इसके चलते केंद्रीय बैंक इस निर्णय पर पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है। अगर आरबीआई ऐसा करता है तो इससे एक बार फिर नियम कानून का रास्ता खुल सकता है। केंद्र सरकार के समर्थन के साथ आरबीआई संभावित धोखाधड़ी से ग्राहकों को बचाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है।

दूसरे परिदृश्य में हो सकता है कि नियामक एक बार फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दे, हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अब इसकी संभावनाएं काफी कम हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा कि आरबीआई के पास प्रतिबंध संबंधी निर्णय को लेकर जरूरी दस्तावेजों अथवा सबूतों का अभाव है। हालांकि अगर विधायिका इस संबंध में कानून बनाने जा रही थी और अगर इस कानून को न्यायालय में चुनौती दी जाती तो कानून को ठोस सबूतों के साथ अपने तर्कों का समर्थन करके इस परीक्षण को पास करना होता। इस मामले में क्रिप्टो एक्सचेंजों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील और इकीगई लॉ के संस्थापक अनिरुद्ध रस्तोगी कहते हैं, 'यह सरकार पर है कि वह जोखिम संबंधी उपायों पर काम करे।'

सरकार एक अन्य विकल्प के तौर पर हालिया निर्णय के आधार पर अपने रुख की समीक्षा कर सकती है। यह फरवरी 2015 में फाइनैंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा प्रकाशित 'क्रिप्टोकरेंसी के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण' जैसी विभिन्न रिपोर्ट की समीक्षा कर सकती है। इसमें अनुसंशा की गई कि क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध का प्रस्ताव करने वाले देशों को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या इस तरह के प्रतिबंध से उद्योग में छुपे तरीके से तो कारोबारी गतिविधि नहीं बढ़ रहीं।

सरकार वर्ष 2018 में अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट का मसौदा विधेयक 'क्रिप्टो टोकन तथा क्रिप्टो एसेट (प्रतिबंध, नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2018' के साथ भी जा सकती है। इस विधेयक के मसौदे में मान्यताप्राप्त तथा विनियमित एक्सचेंजों में क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री तथा खरीद की अनुमति देने के प्रावधान थे। समिति ने शुरू में कहा था कि प्रतिबंध को लागू करना मुश्किल होगा और इससे कई परिचालक अवैध गतिविधियां शुरू कर देंगे जिससे गैर कानूनी गतिविधियों के लिए इनके उपयोग का चलन बढ़ जाएगा।

अगर सरकार इस विधेयक पर वापिस जाती है तो यह उद्योग के लिए 'बैठो तथा देखो' वाली स्थिति होगा। खेतान ऐंड कंपनी में पार्टनर ,संजय खान नागरा कहते हैं, 'कानूनी जटिलताओं के बीच विभिन्न प्राधिकारियों (आरबीआई, सेबी, वित्त मंत्रालय आदि) को इस पर गहन विचार करना होगा।'

इस मामले में याचियों का पक्ष रखने वाले तथा निशित देसाई एसोसिएट्स में वकील जयदीप रेड्डी एवं वैभव पारिख सलाह देते हैं कि सरकार को क्रिप्टोकरेंसी मध्यस्थों के लिए एक नया लाइसेंस लेकर आना चाहिए जिस पर तकनीक, अर्थव्यवस्था तथा वित्त की समझ वाले विशेषज्ञ समूह की निगरानी हो।

विशेषज्ञ क्रिप्टोकरेंसी के लिए आवश्यक नियम बनाने पर जोर दे रहे हैं। इंडसलॉ में पार्टनर श्रीनिवास कट्टा कहते हैं, 'अगर नियामक मुद्रा तथा सिक्योरिटी की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो प्रतिबंध जैसे नियम आसानी से समाप्त किए जा सकते हैं।'

विशेषज्ञों का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी पर कर लगाने संबंधी प्रस्ताव भी नीति निर्माताओं के रुख को बदल सकते हैं। दिनकर कहते हैं, 'क्रिप्टोकरेंसी रहेंगी और जल्द ही विश्व का कानूनी ढांचा इसे स्वीकार कर लेगा।'

नियामकीय सैंडबॉक्स

अगस्त 2019 में आरबीआई नियामकीय सैंडबॉक्स के विचार को लेकर आया था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी तकनीक का उपयोग करने वाली फिनटेक कंपनियों के लिए भी एक नियामकीय सैंडबॉक्स लाया जा सकता है।

विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में सीनियर रेजिडेंट फैलो शहनाज अहमद का कहना है, 'क्रिप्टोकरेंसी संबंधित फिनटेक नवोन्मेष का परीक्षण करने के लिए फिनटेक कंपनियों को अनुमति देने से आरबीआई के समक्ष भारत में साक्ष्य आधारित नियामकीय प्रक्रिया विकसित होगी।'

नियामकीय सैंडबॉक्स नवोन्मेष कर रही कंपनियों तथा नियामकों को एक अलग माहौल उपलब्ध कराता है जिसमें नए प्रयोगों का परीक्षण किया जा सके। इससे सभी को संबंधित प्रयोग के लाभ तथा जोखिम के साक्ष्यों की गणना करने में मदद मिलेगी।

विधि सेंटर फॉर लीगल पालिसी ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट 'ब्लूप्रिंट ऑफ फिनटेक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स लॉ' में एक अलग कानून की सिफारिश की है जो एक समान फ्रेमवर्क के तहत फिनटेक नवोन्मेष के लिए सैंडबॉक्स परीक्षण का अनुमति दे। प्रस्तावित फ्रेमवर्क सैंडबॉक्स परीक्षण में भाग लेने के लिए सभी संबंधित वित्तीय क्षेत्र नियामकों, जैसे सेबी, आरबीआई आदि के लिए एक औपचारिक तंत्र प्रदान करेगा।

प्रस्तावित कानून के व्यापक संदर्भों को रेखांकित करते हुए रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को मिलाकर एक अंतर-नियामकीय समन्वय समिति बनाने का सुझाव दिया गया है। हालांकि प्रत्येक नियामक अपने स्वयं के सैंडबॉक्स का संचालन जारी रख सकता है लेकिन इसमें कहा गया है कि प्रस्तावित कानून को देश में फिनटेक सैंडबॉक्स परीक्षण के लिए न्यूनतम मानकों को पूरा करना चाहिए।

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों का बैंक खातों से कारोबार शुरू

राजेश भयानी

- **दक्षिण भारत के एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज उनोक्वाइन ने बैंक खाता खुलने के साथ ही सेवाएं देना शुरू किया**
- **एक अन्य बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वजीरएक्स जल्द ही बैंकिंग प्रस्ताव की प्रक्रिया को पूरा कर लेगा और बैंकों ने एक्सचेंज के खाते खोलने में रुचि जाहिर की**
- **विशेषज्ञ क्रिप्टोकरेंसी खरीदने में जल्दबाजी नहीं करने और सरकार द्वारा इस पर निर्णय लेने तक प्रतीक्षा करने की सलाह दे रहे हैं**

उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिए जाने के बाद कई एक्सचेंजों ने बैंक खाते खोलना शुरू कर दिया है और अप्रैल 2018 से पहले की तरह उपलब्ध कराई जा रही बैंकिंग सुविधाओं को एक बार फिर प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं। हालांकि निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार के रुख को भी देखने की सलाह दी जा रही है।

इस समय बैंकिंग भुगतान के साथ क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन शुरू कर चुके एक एक्सचेंज के ऐप पर बिटकॉइन, पहली और सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी अपने मूल्य से 1.5-2 प्रतिशत प्रीमियम पर कारोबार कर रही है। हालांकि नए निवेशकों के पंजीकरण के बाद भी एक्सचेंज पर खरीद-बिक्री ऑर्डर के बीच का अंतर काफी अधिक बना हुआ है।

दक्षिण भारत के एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज उनोक्वाइन ने बैंक खाता खुलने के साथ ही सेवाएं देना शुरू कर दिया। एक्सचेंज के मुख्य कार्याधिकारी सात्विक विश्वनाथ ने कहा, 'हमने रुपये के जमा तथा निकासी संबंधी कई सौ आवेदनों का प्रसंस्करण कर लिया है और अब बहुत से ग्राहक पंजीकरण के लिए आ रहे हैं।'

वर्ष 2018 तक देश में क्रिप्टोकरेंसी कारोबार के लिए लोकप्रिय एक एक्सचेंज ने अभी तक भारत में दोबारा सेवाएं देना शुरू नहीं किया है। एक अन्य बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वजीरएक्स जल्द ही बैंकिंग प्रस्ताव की प्रक्रिया को पूरा कर लेगा और बैंकों ने एक्सचेंज के खाते खोलने में रुचि जाहिर की है। इस एक्सचेंज का हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बायनेंस ने अधिग्रहण किया था।

हालांकि विशेषज्ञ क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से पहले केंद्र सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा करने की सलाह दे रहे हैं

वजीरएक्स के मुख्य कार्याधिकारी निश्चल शेट्टी कहते हैं, 'भारत में सबसे अधिक रेटिंग के साथ हमारा ऐप सबसे बेहतर है। हम भारतीय ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर लाते रहेंगे जिससे वे बिटकॉइन तथा दूसरी क्रिप्टोकरेंसी में आसानी से कारोबार कर सकें। फिलहाल हम इनका परीक्षण कर रहे हैं।'

निश्चल उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लेकर काफी आशावादी हैं। वह कहते हैं, 'अब भारत में बड़े स्तर पर क्रिप्टोकरेंसी अपनाने का चलन बढ़ेगा। इसके बाद अब हम संबंधित क्षेत्र में नवोन्मेष कर सकते हैं और पूरा देश ब्लॉकचेन क्रांति में हिस्सा ले सकता है। एक अरब से अधिक की आबादी के साथ भारतीय बाजार इस क्षेत्र में एक छुपी प्रतिभा है।'

इनका मानना है कि अब भारत में कई सौ नए क्रिप्टो स्टार्टअप शुरू होंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट निवेशकों द्वारा लाखों डॉलर का निवेश किया जाएगा और नई नौकरियों का सृजन होगा।

हालांकि विशेषज्ञ क्रिप्टोकरेंसी खरीदने में जल्दबाजी नहीं करने और सरकार द्वारा इस पर निर्णय लेने तक प्रतीक्षा करने की सलाह दे रहे हैं। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के मानद चेयरमैन और इंटरनेट ऐंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल के चेयरमैन नवीन सूर्या कहते हैं, 'क्रिप्टोकरेंसी संबंधी लेनदेन पर निवेशकों को सावधानी बरतनी होगी, जब तक कि केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर अपनी एक राय जाहिर नहीं करती।' अभी तक सरकार का नजरिया देश में क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का रहा है। क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध का प्रस्ताव करने वाला विधेयक फरवरी 2019 में संसद में पेश किया गया था। हालांकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

स्व-वित्तपोषित संस्थानों के लिए अलग बिजली दरें सही

चेक बाउंस मामलों के तेजी से निपटान की व्यवस्था बनाएगा उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने जिला अदालतों में चेक बाउंस के लंबित पड़े 35 लाख से अधिक मुकदमों के तेजी से निपटान के लिए एक ठोस और समन्वित प्रणाली विकसित करने का निर्णय किया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए एक मुकदमा दर्ज किया है और रिजर्व बैंक समेत केंद्र सरकार एवं अन्य हितधारकों से जवाब दाखिल करने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबड़े और न्यायमूर्ति एल. एन. राव के पीठ ने जनवरी 2005 में बाउंस हुए दो चेक से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि इस तरह के मामले विभिन्न अदालतों में 15-15 साल तक लंबित रहते हैं और अदालतों का समय ज़ाया करते हैं। इस याचिका पर पांच मार्च को दिए एक आदेश में पीठ ने कहा, 'इस तरह के मामलों में तेजी लाने के लिए न्यायालय के विभिन्न आदेशों और विधायी संशोधनों के बाद कई बदलाव लाने के बावजूद बड़ी संख्या में सुनवाई अदालतों में ऐसे मामले लंबित पड़े हैं।' एक हालिया अध्ययन के मुताबिक ऐसे 35 लाख से अधिक मामले लंबित पड़े हैं जो जिला अदालतों में लंबित कुल आपराधिक मामलों के 15 प्रतिशत से अधिक हैं। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार महानिदेशकों, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिवों, रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ समेत केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मामले में उनकी प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया है। *भाषा*

अदालत से

एम जे एंटनी

केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग को यह अधिकार है कि वह स्व-वित्तपोषित शिक्षण संस्थानों के लिए सामान्य से ऊंची बिजली दरें तय कर सके। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि सरकारी एवं सरकार-समर्थित निजी संस्थानों की तुलना में स्व-वित्तपोषित संस्थानों के लिए अलग दर तय करना राज्य विद्युत नियामक आयोग के अधिकार में आता है। न्यायालय ने केरल राज्य बिजली बोर्ड बनाम प्रिंसिपल सर सैयद इंस्टीट्यूट मामले का निपटारा करते हुए आयोग की शुल्क अधिसूचना को भी सही ठहराया है। केरल उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने शिक्षण संस्थानों के लिए अलग-अलग दरें रखे जाने को सही ठहराया था लेकिन खंडपीठ ने इसे गलत बताया था। इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की गई तो एकल पीठ के फैसले को सही बताते हुए कहा कि स्व-वित्तपोषित संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के प्रोफाइल सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों से अलग होते हैं। सरकारी संस्थानों या सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र तुलनात्मक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के होते हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों का रखरखाव करदाताओं के पैसे से होता है।

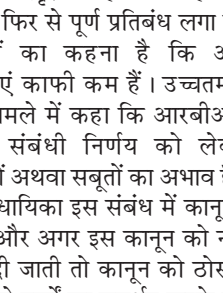

महाराष्ट्र एप्टेल का निरस्तीकरण आदेश खारिज

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग और विद्युत अपीलीय पंचाट (एप्टेल) के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें आयोग के गठन से पहले जारी पांच परिपत्र खारिज कर दिए गए थे। इन परिपत्रों का ताल्लुक राज्य सरकार की कैप्टिव पावर प्लांट नीति से था। महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी बनाम भारत संघ वाद में दायर अपील का मुख्य मुद्दा यह था कि क्या आयोग अपने गठन के पहले वितरण कंपनी द्वारा जारी किए गए परिपत्र निरस्त कर सकता है? आयोग का गठन बिजली नियामक अधिनियम 1998 के तहत किया गया था और इन परिपत्रों को उसके पहले ही बिजली बोर्ड ने जारी किया था। उच्चतम न्यायालय ने इस अपील को स्वीकार करते हुए कहा है कि आयोग के गठन के पहले जारी परिपत्रों एवं नीतिगत निर्णयों को निरस्त करना गैरकानूनी था। इसके साथ ही न्यायालय ने रिफंड से संबंधित आदेश भी खारिज कर दिया जिसमें बिजली वितरण कंपनी पर भारी बोझ डाला गया था।

मध्यस्थता दस्तावेज का पंजीकरण होना भी जरूरी

अगर मध्यस्थता प्रावधान ऐसे पट्टा अभिलेख में दर्ज है जिसका पंजीकरण नहीं हुआ है और न ही उस पर जरूरी स्टांप लगा है तो फिर उस प्रावधान को लागू नहीं कराया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने धर्मरत्नाकर चैरिटी बनाम मैसर्स भास्कर राजू वाद में यह फैसला सुनाया है। चैरिटी ट्रस्ट ने अपने संस्थापक की समाधि के पुनरुद्धार के लिए 1996 में कारोबारी प्रतिष्ठान को 38 साल के पट्टे पर अपनी परिसंपत्ति दी थी। लेकिन उसके बाद के वर्षों में समाधि पुनरुद्धार की दिशा में खास प्रगति नहीं होने पर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर दोषारोपण किए। मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय के पास गया जिसमें विवाद के निपटारे के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने की मांग की गई। इस पर उच्च न्यायालय ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को मध्यस्थ नियुक्त कर दिया। इससे नाखुश चैरिटी ट्रस्ट ने उच्चतम न्यायालय में अपील करते हुए कहा कि पट्टा देने वाले दस्तावेज पर ठीक से स्टांप नहीं लगे होने से उसे वैध नहीं माना जा सकता है। इस में उच्च न्यायालय के फैसले को दोषपूर्ण बताते हुए शीर्ष अदालत ने मध्यस्थता को खारिज कर दिया।

कर्ज वसूली अपील के लिए पूर्व-जमा अनिवार्य

उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर कहा है कि कर्ज वसूली अधिकरण (डीआरटी) में अपील करने वाले कर्जदार को सुरक्षित कर्जदाताओं द्वारा मांगी गई या अधिकरण द्वारा तय की गई राशि अनिवार्य तौर पर पहले जमा करानी होगी। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस कानूनी बाध्यता के दायरे में केवल कर्जदार ही नहीं बल्कि गारंटीदाता और गिरवी रखने वाले भी आते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम रजत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मामले में दायर अपील का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक, सरफाएसी अधिनियम की धारा 18 अपील पर सुनवाई के पहले विवादित राशि का 50 फीसदी हिस्सा जमा करना जरूरी बनाती है। डीआरटी चाहे तो वाजिब कारण दर्ज कराते हुए इस राशि को 25 फीसदी कर सकती है। किसी भी हाल में पूर्व-जमा की शर्त को पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता है। इसके पहले बंबई उच्च न्यायालय ने विपरीत रुख अपनाते हुए पूर्व-जमा के बगैर ही केस सुनने की मंजूरी पंचाट को दे दी थी। इसने दावा किया कि उसके पास ऐसा करने की विवेकाधीन शक्ति थी। लेकिन शीर्ष अदालत ने इस दावे को नकारते हुए कहा कि विवेकाधीन शक्तियों का हवाला देते हुए वैधानिक प्रावधानों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। वैसे उच्चतम न्यायालय ने इस आरोप पर कुछ नहीं कहा है कि बैंक कर्मचारियों की मौन सहमति से 160 तकोड़ रुपये की संपत्ति महज 65 करोड़ रुपये में बेच दी गई।

एमएमटीसी के खिलाफ मध्यस्थता निर्णय खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमएमटीसी और ऐंग्लो अमेरिकन मैटलर्जिकल कोल लिमिटेड के बीच के विवाद में आए मध्यस्थता निर्णय को निरस्त कर दिया है जिससे सार्वजनिक उपक्रम करीब 748 करोड़ रुपये की देनदारी से बच गया है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है, 'हमारी नजर में इस तरह का मध्यस्थता निर्णय अधिक सटीक तथ्यों और कानूनी बुनियाद पर आधारित होना चाहिए, न कि किसी मध्यस्थता पंचाट का निर्णय होने के नाते उसे अलंघनीय बताया जाए। क्षति, ब्याज एवं लागत से संबंधित निर्णय न्याय का प्रहसन है और यह विकृतियों से भरपूर है।' मध्यस्थता पंचाट ने बहुमत से सुनाए गए निर्णय में ऐंग्लो-अमेरिकन कंपनी के क्षतिपूर्ति दावे को स्वीकार कर लिया था हालांकि तीसरे मध्यस्थ ने इसे नकार दिया था। कंपनी ने अपने दावे में कहा था कि एमएमटीसी ने ऑस्ट्रेलिया से मंगाए गए 4.53 लाख टन कोकिंग कोल का उठाव नहीं किया जिससे उसे काफी नुकसान हुआ। निजी फर्म के मुताबिक एमएमटीसी लगातार कोयले के भाव में कटौती की मांग करती रही और फिर अनुबंध में सहमति जताए गए भाव पर कोयला उठाने से मना कर दिया। इसके जवाब में एमएमटीसी का कहना था कि 2008 में विश्वव्यापी वित्तीय संकट होने से पिग आयरन जैसे उसके उत्पादों की कीमतें धराशायी हो गई थीं और वह कोयले के भाव में समायोजन की मांग कर रही थी। न्यायालय ने मध्यस्थता निर्णय से संबंधित तथ्यों के बारे में अपना न्याय-क्षेत्र सीमित होने की बात स्वीकार करने के साथ ही कहा कि दोनों पक्षों के बीच हुए संवाद के विश्लेषण से यही लगता है कि पंचाट ने अलिखित शब्दों के भी मतलब निकालने की कोशिश की।

एमएसएमई अधिनियम की प्रक्रिया का पालन हो

शिकायत करने वाली फर्म के पास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (एमएसएमई) विकास अधिनियम के तहत विधिक समाधान का विकल्प होने पर उसे सीधे उच्च न्यायालय का रुख नहीं कर लेना चाहिए। फाइव्ज स्टेन इंडिया प्रोजेक्ट बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में एमएसएमई सुविधा परिषद ने नाभिकीय एवं बिजली उपकरण बनाने वाली कंपनी के खिलाफ आदेश पारित किया था। उसने महाकौशल रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड से कुछ सामान खरीदा था जो दोयम दर्जे का निकला। विवाद होने पर मामला सुविधा परिषद में ले जाया गया जिसने फाइव्ज स्टेन के खिलाफ आदेश दिया। उसने फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जिसने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एमएसएमई में अपील की प्रक्रिया का प्रावधान है और उसका पालन किया जाना चाहिए।

मोदी के ट्विटर पर 'नारी शक्ति'

ट्विटर पर छाई रहने वाली सात महिलाओं में से तीन को राष्ट्रपति ने दिया 'नारी शक्ति' पुरस्कार

अर्चिस मोहन

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपना सोशल मीडिया अकाउंट, जिंदगी में खास मुकाम हासिल करने वाली सात महिलाओं को सौंप दिया जिन्होंने अपने जीवन के सफर को साझा किया। इन सात में से तीन महिलाओं को रविवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था कि वह अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जिंदगी में एक मुकाम हासिल करने वाली महिलाओं के लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक का अकाउंट छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। इन सात महिलाओं को देश के अलग-अलग क्षेत्रों और आर्थिक-सामाजिक पृष्ठभूमि से चुना गया। इन महिलाओं के काम से मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में भी जागरुकता बढ़ाने में मदद मिली

कश्मीर की परंपरागत हस्तकला के संरक्षण के लिए आरिफा जान को मिला नारी शक्ति पुरस्कार

खासतौर पर स्वच्छ भारत अभियान और जल संरक्षण के लिए 'जल जीवन मिशन'। इन महिलाओं ने जो वीडियो साझा किए उसे सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में लोगों ने देखा। मोदी ने अपने निजी ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। हम अपनी नारी शक्ति के साहस और उपलब्धियों को सलाम करते हैं। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले कहा था, मैं अब विदा ले रहा हूं। खास मुकाम हासिल करने वाली सात महिलाएं अपनी जीवन यात्रा को मेरे सोशल मीडिया अकांउट्स के जरिये साझा करेंगीं।'

उन्होंने कहा, 'देश के सभी हिस्से में अप्रतिम उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाएं हैं। इन महिलाओं ने अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है। उनका संघर्ष और आकांक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। आइए, ऐसी महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाएं और उनसे सीखें।' जिन सात महिलाओं ने अपनी जिंदगी के सफर को ट्विटर के जरिये साझा किया उनमें उत्तर प्रदेश के कानपुर की एक राजमिस्त्री के काम से जुड़ी कलावती देवी शामिल हैं जिन्होंने 4,000 शौचालयों के निर्माण में मदद की। इसके अलावा बिहार के मुंगेर जिले की मशरूम किसान वीना देवी, कश्मीरी की पारंपरिक हस्तकला को लोकप्रिय बनाने और उसे संरक्षित करने के काम में जुड़ीं आरिफा जान शामिल हैं। कलावती, वीना और आरिफा जान को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया।

इनके अलावा मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट पर ग्रामीण महाराष्ट्र के बंजारा समुदाय की हस्तकला को बढ़ावा देने वाली विजया पवार, परोपकारिता के काम और फूड बैंक ऑफ इंडिया की संस्थापक स्नेहा मोहनदास, बम धमाके का शिकार बनी मालविका अय्यर और हैदराबाद की जल संरक्षक कल्पना रमेश शामिल हैं। महिलाओं को ट्विटर अकाउंट सौंपने से पहले मोदी ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं।

स्त्री-पुरुष विविधता पर उद्योग जगत का जोर

बीएस संवाददाता

हाल के वर्षों में औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार में कमी आई है लेकिन देश की शीर्ष कंपनियां महिलाओं के लिए विशेष पेशकश और कार्यक्रम आयोजित करते हुए 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' मना रही हैं। कई स्थापित कंपनियों ने अधिक महिलाओं को नियुक्त करने और उन्हें सशक्त करने की दीर्घावधि योजना बनाई है।

वित्तीय सेवा से लेकर विनिर्माण कंपनियां और कॉरपोरेट लेनदार तमाम कदम उठा रहे हैं ताकि कंपनी में विविधता बनाने के साथ-साथ महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इंडियन होटल्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी पुनीत चटवाल ने कहा, 'टाटा के मूल्यों के अनुरूप इंडियन होटल्स कंपनी ने एक ऐसी संस्कृति बनाई है जो विविधता और समावेशन को बढ़ावा देती है। हम महिलाओं के लिए समान अवसर सृजित करने और उन्हें कंपनी में विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

तंबाकू से लेकर होटल तक कारोबार करने वाली दिग्गज कंपनी आईटीसी भी विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के लिए, आईटीसी की कुछ अत्याधुनिक खाद्य विनिर्माण इकाइयों में महिलाकर्मियों की संख्या में लगातर वृद्धि दर्ज की गई है। तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई (त्रिची) में आईटीसी की इकाई देश की सबसे बड़ी फैक्टरियों में शामिल है और वहां तैनात करीब 85 फीसदी कर्मचारी महिलाएं हैं।

इसी प्रकार, कर्नाटक के मैसूरु में आईटीसी की फूड इकाई उस क्षेत्र की ऐसी पहली एफएमसीजी फैक्टरी है जहां सभी पाली में महिला कर्मियों की तैनाती की गई है। इस इकाई में महिला कर्मियों का अनुपात करीब 60 फीसदी है।

अपने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आईटीसी का फूड कारोबार फैक्टरियों में कई अन्य पहल भी कर रहा है और इसके तहत महिला कर्मियों के लिए भोजन एवं क्रेच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आईटीसी के एक अधिकारी ने कहा, 'विश्वास बहाली के उपाय के तौर पर महिला कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को फैक्टरी में आमंत्रित कर वहां के माहौल और संस्कृति से अवगत कराया जाता है। साथ ही, फैक्टरी की नेतृत्व टीम उनकी सुरक्षा, भोजन, परिवहन आदि संबंधी चिंताओं का ध्यान रखती है।'

अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाले वेदांत समूह ने न केवल विविधता संबंधी अपने लक्ष्यों को पूरा करने का निर्णय लिया है बल्कि वह लोगों की मानसिकता में भी बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। वेदांत के एल्युमीनियम ऐंड पावर बिजनेस के सीएचआरओ दिलीप रंजन साहू ने कहा, 'वेदांत एल्युमीनियम ऐंड पावर बिजनेस में हम शॉप फ्लोर के साथ-साथ रणनीतिक निर्णय लेने संबंधी महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी वाली भूमिकाओं में भी महिला पेशेवरों को नियुक्त करने में यकीन करते हैं। वर्तमान में हमारी

एशिया क्षेत्र की जिन कंपनियों के निदेशक मंडल में दो महिलाएं थीं उनमें शुद्ध मुनाफा मार्जिन अधिक रहा

लैंगिक विविधता 12 फीसदी है जबकि हमारा लक्ष्य इसे 30 फीसदी करने का है। इसके अलावा परिचालन एवं रखरखाव में इसे 20 फीसदी रखने की योजना है।'

समूह महिलाओं को सभी भूमिका में देखना चाहता है चाहे वह कोई गैर-परंपरागत भूमिका ही क्यों न हो। उन्होंने कहा, 'महिलाएं सबकुछ कर सकती हैं और उन्हें करना चाहिए, इस मकसद से उन्हें सभी भूमिकाओं के लिए काम पर रखा जा सकता है जिनमें संयंत्र संचालन से लेकर सुरक्षा, शोध एवं विकास, मार्केटिंग, रख-रखाव, अग्निशमन जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं।'

तकनीकी क्षेत्र ने महिला दिवस को सफलता की दास्तां में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गूगल ने देशभर में 2 से 13 मार्च तक संवाद सत्र की एक सीरीज की मेजबानी की। विमान क्षेत्र में एमिरेट्स विमानन कंपनी ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी कुल कार्यबल के 40 फीसदी से अधिक है जिनमें से ज्यादातर केबिन क्रू के तौर पर काम करती हैं। महिला दिवस के मौके पर एमिरेट्स ने विमान में महिला निर्देशकों की सराही गई फिल्में भी दिखाईं। दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं की दखल बढ़ाने के लिए ही उन्हें नौकरियों में नहीं रखा जाता बल्कि उनकी वजह से मुनाफा बढ़ाने में भी मदद मिलती है।

बीओएफए ग्लोबल रिसर्च की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की जिन कंपनियों के निदेशक मंडल में कम से कम दो महिलाएं थीं उनके शेयरों में कीमत के मुकाबले बेहतर कमाई और ज्यादा शुद्ध मुनाफा मार्जिन का रुझान रहा। बीओएफए के डेटाबेस से यह अंदाजा मिलता है कि 66 फीसदी एशियाई कंपनियों के निदेशक मंडल में दो से कम महिलाएं शामिल हैं। इन्फोटेक, उद्योग जगत, ग्राहकों से जुड़े क्षेत्र में स्त्री-पुरुष विविधता का भारी अभाव है। श्रम बल भागीदारी और आर्थिक भागीदारी में स्त्री-पुरुष असमानता स्थिर हो चुकी है या फिर इसमें बढ़ोतरी के ही संकेत हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि राह अभी काफी लंबी है।

पुरुषों के साथ कार साझा करने में नहीं है परेशानी

ज्योति मुकुल

देश के 10 शहरों में गाड़ी की सवारी साझा (कार पूल) करने वाली 5,465 महिलाओं के एक सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है कि सवारी करने वाली 60 फीसदी महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन के साधनों के मुकाबले कार पूल का विकल्प विकल्प अपेक्षाकृत ज्यादा सुरक्षित लगता है हालांकि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उनके सहयात्री कौन हैं।

दिसंबर 2012 में 23 साल की निर्भया का सामूहिक बलात्कार दिल्ली की एक बस में हुआ था जिस बस का इस्तेमाल निजी तौर पर स्कूल भी किया करते थे। इससे न केवल देश में यौन शोषण कानून पर सवाल खड़े हो रहे हैं बल्कि देश के परिवारों में इस बात को लेकर भी चिंता बढ़ी है कि महिलाएं यातायात के किन साधनों का इस्तेमाल करती हैं खासतौर पर अगर वह किसी अलग शहर में हैं।

इन आठ सालों में अब भी किसी महिला या लड़की के परिवार वालों के दिमाग में इस बात को लेकर चिंता बनी रहती है कि आखिर वह कहीं आने-जाने के किन साधनों का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि कामकाजी महिलाओं ने अपनी यात्रा के तरीके में बदलाव किया है। महिलाओं ने प्राइवेट कार, टैक्सी और बसों के लिए पूलिंग सेवाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं अपनी कार भी न केवल दूसरी महिलाओं बल्कि पुरुषों के साथ भी साझा करने लगी हैं। तकनीक के इस्तेमाल की वजह से सुरक्षा की धारणा में बदलाव आया है। खासतौर पर ऐप आधारित सेवाओं की वजह से सहयात्रियों का ब्योरा भी मिल जाता है जिससे उनकी पुष्टि होती है और ऐसे में भरोसा बढ़ने के साथ-साथ नेटवर्किंग भी हो जाती है।

करीब 84 फीसदी महिलाओं को लगता है कि कार पूल करने से कहीं आना-जाना आसान हो जाता है और इससे सार्वजनिक परिवहन पर निर्भरता भी कम होती है। कार पूल करने की वजह से यह आजादी जरूर मिलती है कि सार्वजनिक परिवहन की दिक्कतों को झेले बगैर वे कहीं भी आसानी से काम करने चली जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं।

एसराइड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और सह संस्थापक लक्षणा चड्ढा झा कहती हैं, 'यह सर्वेक्षण पुणे के एक स्टार्टअप एसराइड ने कराया जो कार पूल की सेवाएं देता है। एसराइड के 20 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में से करीब 60 फीसदी महिलाएं हैं लेकिन केवल 15 फीसदी महिलाओं के नाम ही पंजीकृत कार है यानी कार के मालिकाना हक के मामले में महिलाओं की तादाद कम है।'

सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि महिलाओं के बीच कहीं आने-जाने की 'आजादी' एक मुख्य मुद्दा रहा। बस एग्रीगेटर सेवा शटल के सीईओ और सह संस्थापक अमित सिंह कहते हैं, 'महिलाओं के लिए कहीं आने-जाने की आजादी अहम है ताकि उन्हें आर्थिक मौके को गंवाना न पड़े। कभी-कभी कहीं आने-जाने के अपर्याप्त साधनों की वजह से उन्हें कम मौके वाली जगहों का विकल्प चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है जिससे उन्हें अपने करियर में तरक्की नहीं मिल पाती।'

शटल की महिला उपयोगकर्ताओं की तादाद दो सालों में तीन गुना से ज्यादा बढ़ी है और यह 2019 में 27,750 हो गई। उनके कुल ग्राहकों में महिलाओं की तादाद 2017 के 37 फीसदी से बढ़कर 41 फीसदी हो गई। झा का कहना है कि एसराइड मंच के जरिये होने वाली 70 फीसदी सवारी दोबारा भी कार पूल का विकल्प ही चुनती हैं। उनका कहना है, 'महिलाएं अपने उद्योग के लोगों के साथ ज्यादा सहज होती हैं।' सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाली करीब 44 फीसदी महिलाएं एक महीने में 10 दफा से भी कम प्री पेड कैब का इस्तेमाल करती हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि लोग किफायती और आरामदायक साधनों को ज्यादा तरजीह देते हैं।

सवारी करने वाली कुछ महिलाओं के लिए यह भी जरूरी है कि वे रास्ते में बोर न हों और उनका सहयात्री अच्छी बातचीत करता हो, हालांकि ज्यादातर महिलाओं के लिए ये बातें अहम नहीं है। सर्वेक्षण में कहा गया है, 'मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में जो लोग अक्सर कैब सेवाओं (महीने में 10 बार से अधिक) का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए कार पूल के दौरान लोगों के साथ संवाद एक अहम मुद्दा बन जाता है और इस सेगमेंट के 60 फीसदी से अधिक सवारियों के लिए यह अहम है। बातचीत की गुणवत्ता अहम है क्योंकि लोग सफर में बोरियत कम करना चाहते हैं।'

दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरु, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में यह सर्वेक्षण कराया गया। सभी शहरों के सर्वेक्षण में ज्यादातर रुझान समान ही रहा जिसमें कार पूल में बातचीत और स्त्री-पुरुष समानता अहम रहा। करीब 75 फीसदी सवारियों को महसूस होता है कि कार पूल के दौरान अक्सर नेटवर्किंग या काम से जुड़ी बातचीत अक्सर हो जाती है। सफर के दौरान समसामयिक विषयों पर चर्चा का स्थान दूसरा है और 58 फीसदी सवारी इसे बातचीत का अहम मुद्दा मानती है।

कार पूल: महिलाएं किस पर बात करना पसंद करती हैं

75 फीसदी : नेटवर्किंग और काम से संबंधित विषय पर

58 फीसदी: समसामयिक विषयों पर चर्चा

44 फीसदी: लोकप्रिय रुझान पर

कौन करता है मार्गदर्शन

65 फीसदी: मां

30 फीसदी: महिला प्रबंधक/बॉस

5 फीसदी: अन्य

कोरोना: इटली-ईरान में गंभीर होते हालात

इटली ने कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के अपने प्रयासों के तहत देश भर के सिनेमाघरों, थिएटरों और संग्रहालयों को बंद रखने का आदेश दिया है। चीन के बाहर कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित देशों में इटली का नाम सबसे ऊपर है जहां अब तक इस घातक बीमारी के चलते 230 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है।

हवाईअड्डों पर यात्रियों की हो रही है संक्रमण जांच

कोरोनावायरस से प्रभावित एक अमेरिकी क्रूज जहाज को शनिवार देर रात बंदरगाह पर आने की इजाजत दे दी गई और यह सोमवार को ऑकलैंड के बंदरगाह पर ठहरेगा। वहीं, देश में वायरस संक्रमण के 400 से ज्यादा मामलों की पुष्टि के बाद न्यूयॉर्क ने भी स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। तेजी से फैलते इस वायरस का प्रसार पहले ही अमेरिका के 30 राज्यों में हो चुका है और इससे कम से कम 19 लोगों की जान चली गई, जबकि अमेरिकी राजधानी में शनिवार को मौत का पहला मामला सामने आया।

ईरान में नए मामलों की पुष्टि के साथ ही देश में फरवरी मध्य के बाद से वायरस से मरने वालों की संख्या 194 पर पहुंच गई है। वायरस से सर्वाधिक प्रभावित चीन के बाहर सबसे ज्यादा मौतें इटली और ईरान में ही हुई हैं। यह वायरस ईरान के सभी 31 प्रांतों में फैल चुका है जहां 6,566 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है।

दक्षिण कोरिया में एक सप्ताह से अधिक समय में वायरस के न्यूनतम मामले सामने आए हैं। वहीं चीन में जनवरी के बाद से रविवार को वायरस के सबसे कम नए मामले सामने आए। दुनियाभर में कोरोनावायरस से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़कर शनिवार को एक लाख के पार हो गई।

केरल में कोरोनावायरस के पांच और मामले सामने आए हैं। इनमें से तीन लोग हाल ही में इटली की यात्रा करके लौटे हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश ने विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बसों, मेट्रो को नियमित आधार पर संक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया है। *एजेंसियां*

संक्रमण रोकने के लिए हवाईअड्डे मुस्तैद

बीएस संवाददाता

कोरोनावायरस के महामारी में तब्दील होने के बाद देश के विभिन्न हवाईअड्डों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। चेक-इन काउंटर (बोर्डिंग पास) पर कर्मचारियों को सर्दी-जुकाम आदि से पीड़ित यात्रियों पर पैनी नजर रखने के लिए कहा गया है। हवाईअड्डों पर अल्कोहल युक्त क्लीनिंग एजेंट (संक्रमण रोकने में काम आने वाले पदार्थ, द्रव) से रोजाना सफाई की जा रही है। इसके अलावा एहतिआत के तौर पर कई अन्य उपाय भी किए गए हैं।

गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाईअड्डों पर विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग (जांच) के आदेश जारी किया था। चीन से आने वाली यात्रियों की जांच 17 जनवरी से शुरू हो गई थी और इस फेहरिस्त में 17 अन्य देश भी शामिल किए गए हैं। देश में कोरोनावायरस के 31 मामले पाए जाने पर सरकार पूरी तरह चौकन्नी हो गई है और जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

गुरुवार को मुंबई और दिल्ली हवाईअड्डों पर उतरने वाले यात्रियों को आव्रजन पूर्व स्वास्थ्य जांच के लिए 40 मिनट तक कतारों में खड़ा रहना पड़ा। हालांकि अतिरिक्त डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के आने के बाद शुक्रवार तक कतार छोटी पड़ने लगी और ज्यादातर यात्रियों को 5-15 मिनट मिनट से अधिक कतारों में खड़ा रहना नहीं पड़ा। शुक्रवार को सरकार ने गंभीर रूप से कोरोनावायरस की चपेट में आए 12 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए सीमा शुल्क एवं आव्रजन जांच काउंटरों पर अलग से निकासी एवं बैगेज बेल्ट की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। हालांकि हवाईअड्डों पर फिलहाल ऐसी व्यवस्था मुकम्मल नहीं हो पाई है। शुक्रवार को अमेरिका से मुंबई पहुंचने वाले सलील मोहिदेकर ने कहा, 'स्वास्थ्य जांच कराने में करीब 10-12 मिनट लगे। भीड़ भी अधिक नहीं थी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हवाईअड्डा अधिकारियों को अलग से काउंटरों की व्यवस्था करनी चाहिए।'

शुक्रवार को आए एक अमेरिकी नागरिक ने कहा कि विदेश से आने वाले लोगों के फिंगर प्रिंट लेने के बाद हवाईअड्डों को उनके लिए सैनिटाइजर और टिश्यू पेपर का भी प्रबंध करना चाहिए। मुंबई हवाईअड्डे के एक अधिकारी ने कहा, 'पहले हमारे पास 42 डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी थे, जो तीन सत्रों में काम किया करते थे और अब यह संख्या बढ़कर 136 हो गई है। रात्रि में अंतरराष्ट्रीय उड़ाने अधिक आती हैं, इसलिए अतिरिक्त डॉक्टरों की सेवाएं ली जा रही हैं। हमारे पास 25 इन्फ्रारेड थर्मोमीटर हैं, जो पर्याप्त हैं।'

दिल्ली हवाईअड्डे पर दो थर्मल स्कैनर और 3 तापमान मापक यंत्र इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। बेंगलूरु हवाईअड्डे पर मेडिकल कॉलेज के छात्रों की भी सेवाएं ली जा रही हैं। एएएससीबी इंटरनैशनल एयरपोर्ट, कोलकाता के निदेशक कौशिक भट्टाचार्य ने कहा,'मौजूदा जरूरत के हिसाब से स्वास्थ्य कर्मी पर्याप्त संख्या में हैं, लेकिन हमने एहतियात के तौर पर राज्य सरकार से अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मी मुहैया कराने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। हमें राज्य सरकार से हरेक तरह की मदद मिल रही है।' भट्टाचार्य ने कहा कि विदेश से आने वाले यात्रियों की संख्या प्रति दिन 5,000 से कम होकर अब करीब 3,800 रह गई है।

मॉल-मल्टीप्लेक्स में कम ग्राहक

विवेट सुजन पिंटो और सोहिनी दास

मुंबई, ठाणे, आगरा, नोएडा और दिल्ली जैसे शहरों में कोविड-19 के मामले सामने आने के बाद होली से ऐन पहले खुदरा विक्रेता, मल्टीप्लेक्स परिचालक, मॉल डेवलपर और ढाबा मालिक कोरोनावायरस के कहर से हलाकान हो रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने कहा, 'कारोबार पर असर स्पष्ट नजर आ रहा है। लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने और शहरों में एक जगह पर जमा होने से बच रहे हैं। लिहाजा शनिवार से शुरू हुई होली के त्योहारी सीजन की छुट्टी में परंपरागत और आधुनिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम धंधों पर बुरा असर पड़ रहा है।'

देश भर में मंगलवार को होली मनाई जाएगी। चार दिनों की छुट्टियों का सिलसिला खुदरा कारोबारियों, मॉलों और मल्टीप्लेक्स परिचालकों के लिए वरदान साबित हो सकता था। मुंबई के अंधेरी और मलाड में संपत्तियों का परिचालन करने वाली इनफिनिटी मॉल के मुख्य कार्याधिकारी मुकेश कुमार ने कहा कि उन्हें इस सप्ताहांत में कारोबार में कोई तेजी नजर नहीं आई। उन्होंने कहा, 'अमूमन होली वाले सप्ताहांत में ग्राहकों की संख्या 20-25 फीसदी तक बढ़ी हुई नजर आती है। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हैं और उनकी मनोदशा उत्सवपूर्ण होती है। इस साल हमें उत्सव का भाव नजर नहीं आ रहा है।'

बाजार में दिखा संक्रमण का असर

फिल्म थिएटर उद्योग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में फिल्म देखने आने वाले लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई है लिहाजा पिछले हफ्ते रिलीज हुई शुभ मंगल ज्यादा सावधान और थप्पड़ जैसी फिल्मों के कलेक्शन को जोरदार चपत लगी है। शुक्रवार को टाइगर श्रॉफ की मुख्य किरदार वाली बागी 3 रिलीज हुई जिसने पहले दिन ही 17.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस बारे में कारोबारी विश्लेषकों का कहना है कि फिल्म की पहले दिन की कमाई उम्मीद से कम है।